ISSN-0971-8397

योजना

अक्तूबर 2007 विकास को समर्पित मासिक मूल्य : 10 रुपये

मुद्रास्फीति बनाम विकास

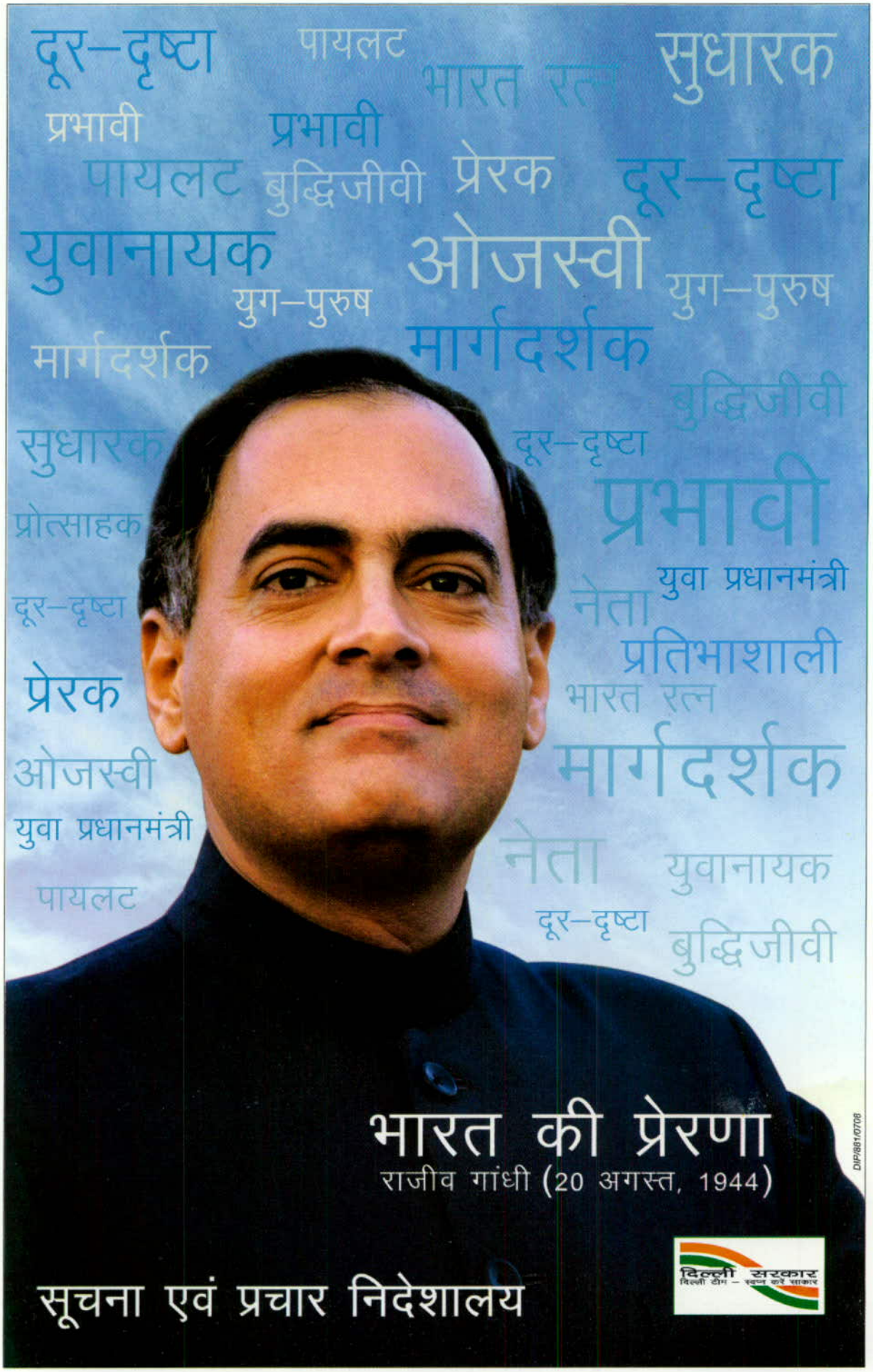
दूर–दृष्टा
पायलट
भारत रत्न
सुधारक
प्रभावी
प्रभावी
पायलट
बुद्धिजीवी
प्रेरक
दूर–दृष्टा
युवानायक
ओजस्वी
युग–पुरुष
युग–पुरुष
मार्गदर्शक
मार्गदर्शक
बुद्धिजीवी
सुधारक
दूर–दृष्टा
प्रभावी
प्रोत्साहक
युवा प्रधानमंत्री
दूर–दृष्टा
नेता
प्रतिभाशाली
प्रेरक
भारत रत्न
मार्गदर्शक
ओजस्वी
युवा प्रधानमंत्री
नेता
युवानायक
पायलट
दूर–दृष्टा
बुद्धिजीवी
भारत की प्रेरणा
राजीव गांधी (20 अगस्त, 1944)
DIP/681/0708
दिल्ली सरकार
सूचना एवं प्रचार निदेशालय

YH-10/07/5

योजना

वर्ष : 51 • अंक 7 अक्तूबर 2007 आश्विन-कार्तिक, शक संवत 1929 कुल पृष्ठ : 68

प्रधान संपादक

अनुराग मिश्रा

कार्यकारी संपादक

राकेशरेणु

सहायक संपादक

रेमी कुमारी

संपादकीय कार्यालय

कमरा नं. 538, योजना भवन, संसद मार्ग,

नयी दिल्ली-110 001

दूरभाष : 23096738, 23717910

23096666/2508, 2511

टेलीफैक्स : 23359578

ई-मेल : ce.yojana48@yahoo.co.in

www.publicationsdivision.nic.in

a) dpd@nic.in

b) dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)

एन.सी. मजूमदार

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)

जगदीश प्रसाद

दूरभाष : 26100207, 26105590

फैक्स : 26175516

आवरण : **मंजुला पटेल**

इस अंक में

संपादकीय	-	3
आर्थिक संकेतक	-	4
क्या है मुद्रास्फीति?	-	5
मुद्रास्फीति पर वित्तमंत्री का रुख कड़ा	-	7
पुनर्विचार मांगता संबंध : महंगाई और आर्थिक विकास	कमलनयन काबरा	8
भारत की प्राथमिक आवश्यकता है विकास	श्याम पोनप्पा टी. सी. ए. श्रीनिवास राघवन	11
मुद्रास्फीति, विकास और ग़रीबी	देवेन्द्र कुमार पंत	15
भारत में विकास और मुद्रास्फीति	पुलाप्रे बालकृष्णन	19
मुद्रा प्रसार : कारण और समाधान	सी.एम. चौधरी	23
सकल घरेलू उत्पाद क्या है?	-	26
हिंदी फिल्मों में 1857 का महाविद्रोह	जवरीमल्ल पारख	28
दस्तावेज : हिंसा से बुराई बढ़ती है	महात्मा गांधी	36
महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रवाद का निम्नवर्गीय प्रसंग	रश्मि चौधरी	37
झरोखा जम्मू-कश्मीर का	-	41
जहां चाह वहां राह : आत्मनिर्भरता के बीज	अनीता पैलूर	45
स्वातंत्र्य चेतना का संवाहक डाकघर	ऋषिकेश	48
ख़बरों में	-	53
मंथन : समय प्रबंधन	विजय प्रकाश श्रीवास्तव	57
स्वास्थ्य चर्चा : शिशु के लिये अनुपम आहार है मां का दूध	अनिल कुमार	61
नये प्रकाशन : 1857 - प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में दिल्ली	देवेंद्र उपाध्याय	64

योजना हिन्दी के अतिरिक्त **असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु** तथा **उर्दू** भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। **पत्रिका मंगवाने हेतु, नयी सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिये मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें : व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नयी दिल्ली-110 066 दूरभाष : 26100207, 26105590,** तार : सूचनाप्रकाशन।

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिये आप हमारे निम्नलिखित **बिक्री केंद्रों** पर भी संपर्क कर सकते हैं : सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 (दूरभाष: 24365609) * 701, बी-विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष: 22610081) * 8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष: 22488030) * 'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर, चेन्नई-600070 (दूरभाष: 24917673) * प्रेस रोड, गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुवनंतपुरम-695001 (दूरभाष: 2330650) * ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष: 24605383) * फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलौर-560034 (दूरभाष: 25537244) * बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष: 2683407) * हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-2, अलीगंज, लखनऊ- 226024 (दूरभाष: 2225455) * अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, पाल्दी, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष: 26588669) * के.के.बी. रोड, नयी कॉलोनी, मकान संख्या-7, चेनीकुटी, गुवाहाटी-781003 (दूरभाष: 2665090)

चंदे की दरें : वार्षिक : 100 रु. **द्विवार्षिक :** 180 रु.; **त्रैवार्षिक :** 250 रु.; विदेशों में **वार्षिक** दरें : **पड़ोसी देश :** 500 रु.; **यूरोपीय एवं अन्य देश :** 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिये 'योजना' उत्तरदायी नहीं है।

आपकी राय

क्रमबद्ध विकास का सूचक

योजना का अगस्त 2007 अंक मिला। विशेषांक होने के कारण इसमें भरपूर सामग्री तो है ही, इसके आवरण पृष्ठ की कलाकृति मूर्धन्य चित्रकार सतीश गुजराल की अनुपम भेंट काफी आकर्षक एवं प्रेरणादायक है। संपादकीय भी किसी मायने में कम नहीं है। यह भी विषयवस्तु के सार तत्वों को समेटते हुए गागर में सागर जैसा प्रतीत होता है। जानकर संतोष हुआ कि आप आगामी अंकों में भी 1857 के विभिन्न आयामों पर तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था और हमारे शासन तंत्र से जुड़े विषयों पर प्रकाश डालते रहेंगे। यह अंक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में झांककर अतीत को देखने का सफल प्रयास है। इसके अलग-अलग हिस्से में अलग ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। कहीं उपनिवेशवाद की आर्थिक समीक्षा है तो कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पर गहन चर्चा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह है विकास की नयी-नयी योजनाएं। आपने इस पहलू पर भी यथोचित सामग्री देने का बखूबी प्रयास किया है।

अंक में गुलज़ार की कविता भी एक आकर्षक केंद्रबिंदु है। आज़ाद हिंद फ़ौज का प्रयाण गीत तो निस्संदेह इसमें चार चांद लगा देता है। यह नवयुवकों में नयी जान डालने एवं नया उत्साह पैदा करने के लिये पर्याप्त है। सिनेमा के माध्यम से मुक्ति कामना की जो एक झलक आपने प्रस्तुत की है वह भी काबिलेतारीफ है। सिनेमा की परछाइयों के माध्यम से आजकल की सच्चाईयों से रू-ब-रू होने का यह एक सशक्त माध्यम है। एक तरफ इससे जहां हम अपने अतीत को जान पाते हैं वहीं दूसरी ओर विकास की भावी योजनाओं को भी साकार रूप देने में कामयाब होते हैं। अतएव यह सुंदर झांकी संदर्भ विशेष में बड़े काम की चीज़ है। हालांकि इस संदर्भ में अगर हम तराना-ए-हिंदी की चर्चा न करें तो निस्संदेह एक गुस्ताख़ी होगी। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो है ही, साथ-ही-साथ यह अपने आप में वर्तमान व भविष्य के सुनहरे सपने को भी संजोए हुए है। चाहे जिस रूप में इसे गाया-गुनगुनाया जाए, यह मो. इक़बाल की एक अनुपम भेंट है।

योजना के प्रतीक चिह्न का ब्यौरा देकर आपने एक बड़ा काम किया है। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसका सही-सही मतलब नहीं समझ पाते। यह हमारे क्रमबद्ध विकास का सूचक है और अतीत को वर्तमान से जोड़ता है। आज यह हमारे देश की संपन्नता एवं विकास के उत्कर्ष की ओर इंगित कर रहा है। इसमें भविष्य में चहुंमुखी विकास की ढेर सारी संभावनाएं भी सन्निहित है।

अतएव इस अंक के लिये *योजना* परिवार तथा इससे जुड़े तमाम लोगों को कोटि-कोटि धन्यवाद।

राकेश कुमार
गढ़पर, उदंतपुरी, बिहार शरीफ
नालंदा

चित्रों ने दिया ऐतिहासिक महत्व

योजना के पिछले विशेषांकों की तरह अगस्त 2007 का अंक भी अत्यंत संग्रहणीय लगा। खासकर भारतीय स्वतंत्रता एवं उसके आंदोलन से जुड़े चित्रों ने इसे एक ऐतिहासिक अंक बना दिया है। विपिन चंद्रा, सव्यसाची भट्टाचार्य, स्वतंत्र मिश्र एवं ओ.पी. भट्ट सहित सभी लेखकों के लेख बहुत पंसद आए। इस अंक में साम्राज्यवाद का जो आर्थिक विवेचन विपिन जी ने किया है, वह अत्यंत सटीक लगा। साथ ही स्मृति कुमार सरकार का लेख भी अंग्रेज़ी राज़ की भारतीय नीति की समीक्षा करता है। ओ.पी. भट्ट के लेख से पता चला कि भारत में दलितों के ऊपर न सिर्फ़ ब्राह्मणवाद का बोझ था, बल्कि बैंक जैसी संस्थाएं भी 60 प्रतिशत तक ब्याज वसूल करके किस प्रकार दलितों को समूल नष्ट करने की साज़िश में शरीक़ थी।

लवकेश द्विवेदी
उरई, जालौन, उ.प्र.

मानवाधिकार संबंधी लेख दें

योजना अगस्त अंक में भारत का कृषि क्षेत्र में नियति से मिलन (स्वामीनाथन), आर्थिक विकास के 150 वर्ष (नारायण एन. आर. मूर्ति) तथा अबुसलेह की 'मानव विकास की यात्रा' काफी ज्ञानवर्द्धक लगी। ऐसे ही लोगों को भारत के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करना चाहिए। अनुरोध है कि मानवाधिकार से सबंधित विषय भी प्रकाशित करें जिससे संवेदनाशून्य लोग भी संवेदनापूर्ण हो सकें।

विजय कुमार
नया टीला, मुजफ्फरपुर, बिहार

जिज्ञासाएं हुईं शांत

योजना का स्वतंत्रता दिवस विशेषांक प्राप्त हुआ। इसने मेरे मन की तमाम जिज्ञासाओं को शांत किया जो मैं अक्सर सोचा करता था। इस सारगर्भित, विलक्षण विशेषताओं से परिपूर्ण विशेषांक के लिये *योजना* की संपूर्ण टीम को बधाई। विशेषांक में 'दादाभाई नौरोजी का अपवहन सिद्धांत' अंग्रेज़ी राज में भारतीय उद्योगों का विनाश, 'भारत में नियोजन का विकास' आदि लेख बहुत ही जानकारीप्रद व स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति का बखूबी वर्णन करने वाले हैं। इनसे मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। गुलज़ार का गीत बहुत ही संजीदा है।

हरित क्रांति के जनक एम.एस.स्वामीनाथन का लेख 'भारत का कृषि क्षेत्र में नियति से मिलन' भी कृषि के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने वाला है। आगामी अंक की प्रतीक्षा है।

सुधांशु पांडेय
राजकीय पालीटेक्निक, गोण्डा-271001

संपादकीय

मुद्रास्फीति में वृद्धि से चौतरफा चिंता होने लगी है। इसी के साथ-साथ यह चिंता भी है कि मुद्रास्फीति-नियंत्रण के उपायों से विकास भी प्रभावित हो सकता है। *योजना* का प्रस्तुत अंक मुद्रास्फीति बनाम विकास की इसी पहेली पर दृष्टिपात करता है।

इन पंक्तियों के लिखे जाने के समय मुद्रास्फीति गिरकर 3.79 प्रतिशत तक आ चुकी है। इस गिरावट का कारण जहां खाद्य और विनिर्मित वस्तुओं का सस्ता होना है, वहीं सरकार का मानना है कि मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुधारना होगा। मुद्रास्फीति में इस गिरावट से लोगों को राहत तो मिली है, परंतु इससे मुद्रास्फीति व विकास के बीच खींचतान पर चर्चा शीघ्र समाप्त नहीं होने वाली।

मुद्रास्फीति से कष्ट होना स्वाभाविक है। यह कष्ट उन आम लोगों को सबसे अधिक होता है जिनकी बंधी-बधाई आय होती है और खासकर जिनके पास नियमित काम और आय के निश्चित स्रोत नहीं होते। इससे बचतकर्ताओं को भी कष्ट होता है, जिसका प्रभाव निवेश और अंततः विकास पर पड़ता है। विकास का लाभ लोगों तक धीरे-धीरे पहुंचता है, परंतु मुद्रास्फीति सीधे आम आदमी को प्रभावित करती है।

अर्थशास्त्रियों के अनुसार, भारतीय संदर्भ में विकास और मुद्रास्फीति के बीच परस्पर द्वंद्व हाल के दिनों में अधिक मुखरित हुआ है। नब्बे के दशक के पूर्वार्द्ध तक मुद्रास्फीति में वृद्धि या तो मानसून की असफलता के कारण या फिर कच्चे तेल के भंडार में आई कमी के कारण होती थी। नब्बे के दशक के पूर्वार्द्ध में मुद्रास्फीति में वृद्धि होती रही और विकास में भी तेज़ी आई। नब्बे के दशक के उत्तरार्द्ध में विकास की गति धीमी हुई तो मुद्रास्फीति में भी कमी आ गई। वर्तमान में, विकास दर 8-9 प्रतिशत की गति से बढ़ रही है तो मुद्रास्फीति की दर में भी वृद्धि देखी जा रही है।

यदि ध्यान से देखा जाए तो पता चलेगा कि इस समय मुद्रास्फीति में जो वृद्धि हो रही है उसके मूल में खाद्य पदार्थों की क़ीमतें हैं, जो आपूर्ति संबंधी दबाव झेल रही हैं। उदाहरणार्थ, इस वर्ष अगस्त माह में थोक मूल्य आधारित सब्ज़ियों में 25.3 प्रतिशत और खाद्य तेलों में 12.3 प्रतिशत मूल्यवृद्धि देखी गई। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल का मूल्य 81 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति की दर 5 प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है। मध्यम अवधि में इसके 4-4.5 प्रतिशत तक सीमित रहने का अंदाजा लगाया गया है।

मुद्रास्फीति में वृद्धि के प्रति हमारी क्या नीति होनी चाहिए? राजनीतिक धरातल पर निर्धनों के उपभोग (खपत) स्तर को बनाए रखना हमारी उच्च प्राथमिकता है। राजकोषीय उपायों से केवल थोड़े समय के लिये ही राहत मिलती है। मौद्रिक नीति में परिवर्तन का प्रभाव अधिक होता है, और यदि मुद्रास्फीति में गिरावट नहीं आई तो इसी उपाय को अपनाना होगा तथापि, मौद्रिक नीति संबंधी उपायों से केवल अस्थायी तौर पर समाधान हो सकता है। मुद्रास्फीति में जो वृद्धि हम देख रहे हैं, वह आपूर्ति में अभाव के कारण है , विशेषकर खाद्यान्न क्षेत्र में।

योजना के इस अंक में इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेषज्ञों के विचारों से आप रूबरू होंगे- क्या मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिये विकास को रोक देना चाहिए? क्या कसी हुई मौद्रिक नीति से विकास थम जाएगा? और क्या मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिये सरकार को आपूर्ति से जुड़े पक्ष और उत्पादकता में वृद्धि पर ज़ोर देना चाहिए? यह अंक इन्हीं प्रश्नों का हल खोजने का प्रयास करता है। ❑

आर्थिक संकेतक

संकेतक: वार्षिक	इकाइयां	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (प्रक्षेपित)
जनसंख्या (1 अक्तूबर तक)	करोड़ में	101.9	103.7	105.5	107.3	109.1	110.7	112.2	
जीडीपी वर्तमान बाज़ार मूल्य पर	करोड़ रुपये	21,02,375	22,81,058	24,58,084	27,65,491	31,26,596	35,67,177	41,25,725	
जीडीपी प्रतिव्यक्ति (वर्तमान मूल्य)	रुपये	20,632	21,976	23,299	25,773	28,684	32,224	36,771	
सकल घरेलू बचत (वर्तमान मूल्य)	जीडीपी प्रति.	23.7	23.5	26.4	29.7	31.1	32.4		
सकल घरेलू पूंजी निर्माण (वर्तमान मूल्य)	जीडीपी प्रति.	24.3	22.9	25.2	28.0	31.5	33.8		
सकल राजकोषीय हानि	जीडीपी प्रति.	5.7	6.2	5.9	4.5	4.0	4.1	3.7	
वर्तमान मूल्य पर जीडीपी एफसी का क्षेत्रवार हिस्सा									
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	जीडीपी का	23.4	23.2	20.9	20.9	18.8	18.3	17.5	
उद्योग	जीडीपी का	26.2	25.3	26.4	26.1	27.5	27.6	27.9	
सेवा	जीडीपी का	50.5	51.5	52.7	52.9	53.7	54.1	54.6	
मूल्य (वार्षिक औसत)									
थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू 100.00)	अप्रैल 1993=100	155.7	161.3	166.8	175.9	187.2	195.5	206.1	
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक =औद्यो. कर्म	जुलाई 2001=100	95.93	100.07	104.05	108.07	112.2	117.2	125.0	
कृषि उत्पादन आम सूचकांक भारत									
खाद्यान्न	मिलि. टन	196.8	212.9	174.8	213.9	198.4	208.6	216.1	217.6
मोटा अनाज	मिलि. टन	185.7	199.5	163.7	198.3	185.2	195.2	201.9	
चावल	मिलि. टन	85.0	93.3	71.8	88.5	83.1	91.8	92.8	93.0
गेहूं	मिलि. टन	69.7	72.8	65.8	72.2	68.6	69.4	74.9	75.0
दालें	मिलि. टन	11.1	13.4	11.1	14.9	13.1	13.4	14.2	14.6
तिलहन	मिलि. टन	18.4	20.7	14.8	25.2	24.4	28.0	23.9	27.3
गन्ना	मिलि. टन	296.0	297.2	287.4	233.9	237.1	281.2	345.3	365.0
उद्योग और ऊर्जा									
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (मान-100) (वार्षिक औसत)	अप्रैल 1993=100	162.69	166.99	176.64	188.97	204.8	221.52	247.05	
	% परिवर्तन	5.06	2.64	5.78	6.98	8.37	8.16	11.53	
व्यावसायिक ऊर्जा उत्पादन	एमटीओई #	230.9	237.9	246.9	259.2	272.0	281.4		
सार्वजनिक इकाइयों द्वारा ऊर्जा उत्पादन	मिलि. केडब्ल्यूएच	501.2	517.4	532.7	565.1	594.5	617.5	662.5	
विदेश व्यापार									
निर्यात	मिलि.अमरीकी. डॉलर	44,147	43,958	52,823	63,886	83,502	1,03,075	1,26,246	
आयात	मिलि.अमरीकी. डॉलर	50,056	51,567	61,533	78,203	1,11,472	1,49,144	1,90,438	
विदेशी मुद्रा भंडार (मार्च अंत)^	मिलि.अमरीकी. डॉलर	39,554	51,049	71,890	1,07,448	1,35,571	1,45,108	1,91,924	
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (शुद्ध)	मिलि.अमरीकी. डॉलर	4,031	6,125	5,036	4,322	5,987	7,661	19,442	
भारत में पोर्टफोलियो निवेश (शुद्ध)	मिलि.अमरीकी. डॉलर	2,760	2,021	9,79	11,356	9,311	12,494	7,004	
रुपया विनिमय दर	रुपये/डॉलर	45.61	47.55	48.30	45.92	44.95	44.28	45.29	

संकेतक : मासिक/इकाइयां		जुलाई 06	अगस्त 06	सित. 06	अक्तू. 06	नव. 06	दिस. 06	जन. 07	फर. 07	मार्च 07	अप्रैल 07	मई 07	जून 07	जुलाई 07	अग 07
मूल्य															
थोक मूल्य सूचकांक	1993-94=100	204	205.3	207.8	208.7	209.1	208.4	208.8	208.9	209.8	211.5	212.3	212.3	213	213.4
(सभी सामग्रियां)	% परिवर्तन	4.82	5.13	5.38	5.47	5.49	5.68	6.38	6.34	6.61	6.27	5.45	4.52	4.4	3.97
कृषि															
वास्तविक वर्षा: अखिल भारत	मिलीमीटर	243	325	169	44	50	12	2	30	32	27	48	153	259	299
सामान्य वर्षा से अंतर	प्रतिशत	-5	8	0	-47	33	-24	-92	32	14	-20	-31	8	0	-2
चावल भंडार (केंद्रीय पूल)	मिलि. टन	9.5	7.8	6.0	12.5	12.1	12.0	12.6	14.0	13.2	13.5	12.6	10.6		
गेहू भंडार (")	मिलि. टन	7.3	6.7	6.4	6.0	5.6	5.4	5.4	5.1	4.6	11.6	13.3	12.8		

निवेश (सीएमआईई कैपएक्सडेटाबेस)		मार्च '05	मार्च '06	जून '06	सितंबर '06	दिसं. '06	मार्च '07	जून '07
तिमाही के अंत में बकाया परियोजना निवेश*	करोड़ रुपये	1975539	2814222	3055052	3616013	4056048	4480243	4697985
	परियोजना की संख्या	9,826	10,054	10,431	11,291	12455	12,735	12,898

टिप्पणी : (क), %परिवर्तन वार्षिक आधार पर है; (ख) एमटीओई: मिलियन टन तेल का समतुल्य; (ग) ^भारत सरकार के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा का कुल मूल्य (स्वर्ण एवं एसडीआर को छोड़कर); (घ)* यह देश में चल रहे सभी चालू पूंजीगत व्यय वाली परियोजनाओं की परियोजना लागत का सकल योग है। ये परियोजनाएं इनमें से किसी भी तीन अवस्थाओं में हो सकती हैं - घोषित, प्रस्तावित अथवा जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा हो।

स्रोत : योजना आयोग में स्थित i³ (आई-क्यूब) सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई)।

क्या है मुद्रास्फीति?

मुद्रास्फीति को मूल्य संकेतकों में होने वाले परिवर्तनों के जरिये मापा जाता है। मूल्य सूचकांक का उद्देश्य किसी वस्तु विशेष की बजाय वस्तुओं के मूल्यों में कुल मिलाकार हुई वृद्धि या कमी का परिमाण निर्धारित करना है। मूल्य सूचकांक निर्धारित करने के लिये किसी वस्तु विशेष के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों का औसत परिवर्तित मूल्य निकाला जाता है। वस्तु विशेष के भार का निर्धारण उनके तुलनात्मक महत्व पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर गेहूं के मूल्य में परिवर्तन होना, जिसका आप लगभग रोज़ाना उपभोग करते हैं, जूते-चप्पलों के मूल्य में बदलावों की अपेक्षा निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। सूचकांक मुख्यत: दो प्रकार के होते हैं- थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। पहले के तहत थोक मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है जो कि उत्पादकों के दृष्टिकोण से ज्यादा अर्थपूर्ण हो सकता है जबकि दूसरे के तहत खुदरा मूल्यों में होने वाले बदलावों को मापा जाता है जो निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं के लिये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस मुद्रास्फीति की दर के बारे में भारत में अक्सर समाचारपत्रों में चर्चा होती रहती है उसकी गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। जब अख़बार में यह छपता है कि अमुक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 5.2 प्रतिशत पहुंच गई तो इसका अर्थ है कि थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर वस्तुओं के मूल्यों का औसत स्तर इससे पहले के वर्ष में उसी सप्ताह के आंकड़ों के मुक़ाबले (या 52 सप्ताह का सारांश)5.2 प्रतिशत अधिक था। यह जानना ज़रूरी है कि मुद्रास्फीति घटने का अर्थ यह नहीं है कि मूल्य भी घट रहे हैं। इसमें तो सिर्फ़ मूल्यों के घटने या बढ़ने की दर दर्शाई जाती है।

भारत में कितने प्रकार के सूचकांक हैं?

हमारे यहां एक थोक मूल्य सूचकांक और तीन तरह के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हैं। ये तीन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हैं: खेतिहर मज़दूरों के लिये, औद्योगिक कामगारों के लिये और शहरी गैर-शारीरिक श्रम करने वाले कर्मचारियों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इतने ज्यादा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होने के पीछे कारण यह है कि ऊपर वर्णित प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं में कई प्रकार से भिन्नता होने की संभावना होती है। उदाहरण के तौर पर मुंबई में उपनगरीय ट्रेन टिकटों के मूल्यों को कृषि कामगारों संबंधी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल करना उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि शहरी गैर-शारीरिक श्रम करने वाले कर्मचारियों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल करना ज़रूरी है । इसी प्रकार खाद्य पदार्थ वर्ग में, विशेषकर अनाज, कृषि श्रमिक संबंधी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में ज्यादा महत्व रखता है क्योंकि यह माना जाता है कि कृषि कामगार अपनी दिहाड़ी का ज्यादा हिस्सा भोजन पर ख़र्च करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अखिल भारतीय सूचकांक के अलावा विभिन्न शहरों या केंद्रों के लिये भिन्न-भिन्न क्यों होता है।

मूल्य सूचकांक किस प्रकार निर्धारित होता है?

पहले कदम के तौर पर यह तय करना होता है कि सूचकांक में किन वस्तुओं या श्रेणियों को शामिल किया जाना है। थोक मूल्य सूचकांक के मामले में इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी उत्पादित या प्रयुक्त वस्तुएं। लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मामले में वस्तुओं का निर्धारण घरेलू सर्वेक्षणों के आधार पर किया जाता है जिससे उपभोक्ता पैटर्न का पता चलता है। इसके बाद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मामले में वस्तु को कुल व्यय में उसके हिस्से के औसत के अनुसार समग्र सूचकांक में एक स्थान प्रदान किया जाता है तथा थोक मूल्य सूचकांक के मामले में सभी वस्तुओं के कुल उत्पादन में उस वस्तु के उत्पादन मूल्य के औसत के रूप में वज़न निर्धारित होता है। सूचकांक प्रत्येक वस्तु के औसत वज़न का सूचक है। किसी एक आधार वर्ष को चुना जाता है जिसमें प्रत्येक वस्तु के मूल्य को देखा जाता है और इस प्रकार समग्र सूचकांक को 100 अंकों के साथ समीकृत किया जाता है। इसे भविष्य की क़ीमतों के लिये आधार माना जाता है। इस प्रकार यदि कहा जाए कि गेहूं का मूल्य आधार वर्ष में 10 रुपये प्रति किग्रा. है तथा इससे अगले वर्ष की उसी अवधि में यह 15 रुपये प्रति किग्रा. हो, तो बाद के वर्ष के लिये गेहूं सूचकांक में परिवर्तन समग्र सूचकांक को कितना प्रभावित करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका भार कितना है। जितना ज्यादा भार होगा उतना ही अधिक उसका असर होगा। ❑

2007 के परिणाम

शीर्षस्थ 100 में 10 स्थान एवं कुल 77 चयन 474 सीटों में महिलाओं में सर्वोच्च स्थान, मानविकी विषयों में सर्वोच्च स्थान एवं भूगोल से सर्वोच्च स्थान

आनंदिता मित्रा (8वां स्थान)

पिछले पांच में से चार वर्षों में भूगोल विषय से सर्वोच्च स्थान

2007 आनंदिता मित्रा (8वां स्थान), 2006 रणधीर कुमार (3सरा स्थान), 2004 भास्कर कातम्मेनी (8वां स्थान), 2003 अजय कुमार मिश्रा (5वां स्थान)

हिंदी माध्यम से भूगोल में सर्वोच्च स्थान

2005 विक्रांत पांडेय (63वां स्थान), 2004 प्रदीप सिंह राजपुरोहित (13वां स्थान), 2003 अजय कुमार मिश्रा (5वां स्थान)

2007 के भूगोल से चार शीर्षस्थ स्थान

8th Rank
Anindita Mitra

19th Rank
Sheetal Verma

22nd Rank
Atul Kumar

33rd Rank
Abhay

पाँच वर्षों के परिणाम संयोग नहीं होते। यह परिणाम हमारी गुणवत्ता, काम के प्रति निष्ठा, इन परिणामों को देने की क्षमता और वर्ष दर वर्ष इसे बरकरार रखने की हमारी अदम्य इच्छाशक्ति को दृष्टिगत करता है। फिर भी उपरोक्त सारे परिणाम हमारे लिए मिथ्या है निस्सार है। हम यह सारी बाते नहीं याद रखते इतने अधिक विद्यार्थियों का उत्तीर्ण होना हमारी गुणवत्ता, हमारे निरंतर बेहतर करने की लगन, विद्यार्थियों के प्रति ईमानदारी को दर्शाता होगा पर हमारे लिए यह बातें पारिभाषिक अर्थ से परे है, गुणवत्ता का अर्थ हमारे किए बिल्कुल अलग ही है.....

गुणवत्ता का अर्थ	विद्यार्थियों के अध्ययन, प्रयास एवं उनकी मेहनत को कम करना है
गुणवत्ता का अर्थ है	निश्चल संकल्पना
गुणवत्ता का अर्थ है	उच्च विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास
गुणवत्ता का अर्थ है	संकल्पनाओं एवं तथ्यों का अन्तर्सम्बन्ध
गुणवत्ता का अर्थ है	प्रश्न के जवाब के उत्तर के लिए व्याख्याओं का संकुचन एवं प्रसार
गुणवत्ता का अर्थ है	सुरक्षा
गुणवत्ता का अर्थ है	ज्ञान की गहनता एवं विस्तार
गुणवत्ता का अर्थ है	प्रत्यक्षीकरण एवं विचारों का संतुलन
गुणवत्ता का अर्थ है	सफलता की निश्चितता

.....और .....उपरोक्त बातें हम हमेशा याद रखते हैं

IAS 2007-08

कक्षा कार्यक्रम

भूगोल

के. सिद्धार्थ

के निर्देशन में

शरत्कालीन सत्र 15 अक्टूबर 2007

यह कार्यक्रम उन विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट रूप से इस तरह तैयार किया गया है कि वे 2007 के मुख्य परीक्षा के समय तक अपने पाठ्यक्रम की भली भांति तैयारी कर उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकें, इसके बावजूद कि वे भूगोल का क, ख, ग, भी नहीं जानते। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को कहीं भी, कभी भी किसी भी दशा में बिना किसी सहायता के परीक्षा में औसत से अधिक अंक प्राप्त कराने का प्रयत्न करता है और प्रारंभिक परीक्षा की इतना गहन अभ्यास कराता है कि विद्यार्थी 80–90 प्रश्नों का उत्तर दे सकें।

सम्मिलित कार्यक्रम

मौलिक भूगोल 15 से 21 अक्टूबर '07

मुख्य कक्षा–22 अक्टूबर से दिसंबर अंत

प्रारंभिक कक्षा–जनवरी–फरवरी

SAT जनवरी 2008

QIP जुलाई 2008

इतिहास

कुमार नलिन

विकसित मुख्य सह प्रारंभिक परीक्षा समन्वित कार्यक्रम में मुख्य परीक्षा का नवीनतम् अवधारणाओं के आधार पर विस्तृत विश्लेषण एवं प्रारंभिक परीक्षा का सघन विश्लेषण। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एक सामान्य छात्र को मुख्य परीक्षा में 350+ अंक पाने और प्रारंभिक परीक्षा में 105+ प्रश्न हल को तैयार कराना है।

राजनीति विज्ञान

कैलाश मिश्रा

भारत में भूगोल का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

के. सिद्धार्थ के निर्देशन में

ENSEMBLE KNOWLEDGE PARK

North Delhi: 2272, Hudson Lines, Kingsway Camp, Delhi-9 PH.: 011-27418242, 27411099, 9811506926

YH-10/07/12

मुद्रास्फीति पर वित्तमंत्री का रुख कड़ा

आपूर्ति की कमी समाप्त करने के लिये कृषि उत्पादन बढ़ाएं – चिदंबरम

मुद्रास्फीति एक मौद्रिक स्थिति है। आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा प्रकाशित आर्थिक दृष्टिकोण में विस्तार से इस पर चर्चा की गई है। विशुद्ध मुद्रास्फीति की गणना ईंधन के मूल्यों और खाद्य पदार्थों के मूल्यों के अंतर के आधार पर की जाती है। मौद्रिक नीति का वस्तुत: खाद्यान्न और ईंधन के मूल्यों पर कोई असर नहीं पड़ता। कच्चे तेल के मूल्यों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। आज कच्चे तेल की क़ीमत 72 डॉलर प्रति बैरल है और खाद्यान्न मूल्य मांग और आपूर्ति के आधार पर घटते-बढ़ते रहते हैं।

खाद्यान्न मूल्यों की क़ीमतों से वृद्धि का जो दबाव है, उसका मुख्य कारण गेहूं, चावल, दालों और तिलहनों के उत्पादन में आया ठहराव है। जब तक हम गेहूं, चावल और दालों का उत्पादन अधिक मात्रा में नहीं बढ़ाएंगे, देश में यह दबाव लगातार बना रहेगा। भारत जैसा कोई भी विशाल देश आयातित खाद्यान्न पर निर्भर नहीं रह सकता। हमें सभी अनाज पैदा करना होगा, जो हमें चाहिए। यही कारण है कि हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया है। और यही वजह है कि राज्यों को खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये हम 2 खरब 50 अरब रुपये की विशेष योजना लेकर आए हैं। लेकिन हाल-फिलहाल हमें सभी आयातों का ढंग से प्रबंधन करना होगा और भंडारों को बढ़ाना होगा।

परंतु ईंधन और खाद्यान्न क़ीमतों को छोड़ दिया जाए तो जहां तक विशुद्ध मुद्रास्फीति का संबंध है, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति विषयक उपायों का प्रभाव दिख रहा है। मुद्रास्फीति अब नीचे की ओर आ रही है। थोक मूल्य सूचकांक संबंधी मुद्रास्फीति गिर कर अब 4.05 प्रतिशत पर आ गई है। हमें इस थोक मूल्य सूचकांक जनित मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाना होगा। देश की मुद्रास्फीति के इतिहास पर नज़र डालें तो स्थिति अधिक स्पष्ट होगी। 1979-80 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक 17.1 प्रतिशत थी; और 1990-95 की अवधि में जब आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई तो मुद्रास्फीति की औसत दर 11 प्रतिशत थी; 2000 और 2004 के बीच थोक मूल्य सूचकांक की दर 4.9 प्रतिशत थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस वर्ष विकास दर को देखते हुए मुद्रास्फीति की दर 4.5 से 5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। परंतु हमारा लक्ष्य इसे चार प्रतिशत के आसपास ही रखने का है। हम मौद्रिक और राजकोषीय उपायों के साथ-साथ आपूर्ति संबंधी वे सब कदम उठाएंगे जिससे मुद्रास्फीति 4 से 4.5 प्रतिशत के बीच रखी जा सके। आशा करनी चाहिए कि इसे 4 प्रतिशत के आसपास ही रखा जा सकेगा।

परंतु जहां तक गेहूं, चावल, दूध और तिलहनों जैसी आवश्यक वस्तुओं की मूल्यवृद्धि का प्रश्न है, यह आपूर्ति और मांग का मामला है। जब तक आपूर्ति में वृद्धि नहीं होगी, मूल्यों पर दबाव बना रहेगा।

वित्तमंत्री पी.चिदंबरम ने राज्यसभा में आगे कहा कि मूल्य वृद्धि रोकने के लिये वे और भी राजकोषीय कदम उठाने से संकोच नहीं करेंगे। मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण फलों, सब्ज़ियों, बाजरा, मसूर, चना और कुछ अन्य विनिर्मित वस्तुओं के मूल्यों में हुई बढ़ोतरी है।

श्री चिदंबरम ने विनियोग विधेयक, 2007 पर राज्यसभा में हुई बहस का उत्तर देते हुए कहा कि "मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिये मैं और भी राजकोषीय उपाय करने से हिचकिचाऊंगा नहीं।" टमाटर और आलू और जैसी चीजों की मांग और आपूर्ति में अंतर को आयात से नहीं पाटा जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि, " हम टमाटर और आलू का आयात नहीं कर सकते।"

वित्तमंत्री ने यह बात भी दोहराई कि सरकार राजकोषीय विवेक की नीति को जारी रखकर इस वर्ष के अंत तक राजस्व घाटा शून्य तक ले आने का प्रयास करती रहेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि वर्ष 2008-2009 तक वे राजस्व घाटे को पूरी तरह से समाप्त करने में समर्थ होंगे। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में निश्चित किए गए लक्ष्यों का यह महत्वपूर्ण अंश है। ❑

(संसद के दोनों सदनों में वित्तमंत्री पी. चिदंबरम द्वारा दिए गए भाषण से उद्धृत)

पुनर्विचार मांगता संबंध : महंगाई और आर्थिक विकास

❍ कमलनयन काबरा

वर्तमान वित्तीय वर्ष में क़ीमतों की बढ़त ने आम आदमी की तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों मुश्किलें बढ़ा दी है। इस स्थिति से निपटने के लिये मौद्रिक नीति, आयात नीति, सीमा-शुल्क नीति के तहत कई प्रशासनिक उपाय किए गए हैं। सप्ताह-दर-सप्ताह थोक क़ीमतों के सूचकांक के आंकड़ों की विधिवत घोषणा की जाती है। प्रशासनिक शीर्ष स्थान पर क़ीमतों की चाल-ढाल पर नज़र रखने की कुछ विशेष तज़बीज करने की भी घोषणा की गई थी। इन प्रयासों के नतीज़ों से शासकीय स्तर पर आमतौर पर संतोष प्रकट किया जा रहा है। इस संतुष्टि को सफलता माना जा रहा है अथवा इसे 'स्थिति नाजुक, परंतु नियंत्रित' वाली तर्ज़ पर समझा जाए अथवा लीपापोती का सामान्य प्रशासनिक उपाय, यह सोचने-समझने का मसला है। मुद्रास्फीति के रंग-ढंग का चालू वर्ष का लेखा-जोखा देखने के साथ-साथ महंगाई के बारे में सरकारी नज़रिये और उनसे उपजी नीतियों का परिप्रेक्ष्य भी विचारणीय विषय है। मुद्रास्फीति के लगभग प्रत्येक पहलू पर भ्रम की कुछ पर्तें जमी नज़र आती हैं। सामान्य क़ीमत स्तर ऐसी की लगातार तीव्र गति वृद्धि, जो अमूमन धीरे-धीरे स्वयं अपने आपको गति देने वाला बड़ा कारण बन जाता है, अंग्रेज़ी में 'इंफ्लेशन' नाम से जानी जाती है। इसे हिंदी में मुद्रास्फीति कहना हमारे भ्रम का प्रतीक है। मुद्रास्फीति का अर्थ देश में किसी अवधि विशेष में प्रसारित सब प्रकार की मुद्रा की मात्रा की अतिशय बढ़ोतरी हो सकता है। क़ीमतों की लगातार, स्वयंपोषक बढ़त का एक कारण मुद्रा की मात्रा का इस तरह का प्रसार हो सकता है। परंतु किसी भी आंशिक तथा स्थिति विशेष में लागू कारण को उस घटना का नाम तो नहीं माना जाना चाहिए।

ख़ैर, मुख्य मुद्दा यह है कि क्या 4 प्रतिशत के इर्द-गिर्द देखी गई थोक क़ीमतों की बढ़ोतरी हमारी क़ीमत नीति का वाजिब लक्ष्य माना जा सकता है। इस सवाल के साथ ही यह भी पूछा जा सकता है कि क्या वर्तमान महंगाई की दर वास्तव में चार प्रतिशत के आसपास नहीं है अथवा कुछ अरसे पहले छह प्रतिशत की दर से अब लक्ष्यानुसार यानी केवल सहनीय अपितु शुभकर चार प्रतिशत के जादुई अंक तक ला दी गई है। प्रत्येक सप्ताह घोषित महंगाई वृद्धि दर या परिवर्तन दर एक अनंतिम, तात्कालिक आंकड़ा होता है। ध्यान देने लायक बात यह भी है कि थोक दाम व्यावसायियों और व्यापारियों की रुचि के मामले होते हैं। आम लोगों के लिये, गृहणियों के लिये तो खुदरा क़ीमतों की स्तर तथा उनकी बढ़त की दर सिरदर्द के मसले होते हैं। मुद्रास्फीति पर चर्चा आम लोगों के लिये सार्थक तभी हो सकती है जब उसका केंद्रबिंदु खुदरा व्यापार क़ीमत को बनाया जाए और उनकी त्वरित जानकारी हासिल की जाए। हमारे यहां खुदरा क़ीमतों के तीन सूचकांक बनाने की स्वस्थ परंपरा है। अब इसे ज्यादा केंद्रों के आधार पर, सूचना तकनीक के आधार पर शीघ्र ही प्रकाशित किया जाए और इन क़ीमतों को भी नीति प्रक्रिया में विचारणीय विषय बनाया जाए।

इन कुछ शुरुआती बिंदुओं में एक अति महत्वपूर्ण तत्व छिपा है। ज़रूरी है कि जिस अंक के रूप में महंगाई को नापा जाता है उसकी प्रकृति, औचित्य और असर पर भी गौर किया जाए। मुद्रास्फीति द्वारा पता लगाया जाता है कि सभी बिक्री योग्य उत्पादों की क़ीमतें कुल मिलाकर किसी अवधि विशेष में घट रही हैं, बढ़ रही हैं अथवा स्थिर हैं और कितनी तेज़ी से घट या बढ़ रही हैं। सभी चीज़ों के दाम को मिलाकर उनका सूचकांक बनाया जाता है। इसमें संपूर्ण उत्पादन में विभिन्न वस्तुओं की भागीदारी के आधार पर उनको अलग-अलग वजन दिया जाता है। इस तरह क़ीमतों के सूचकांक में आया परिवर्तन महंगाई की स्थिति का, उसके स्तर, बदलाव की दिशा और दर का, पूरा सही चित्र पेश कर देता है। परंतु हमारे यहां महंगाई का स्तर नहीं बताकर इस साल के सप्ताह के परिवर्तन को पिछले साल के परिवर्तन की दर के मुक़ाबले कितना घटा या बढ़ा है इसका आंकड़ा दिया जाता है। महंगाई की दर घटने के समाचार से खुश खरीदार को बाज़ार पहुंचने पर सदमा लगेगा कि क़ीमतें तो बढ़ी हैं परंतु पहले से कम तेज़ी से।

हमें यह लगता है कि महंगाई नापने का यह तरीका महंगाई के प्रति नीति निर्माताओं के दृष्टिकोण का सांकेतिक प्रतिबिंब भी है। महंगाई का यह माप उसके बढ़ने की कम या ज्यादा होती दर ऐसा संकेत देती है मानों क़ीमतों की अंतहीन, सतत वृद्धि कोई अनिवार्यता हो। इन दिनों यह कहा जाता है कि महंगाई वृद्धि दर को चार प्रतिशत तक रोक कर रखना सरकार का नीतिगत उद्देश्य है। इसके साथ ही अभी सरकार की आर्थिक नीतियों के लिये जिम्मेदार तत्वों का यह कथन भी सामने आया जिसमें

जनता को यह सलाह दी गई कि वे लगातार जारी महंगाई बढ़त को जिंदगी की ठोस सच्चाई के रूप में मानना शुरू करें क्योंकि ऐसी महंगाई तो आर्थिक वृद्धि की अपरिहार्य लागत है। लगता है, मानो क़ीमत स्थायित्व को आर्थिक वृद्धि के प्रतिकूल और मंहगाई की हल्की-हल्की, मंद-मंद गजगति को आर्थिक वृद्धि में सहायक मानने का सोच इस मत के पीछे छिपा है।

क़ीमतों में परिवर्तन और आर्थिक वृद्धि निस्संदेह आपस में जुड़े हुए होते हैं। आर्थिक परिवर्तन और प्रसार के साथ अर्थव्यवस्था की संपूर्ण मांग तथा आपूर्ति दोनों बदलते हैं। ये बदलाव हमेशा और अनिवार्य रूप से आपस में संतुलन बनाए रखें और साथ में प्रत्येक उत्पादित और मांगी गई वस्तु तथा सेवा की आपूर्ति औसत तथा सीमांत लागत और मांग भी पारस्परिक संतुलन बनाए रखें, यह कैसे संभव हो सकता है? नयी वस्तुओं व सेवाओं के चलन, तकनीकी परिवर्तन, नये निवेश से स्थायित्व,आर्थिक गतिविधियों के संचालन की भौगोलिक स्थिति, लोगों की पसंद-नापसंद तथा रुचियों के निरंतर बदलाव, आर्थिक संसाधनों का विभिन्न वर्गों, तबकों, परिवारों आदि में निरंतर बदलता वितरण आदि भी ऐसे हों कि उनके कारण क़ीमतों की निर्धारण करने वाली मांग, आपूर्ति तथा निर्णय करने की शक्तियां या तो बदले ही नहीं अथवा उनके विभिन्न प्रभाव एक-दूसरे को निरस्त करके क़ीमतों के स्तर तथा उनके पारस्परिक संबंध अपरिवर्तित रहने दें। ये सब बातें कदापि संभव नहीं हैं। इस तरह, सिद्धांत के स्तर पर तीव्र गतिमय, निरंतर तथा गुणात्मकता से परिपूर्ण आर्थिक प्रसार के साथ क़ीमतों के सभी निर्धारक तत्वों में भी मात्रात्मक, गुणात्मक तथा ढांचागत परिवर्तन एक अपरिहार्य नियति है। फलत: विभिन्न क़ीमतें भी बदलती रहती हैं। इस तरह एक वर्द्धमान, गतिशील, विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में क़ीमतों के यथावत बने रहने की आशा के कोई ठोस आधार नहीं होते हैं। आर्थिक बढ़ोतरी का विभिन्न अवधियों का अनुभव भी उपर्युक्त सैद्धांतिक परिकल्पना की पुष्टि करता है।

परंतु यह भी सोचने का विषय है कि क़ीमतों में परिवर्तन की अनिवार्यता को सभी क़ीमतों के संयुक्त सूचकांक अर्थात क़ीमत स्तर को तीव्र और स्वपोषक वृद्धि की अनिवार्यता क्यों माना जाए। यह सच है कि एक दीर्घकालिक परिदृश्य में विभिन्न विकासोन्मुख तथा विकसित देशों का ऐतिहासिक अनुभव संपूर्ण तथा औसत आय वृद्धि के साथ-साथ क़ीमत स्तर के चढ़ाव का अनुभव बड़ा है। किंतु आर्थिक बढ़त और क़ीमत स्तर की सहवर्ती वृद्धि, इन दोनों अनुभवों के साथ विभिन्न रूपों में जुड़े अन्य अनेक परिवर्तनों को ध्यान में लिये बिना समझना भी निरी भूल होगी। आर्थिक वृद्धि और क़ीमत सार की वृद्धि की अनुभूत दिशा केवल वृद्धि का नहीं, अपितु आर्थिक वृद्धि के स्वरूप का द्योतक है। आर्थिक बढ़ोतरी के साथ-साथ आर्थिक ढांचा, विभिन्न उद्योगों-कार्यकलापों का सापेक्षिक रिश्ता बदल जाता है। उपभोग का ढांचा, जनसंख्या का शहरों तथा गांवों में वितरण, जनसंख्या की आयु, लिंग तथा व्यावसायिक संरचना आदि भी बदल जाते हैं। रुचियों और पसंद, फैशन तथा चलन में भी फेर-बदल होता है। अत: क़ीमतों के नये समीकरणों की रचना भी होती रहती है। उत्पादन बचत निवेश तथा तकनीक करने वाले तबके और संगठन बदलते रहते हैं और उनकी आर्थिक-राजनीतिक ताक़त भी बदलती रहती है। आर्थिक बढ़त के साथ क़ीमत स्तर की वृद्धि यह दिखाती है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की लागत बढ़ी है, अथवा मांग के मुक़ाबले आपूर्ति कम बढ़ी है, अथवा क़ीमत निर्धारक आर्थिक वित्तीय इकाइयों की बाज़ार में प्रतियोगितात्मक ताक़त अपेक्षाकृत ज्यादा बढ़ी है।

इस तरह के मूल्य-स्तरवर्द्धक आर्थिक वित्तीय परिवर्तनों के अनेक आर्थिक, वित्तीय, मौद्रिक,विदेशी व्यापार, विदेशी मुद्रा तथा उसकी विनिमय दर, तकनीकी परिवर्तन, संसाधनों की निवल उपलब्धि संबंधी लोगों की उपभोग प्रवृत्ति और विभिन्न चीजों की मांग, आर्थिक वित्तीय शक्ति संतुलन, उत्पादन तथा मांग की भौगोलिक स्थानों पर अवस्थिति, यातायात लागत, कराधान आदि दिए रहते हैं। इन सब बातों पर सरकारी नीतियों और कामों के सीधे तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव भी छिपे रहते हैं। निवेश तथा तकनीकी प्रगति उत्पादन के विशालतर होते स्तर, नये प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, श्रम की उत्पादकता बढ़ने आदि के द्वारा आर्थिक वृद्धि का मुख्य स्रोत बढ़ते उत्पादन के कारण औसत लागत में कमी के रूप में प्रकट या प्रभावी होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आपूर्ति की दिशा से क़ीमतों के बढ़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न होने का कोई आधार प्रस्तुत नहीं होता है। हो सकता है कि ऐसे स्रोतों से उत्पन्न बढ़ोतरी के कारण क़ीमतें घट भी जाएं। परंतु यदि तकनीकी परिवर्तन वस्तुत: तकनीकी प्रगति नहीं है (चाहे वह ज्ञान-विज्ञान की नयी ही नहीं नवीनतम, चामत्कारिक खोजों पर ही आधारित क्यों न हो) और पूंजी, श्रम, प्रबंधन, ऊर्जा तथा प्राकृतिक संसाधनों की बढ़ती मात्रा के अनुपात में प्रतिफल नहीं देता है, अथवा पूंजी या प्रबंधन अथव श्रम प्रदान करने वाले अपने बढ़ती उत्पादकता से ज्यादा प्रतिफल ले लेते हैं, अथवा अतिरिक्त माल का उत्पादन मांग के मुक़ाबले कम होता है, तो स्पष्ट है कि ऐसी आर्थिक संवृद्धि के साथ क़ीमतों में इज़ाफ़ा होगा।

कई बार सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर अत्यधिक करारोपण से भी दाम बढ़ जाते हैं। मौद्रिक अधिकारियों और बैंकों द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता के परनाले खोल कर आर्थिक-मौद्रिक संतुलन भंग करने के कारण भी क़ीमतों में अति तीव्र गति से बढ़ोतरी होने लगती है। विदेशी आर्थिक संबंधों और विदेशी विनिमय दर संबंधी गलत नीतियां भी क़ीमत स्फीति को हवा दे सकती हैं। अर्थव्यवस्था में अनुपार्जित आय यानी आमदनी का ऐसा सृजन जिसके साथ या जिसके कारण साथ-साथ आनुपातिक या उससे ज्यादा बिक्री योग्य माल बाज़ार में नहीं बनता हो, बढ़ने से भी मांग और आपूर्ति में असंतुलन उत्पन्न होकर क़ीमतों पर ऊपर चढ़ने का दबाव बन जाता है। उदाहरण के लिये, भारत में पिछले एक दशक से ज्यादा अरसे से शेयर और वायदा बाज़ार का अति विशाल प्रसार हो रहा है। इन दोनों बाज़ारों का सालाना कारोबार संपूर्ण राष्ट्रीय आय के दो गुने के लगभग हो गया है। अनेक लोग विद्यमान शेयरों की ख़रीद-फ़रोख्त और जिंसों के वायदे से मोटी रकम हासिल कर लेते हैं। इस करोड़ों-अरबों रुपयों की आमदनी के बदले

एक धेले के मोल के तुल्य भी उत्पादन बाज़ार में नहीं आता है। इस तरह इन दोनों बाज़ारों का अति प्रसार महंगाई को बल देता है।

कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकलता है कि आर्थिक बढ़ोतरी का एक खास किस्म का चरित्र या स्वरूप मुद्रास्फीति या क़ीमतों में अति तीव्र और निरंतर उछाल का कारण बनता है। आर्थिक बढ़ोतरी को हमेशा और अनिवार्य रूप से आर्थिक विकास नहीं कहा जा सकता है। इसके अनेक आधार होते हैं। यदि आर्थिक बढ़ोतरी आय और संपत्ति की गैर-बराबरी बढ़ाती है, क़ीमतों में अनिवार्य रूप से तेज़ और स्वपोषित उछाल का रुख पैदा करती है, रोज़गार नहीं बढ़ाती है तथा पर्यावरण प्रदूषण और संकट का कारण बनती है तो निस्संदेह यह सुविकास नहीं, अपितु कुविकास होता है।

इस सैद्धांतिक और वस्तुगत पृष्ठभूमि में भारत में मुद्रास्फीति के अनुभव के विविध पक्षों को समझा जा सकता है। जैसे-जैसे क़ीमत स्तर बढ़ता है, रुपये की क्रय शक्ति, उसका ठोस वास्तविक मूल्य घट जाता है। संलग्न तालिका में पिछले कुछ सालों में रुपये की घटती क़ीमत और महंगाई के दावानल में उसके भस्म होते वास्तविक मोल की कहानी कहती है।

तालिका स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कितने अंशों तक क़ीमतों के सामान्य स्तर के बढ़ने से रुपये की क्रयशक्ति घटती रहती है। पिछले कुछ सालों में हमारी राष्ट्रीय आय की बढ़ोतरी की दर काफी ऊंची रही है। परंतु क्या इस दौरान संसाधनों का उपयोग कुशलतापूर्वक हुआ है? 1990-91 से 2007 के अप्रैल माह तक रुपये की क्रयशक्ति घटकर लगभग एक तिहाई रह गई है। क्या इस दौरान वास्तविक राष्ट्रीय आय में रुपये के मूल्य की छीजन के अनुपात में वृद्धि आई है? इसके अलावा यह नहीं भूलना चाहिए कि एक आर्थिक इकाई द्वारा चुकाई गई क़ीमत विक्रेता के लिये आमदनी का स्रोत होती है। इसलिये बढ़ती क़ीमतें आय और संपत्ति का पुनर्वितरण करती है। बाज़ार में बिक्री करने वालों, क़ीमत वसूलने और तय करने वालों के मुक़ाबले खरीदी करने वालों तथा तयशुदा अपरिवर्तित क़ीमत प्राप्त करने वालों की वास्तविक आमदनी घटती है। आम आदमी का उपभोग स्तर गिरता है। मंहगाई के कारण वास्तविक आमदनी में उनका हिस्सा घट जाता है। बढ़ती महंगाई आय में मुनाफ़े का अनुपात बढ़ाती है। हमारे यहां थोक क़ीमतों के सूचकांक के मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र का वजन 60 प्रतिशत से अधिक है। अनाजों आदि के साथ इस क्षेत्र के दामों के उछाल ने कंपनी क्षेत्र को मुनाफ़ास्फीति का स्वर्णिम युग दिया है। एक आकलन के अनुसार, पिछले पंद्रह सालों में देश की सौ सबसे बड़ी कंपनियों का मुनाफ़ा तेरह गुना बढ़ गया है।

तालिका

भारतीय रुपये की क्रय शक्ति

(आधार वर्ष 1990-91-100 पैसे)

वर्ष	वास्तविक क्रय शक्ति
1991-92	88
1991-93	80
1991-94	74
1991-95	65
1991-96	61
1991-97	58
1991-98	55
1998-99	52
1999-00	51
2000-01	47
2001-02	46
2002-03	44
2003-04	42
2004-05	39
2005-06	38
2007(अप्रैल पहला सप्ताह)	35

स्रोत: वी. उपाध्याय: इनफ्लेशन: आल्टरनेटिव इकोनॉमिक सर्वे: इंडिया, 2006-07

इनके वास्तविक उत्पादन में निश्चित तौर पर तेरह गुना ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई। इस तरह मूल्य संवर्द्धन से बेहिसाब ज्यादा गैर-आनुपातिक मुनाफ़ा वृद्धि कार्यकुशलता का प्रमाण नहीं, बल्कि प्रतियोगिता शक्ति के कमज़ोर होने या अल्प-प्रतियोगिता (ओलीगोपाली) के बढ़ने का प्रमाण है। बाज़ारीकरण की नीति अपनाने का एक मकसद 'गेटिंग प्राइसेज़ राईट' यानी क़ीमतों का सही, सच्चा और उचित निर्धारण था। क्या आय और संपत्ति की विषमता बढ़ने, मुनाफ़े में कार्यकुशलता और मूल्य संवर्द्धन से बेहिसाब बढ़ाने, आम आदमी के ज़ेब का वास्तविक वजन घटाने वाली महंगाईवर्द्धक राष्ट्रीय आय की दर की बढ़ोतरी विकास के मानवीय पक्ष को कमज़ोर नहीं करती है? वैसे गनीमत है कि भारत की ये बाज़ारवादी नीतियां महंगाई बढ़ाने की दक्षिण अमरीका जैसी मुद्रास्फीति के भयावह अनुभव से भारतीय जनता को अब तक त्रस्त नहीं कर पाई हैं। वहां तीन-चार अंकों वाली सालाना मुद्रास्फीति, यानी हर सप्ताह दो अंकों वाली मुद्रास्फीति द्वारा उत्पन्न त्रासदी ने असमानताओं, जीवनस्तर ह्रास तथा दीर्घकालिक आर्थिक हानि करने की असमर्थता का कष्ट भोगा था। यह भारतीय लोकतंत्र, व्यापक ग़रीबी तथा मध्यवर्ग की ताक़त ही है की मुद्रास्फीति की मीठी, छिपी कटारी अभी रुपये की क्रय शक्ति को धीरे-धीरे ही छिजा पाती है। परंतु यदि विषमता, ग़रीबी और सही दीर्घकालिक सामाजिक आकलन पर आधारित आर्थिक निर्णयों को बढ़ावा देना है तो चार प्रतिशत महंगाई को सामान्य, स्वीकार्य नीतिगत उद्देश्य मानने के आग्रह से छुटकारा पाकर ज्यादा वाज़िब मूल्य स्थायित्व के लक्ष्य को पाने वाली नीतियां अपनानी होंगी। वास्तविकता के स्तर पर हमारी नीति का लक्ष्य क़ीमत स्थायित्व तथा समष्टिगत संतुलन के साथ विकास मानकर नीतियां बनानी होंगी। इस तरह नीतिगत लक्ष्य, ठोस बहुमुखी नीतियां और उनके क्रियान्वयन की प्रशासनिक तज़बीज निर्धारित करने में क़ीमतों की क्रयशक्ति पर प्रभाव के तुरत-फुरत असर के साथ उनके आय तथा संपति के पुनर्वितरणकारी (यानी मुनाफ़े में उछाल तथा श्रम आदि की अपेक्षाकृत कम परिवर्तनशीलता) प्रभाव को संतुलित तथा समुचित महत्व देना होगा। ❑

(लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री और नयी दिल्ली स्थित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हैं।

ई-मेल: kamalnkabra@yahoo.com.in)

भारत की प्राथमिक आवश्यकता है विकास

अधिकतम विकास और पूंजी निवेश के तरीके

❍ श्याम पोनप्पा
टी. सी. ए. श्रीनिवास राघवन

मुद्रास्फीति और विकास की स्थिति के बारे में बहस सैद्धांतिक रूप से रुचिकर हो सकती है, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों के बीच इस तरह की तुलना की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिये कि मुद्रास्फीति के लिये आमतौर पर त्रुटिपूर्ण अनुपयुक्त नीतियां जिम्मेदार होती हैं न कि उच्च विकास दर। यदि नीतियां और कार्य पद्धति सही हो तो विकास की उच्च दर और मुद्रास्फीति की निम्न दर, दोनों ही हासिल किए जा सकते हैं। चीन इसका उदाहरण है, जहां पिछले कई वर्षों से विकास दर 9 प्रतिशत के आसपास और मुद्रास्फीति 3 प्रतिशत के नीचे रही है। हालांकि खाद्यान्न के मूल्यों में अधिक वृद्धि जैसी कुछ क्षेत्रों में विसंगतियां दिखाई देती हैं (तालिका -1)।

परंतु विकास को संतुलित, व्यवस्थित और समावेशी होना ही चाहिए। लक्षित प्रतिव्यक्ति जीडीपी ओईसीडी देशों की जीडीपी तीन चौथाई हिस्से से कम हो सकती है, बशर्ते हम अपने जीवनस्तर को परिभाषित करने और उसको हासिल करने के बारे में थोड़ा विचारवान हों। जैसेकि उपभोक्तावादी और संतुलित जीवनशैली या एकीकृत क्षेत्रीय नियोजन बनाम शहरों में पलायन जैसे विषयों पर हमारी सोच स्पष्ट होनी चाहिए।

निर्धनतम व्यक्ति मुद्रास्फीति से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं और इसी से उच्च स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता जन्म लेती है। यदि अस्थिरता पैदा करने वाले स्तरों को छोड़ भी दिया जाए तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत की प्राथमिक आवश्यकता विकास है और इससे संपन्न वर्ग भी अलग नही हैं। यही कारण है कि जैसा ऊपर परिभाषित किया गया है, विकास पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, न कि मुद्रास्फीति को रोकने पर।

- **विकास हेतु अनिवार्यतायें**

(1) नयी परियोजनाओं हेतु नीतिगत ढांचा

दीर्घकाल तक निर्बाध रूप से चलने वाले विकास की शर्तें एक ठोस नीतिगत ढांचे, या इसके न होने से निर्धारित होती हैं। नीचे दी गई शृंखला से स्पष्ट होता है कि किसी विशेष वातावरण में यह किस तरह उपलब्धि-उन्मुखी उत्पादन क्षमता को सुगम बनाती है।

नीतिगत उद्देश्य - नियम-कानून - संस्थागत सहायता - सहायक वातावरण

तालिका-1

चीन का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एवं मुद्रास्फीति

	01-05 औसत	2006	2007 (संभा.)	2008 (संभा.)
जीडीपी (प्रतिशत वृद्धि, वास्तविक)	9.5	10.5	9.4	9.5
मुद्रास्फीति	1.3	1.4	2.5	2.7

स्रोत : ईडीसी इकोनामिक्स - http://www.edc.ca/english/docs/gchive-e.pdt

भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के इस दौर में इस समय जनहित में तीन लक्ष्य अनिवार्य हैं:

(क) आर्थिक विकास;
(ख) प्रतिव्यक्ति जीडीपी में वृद्धि; और
(ग) समान वितरण

ही है। करोड़ों लोगों की उत्पादन क्षमता, कम आमदनी के कारण अवसरों की कमी से प्रभावित होती है। व्यवहार की लागत को देखते हुए यह जरूरी हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवनस्तर के समावेशी विकास में संभावित सुधार के लिये भी ऐसा होना जरूरी

यह एक ऐसी चीज है जिसका समाधान करने में भारत की सभी सरकारें असफल रही हैं। एक कड़ी से दूसरी कड़ी की ओर सुनिर्धारित और सुविचारित तरीके से बढ़ने की बजाय सस्ते और काम चलाऊ राजनीतिक जोड़तोड़ का सहारा लिया जाता रहा है। इसके

उदाहरण हैं - दूरसंचार सेवाओं के लिये प्रारंभिक निविदायें, पहले भारतीय दूरसंचार नियंत्रक प्राधिकरण का गठन, कुछ समय बाद उसकी बर्ख़ास्तगी, 1999 में एनटीपी का विकास (इसके साथ मैं नज़दीकी रूप से जुड़ा था, परंतु दुख है कि न तो मैं इसका श्रेय ले सकता हूं और न ही किसी उत्तरदायित्व का खंडन कर सकता हूं)।

• ब्याजदर

(क) निम्न ब्याज दरों का महत्व

निम्न ब्याज दरें विकास को मूलभूत गति और बल प्रदान करती हैं। अतएव मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों में बेहतर समन्वय जरूरी है ताकि ब्याज दरों को कमतर रखा जा सके। यह जरूरी है पर्याप्त नहीं। संस्थागत प्रक्रिया की भी आवश्यकता है जिससे छोटे कारीगरों और लघु एवं मझोले उद्योगों को आसानी से मिल ऋण सके। दुनियाभर में इस समय अतिशय तरलता की स्थिति है जहां वास्तविक अर्थव्यवस्था से होने वाले लाभ की बनिस्वत पैसे के कारोबार में अधिक लाभ हो रहा है। विनिर्माण और अवस्थापना के मुकाबले विशुद्ध वित्तीय खेल से अधिक लाभ मिल रहा है और ऐसा कई वर्षों से हो रहा है। यदि और जब कभी विश्व में कोई प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन होगा, जैसेकि तमाम सुरक्षित कोष डगमगा जाएं, या फिर अमरीका में ज़मीन-जायदाद का बाज़ार रसातल में चला जाए, उपभोक्ता व्यय में बड़ी कमी आ जाए या फिर सुरक्षित स्वर्णकोष अमरीकी कोषागारों की बजाय अन्य कहीं निवेश किया जाने लगे या फिर चीन में कोई बड़ी उलझन सुलझा ली जाए, तो इस स्थिति में बदलाव आ सकता है। फिलहाल संस्थागत निधियों को बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल कर उत्पादक उद्यमों में लगाया जाना चाहिए। अधिक लाभदायी वित्तीय अवसरों के लोभ से दूर रहने की कोशिश होनी चाहिए।

(ख) उच्च ब्याज दर विकास को कुंठित कर सकता है

भारत में ब्याज दरें आर्थिक विकास की गति को नष्ट करने के नज़दीक हैं। *इकोनॉमिस्ट* के कथनानुसार अक्सर मंदी तब आती है जब बढ़ती ब्याज दरों के कारण कंपनियां रोज़गार की संख्या कम कर देती हैं और पूंजीगत व्यय घटा देती हैं।

(ग) अनुकरण हेतु नियोजन-प्रादर्श

भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्त मंत्रालय नियोजन प्रादर्शों का तर्कपूर्ण ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे परिदृश्यों और प्रतिक्रियाओं का अनुसरण किया जा सके। उदाहरण के लिये, निकट भविष्य में कितनी और कितने संभावित मूल्यों पर गैस/तेल का आयात किया जाने वाला है, और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे निर्यात के पिटारे में क्या-क्या है और कौन-कौन सी मुद्रा किन विनिमय दरों पर प्राप्त होने की संभावना है और आयात में क्या-क्या है और इसी के साथ साथ क्या होगा यदि तरह का विश्लेषण किया जा सकता है ताकि विकल्पों के बारे में निर्णय लिया जा सके। इससे हमें सुविचारित निर्णय लेने में मदद मिलेगी, जिससे रिज़र्व बैंक और सरकार एक समन्वित कार्ययोजना तैयार कर सकें।

• 'ओवर हीटिंग' एवं मुद्रास्फीति

(क) चिरकालिक अभावों के लिये संरचनात्मक समाधान

पिछले कुछ वर्षों में भारत के विस्फोटक विकास को देखते हुए आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन के कारण दबाव बने रहने की संभावना है। त्वरित आयात और सीमाशुल्क में तीव्र कटौती से कुछ सीमा तक इस स्थिति से उबरा जा सकता है। लेकिन गेहूं, दालों, आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं के बारे में भारत को जिस तरह की समस्यायें 2007 में झेलनी पड़ीं, उनके लिये दीर्घकालिक समाधानों की जरूरत है। एक-एक चीज की आपूर्ति क्षमता में सुधार का कोई छोटा रास्ता नहीं है। उदाहरणार्थ, आस्ट्रेलिया अथवा म्यांमा, से सामयिक समझौते कर दालों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है, अथवा गेहूं के अर्जन और आपूर्ति का कुशल प्रबंधन कर समस्या का समाधान किया जा सकता है।

(ख) पूंजी प्रवाह से निपटना

हम इस समय एक विरोधाभासी स्थिति में हैं। हमें जहां पूंजी के आंतरिक प्रवाह की जरूरत है, वहीं हम इस तरह के प्रवाह से पैदा होने दबावों, जैसे- मुद्रास्फीति, संपदा के बुलबुले और विनिमय दर में वृद्धि से भी जूझ रहे हैं। परंतु यह स्थिति उच्च विकास दर के चरण से गुजर रही सभी अर्थव्यवस्थाओं में आती है। जब तक विकास दर ऊंची बनी रहेगी, पूंजी का प्रवाह भी बना रहेगा। बेहतर होगा कि आधिक्य की इस समस्या से हम किस तरह निपटें, इस पर विचार करें।

उपर्युक्त के आलोक में समाधान इस प्रकार से हैं:

• निवेश नीतियों का निर्माण

सभी क्षेत्रों के उत्पादक उपक्रमों में प्रत्यक्ष निवेश के लिये अनुकूल वातावरण का निर्माण करना। यह एक सच्चाई लगती है, परंतु नये निवेशों को स्वीकार करने (दूसरे दर्ज़े के बाज़ार का कारोबार नहीं) की हमारी क्षमता बहुत सीमित प्रतीत होती है। उदाहरण के लिये बिजली को लीजिए। पिछले पांच वर्षों में क्षमता में वृद्धि 4 हजार मेगावाट प्रतिवर्ष की रही है जबकि पिछला रिकार्ड क़रीब तीन हजार मेगावाट का था। इसके बावजूद, ऊपर वर्णित एक सिरे से दूसरे सिरे तक की प्रक्रिया शृंखला में बिना कोई बड़ा परिवर्तन किए, 2012 तक प्रतिवर्ष 15 हजार मेगावाट क्षमता की वृद्धि की योजना बनी हुई है। इस तरह के लक्ष्यों के यथार्थवादी होने के लिये हमें परियोजना को प्रारंभ करने की प्रक्रिया की अपनी प्रणालियों में व्यापक और एकीकृत परिवर्तन करने होंगे। अन्यथा सर्वव्यापी विफल संकट के कारण हम हमेशा की तरह अपनी आर्थिक क्षमता के इष्टतम तक पहुंचने के लिये हांफ-थक कर ठहर जाएंगे।

स्पष्ट है कि संभव बनाने वाली अवस्थापना: ऊर्जा, परिवहन, संचार, प्रारंभिक शिक्षा और स्वास्थ्य एवं सफाई, हमारी पूर्व आवश्यकता है। परंतु जैसा अगले अनुच्छेद में वर्णित है व्यावहारिकता क्षेत्रवार निवेश के लिये वरीय और चरणबद्ध दृष्टिकोण के साथ अंतरिम उपायों के लिये विवश कर देती है।

• विदेशी मुद्रा भंडार का परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन

परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन दृष्टिकोण अचानक ही भारी भुगतान करने (बहिर्प्रवाह) के ख़तरे पर ध्यान देते हुए अतिरिक्त आरक्षित राशि की व्यवस्था करने की बात करता है। इन आरक्षित राशियों का विदेशों में मान्यता प्राप्त फंड मैनेजरों के जरिये लाभदायक तरल संपत्तियों में निवेश किया जा सकता है। तरलता (नकद पैसे) के संकट की स्थिति में इन परिसंपत्तियों को बेचकर नकदी प्राप्त की जा सकती है। इस तरह का निवेश : (क) मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के साथ-साथ (ख) रुपये पर लघु अवधि के प्रवाह के दबाव को भी कम करता है ताकि रुपये में मज़बूती आ सके।

यद्यपि सैद्धांतिक रूप से यह एक सीधा सा तरीक़ा है परंतु इसकी सफलता के लिये वास्तव में परिसंपत्ति-देयता अंतर आकलन और परिसंपत्ति प्रबंधन में विशेषता की आवश्यकता है। इसके लिये अर्थशास्त्रियों, शिक्षाविदों, सांसदों अथवा मंत्रियों की समितियों की कोई जरूरत नहीं है। यहां यह याद रखना लाभकर होगा कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं है।

इसके बावजूद, इसे शुरू करने के लिये एक बहुपक्षीय राजनीतिक पहल की आवश्यकता है। क्योंकि साधारण तौर पर रिज़र्व बैंक इसे स्वयं नहीं कर सकता। बेहतर होता कि इस पर एक बहुपक्षीय विशेषज्ञ समिति की सहायता से मंत्रियों का अधिकार संपन्न समूह विचार करे। अमरीकी ख़ज़ाने में भारत की आरक्षित राशि को जमा कर, अमरीकी उपभोक्ताओं की मदद जारी रखने से तो यही बेहतर होता। एक खरब 50 अरब डॉलर पर केवल 15 प्रतिशत की आय से 22 अरब 50 करोड़ डॉलर (9 खरब रुपये) की अवसर लागत हासिल की जा सकती है।

• परिणामों पर प्रभाव डालने हेतु हस्तक्षेप (बोनिंग)

जिस तक सरकारें बिना किसी पक्षपात के बाज़ारों को व्यवस्थित बनाए रखने के लिये निष्पक्षता पूर्वक काम करती हैं, उस हद तक सरकारी हस्तक्षेप एक स्वस्थ शासन की निशानी है। परंतु समस्या तब खड़ी होती है, जब पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जाती है या अति उत्साह में हस्तक्षेप किया जाता है। यह जनहित में नहीं होता।

निष्कर्ष

आगे का रास्ता अज्ञात है। हम दूसरे स्थानों से सबक ले सकते हैं, लेकिन भारत को अपना मार्ग खुद चुनना होगा। कहां जाना है और कैसे जाना है, यह खुद ही तय करना होगा। इसके लिये निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता के साथ मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों में बेहतर समन्वय की आवश्यकता है और क्षेत्रीय विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इन प्रयासों के लिये, अनेक आयामों में विशेषता को एक साथ लाना होगा, नये-नये विचारों को अपनाना होगा, परंतु अनुपयुक्त प्रादर्शों को लागू करने के बारे में सावधानी बरतनी होगी। उदाहरणार्थ, विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उभरते बाज़ारों में विकास और ब्याज दरों के बीच बिलकुल अलग तरह के संबंध होते हैं, ऐसी बातों पर ध्यान देना होगा। आरक्षित कोष प्रबंधन के लिये नियोजन और संभावित नकदी प्रवाह के आकलन, अंतर और निवेश प्रबंधन और रचनात्मक संरचना की आवश्यकता होती है। नीतिगत ढांचे के लिये एकीकृत प्रणाली दृष्टिकोण के साथ नियामक और निजीकरण नीति निर्धारण, ठोस वैधानिक और संगठनात्मक सहयोग, ऊर्जा, विद्युत उत्पादन/आपूर्ति, परिवहन, स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ-साथ विशेष प्रकार के नियोजन की आवश्यकता होती है। इनको ठोस परियोजना प्रबंधन की योग्यता और अनुशासन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हमें विकास के इस चरण में अपने उद्देश्यों के लिये उपयुक्त प्रणालियों की रचना करनी होगी और अपनी मार्ग प्रणाली का प्रबंधन करना सीखना होगा। ❑

(लेखकद्वय क्रमशः निजी क्षेत्र में निवेश बैंकर तथा बिजनेस स्टैंडर्ड के कंसल्टिंग एडीटर हैं।
ई-मेल : syamponapppa@gmail.com)

योजना

नवंबर 2007 अंक

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के 50 वर्ष

पर केंद्रित होगा

PATANJALI IAS/PCS

दर्शनशास्त्र की तैयारी हेतु समर्पित भारत का विशेषज्ञ संस्थान

सर्वाधिक लोकप्रिय, अंकदायी एवं सशक्त विषय

उनके लिए – जो सिविल सेवा की तैयारी प्रारम्भ कर रहे हैं, और उनके लिए भी जो सुधार चाहते हैं।

धर्मेन्द्र कुमार के विशेषज्ञतापूर्ण एवं सारगर्भित मार्गदर्शन में संस्थान ने अपनी स्थापना के पश्चात् दर्शनशास्त्र को लेकर सिविल सेवा के क्षेत्र में लगातार सफलता के नवीन प्रतिमानों को स्थापित किया है तथा इसे एक सुरक्षित, विश्वसनीय एवं सर्वाधिक अंकदायी विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया है।

दर्शनशास्त्र नया सत्र

(मुख्य परीक्षा - 2007)

प्रथम बैच - 21 नवम्बर (प्रातः 8:30)

दर्शनशास्त्र (प्रारम्भिक परीक्षा) Philosophy (P.T.)

स्वतंत्र बैच - 03 दिसम्बर 2007

पत्राचार कार्यक्रम

दर्शनशास्त्र (मुख्य परीक्षा) से संबंधित सम्पूर्ण सामग्री अब अपने परिष्कृत रूप में उपलब्ध है। इसमें वैसे सभी अध्यायों की भी समुचित एवं क्रमवार विवेचना की गई है जिस पर प्रमाणिक सामग्री सहजता से उपलब्ध नहीं है, जैसे-ईश्वर की धारणाएँ, ईश्वरविहिन धर्म, वैज्ञानिक मनोवृत्ति, लिंग समानता, पारिस्थितिकी दर्शन आदि। पत्राचार सामग्री को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित राशि का दिल्ली में भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट-"PATANJALI IAS CLASSES" के नाम भेजें। -

PATANJALI

2580, Hudson Line, Kingsway Camp, Near Delhi Universrity, Delhi - 110009.

Ph. No. : 32966281, 9810172345

YH-10/07/3

मुद्रास्फीति, विकास और ग़रीबी

○ देवेन्द्र कुमार पंत

इस समय भारत की विकास दर तेज़ है और देश जल्दी ही दो अंकों वाली वृद्धिदर प्राप्त करने की तमन्ना रखता है। लेकिन ज्वलंत प्रश्न यह है कि क्या आर्थिक विकास के लाभ सब तक पहुंच रहे हैं या समाज का कोई वर्ग ऐसा भी है जो इससे वंचित है?

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ग़रीबी हटाने को भारत की नियोजन प्रक्रिया में उच्च प्राथमिकता दी गई। देश में निर्धनता कम करने के उद्देश्य से ग़रीबी दूर करने वाले बहुत से कार्यक्रम शुरू किए गए। साथ ही, सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (सविल) पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत इस बात के लिये वचनबद्ध हो गया है कि 2015 तक ग़रीबी 1990 के स्तर से आधी रह जाएगी। दसवीं पंचवर्षीय योजना में सविल पर ध्यान दिया गया है और योजनावधि में कई लक्ष्य पूरे करने का निश्चय किया गया है। सविल के अंतर्गत भारत की स्थिति यह है कि 2015 तक ग़रीबी रेखा से नीचे वाली आबादी का प्रतिशत 1990 के 37.5 प्रतिशत से घटा कर 18.75 प्रतिशत किया जाए। 1999-2000 की स्थिति के अनुसार, ग़रीबी रेखा से नीचे वाले लोगों का अनुपात 26.1 प्रतिशत था और निर्धनता अंतर 5.2 प्रतिशत था। राष्ट्रीय खपत में ग़रीबों का अंश 10.1 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में और 7.9 प्रतिशत शहरी इलाकों में था और 47 प्रतिशत तक बच्चे औसत से कम भार वाले थे (*मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इंडिया कंट्री रिपोर्ट 2005*, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)।

इस समय भारत की विकास दर तेज़ है और देश जल्दी ही दो अंकों वाली वृद्धि दर प्राप्त करने की तमन्ना रखता है। लेकिन ज्वलंत प्रश्न यह है कि क्या आर्थिक विकास के लाभ सब तक पहुंच रहे हैं या समाज का कोई वर्ग ऐसा भी है जो इससे वंचित है? भारत जैसे विकासशील देश के समक्ष मौजूद अधिकांश समस्याओं का समाधान यह है कि यहां एक लंबे समय तक विकास की ऊंची दर बनाए रखी जाए। ग़रीबी हटाने पर आर्थिक विकास के प्रभाव को लेकर किसी तरह का मतभेद नहीं है। विकास लाभों को ऊपर से नीचे के वर्गों तक पहुंचाने के समर्थकों का तर्क है कि त्वरित विकास से ग़रीबी दूर होगी, लेकिन इस सिद्धांत के विरोधियों का मत है कि उन वितरण नीतियों पर अधिक ज़ोर दिया जाना चाहिए जिनका उद्देश्य ग़रीबों को वस्तुएं उपलब्ध कराना है, जैसे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आदि। विकास और ग़रीबी हटाने के अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से भी पता चलता है कि इसका मिला-जुला असर रहा है और जिन अर्थव्यवस्थाओं में तेज़ विकास और ग़रीबी हटाओ कार्यक्रम चलाए गए हैं, उनका अनुभव अलग-अलग प्रकार का रहा है। इस बारे में विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं के मतभेद के बावजूद यह माना जाता है कि अगर काफी समय तक लगातार विकास का क्रम जारी रहे तो यह ग़रीबी उन्मूलन और ऐसी ही अनेक समस्याओं का निवारण कर सकता है। इस समय भारत जैसे विकासशील देश की ज़रूरत इस बात की है कि वे विकास आदि के लिये आर्थिक विकास की नीतियां बनाएं।

वर्तमान विकास प्रक्रिया काफी ज़ोरदार रही है लेकिन इसके साथ ही मुद्रास्फीति भी बढ़ी है। 2006-07 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गई जब कि 2005-06 में यह 4.4 प्रतिशत थी। 12 दिसंबर, 2006 को समाप्त सप्ताह से 24 मार्च , 2007 के अंत तक मुद्रास्फीति दर 6 प्रतिशत से अधिक थी। 27 जनवरी, 2007 को समाप्त सप्ताह में अंक दर अंक मुद्रास्फीति सबसे ज्यादा यानी 6.7 प्रतिशत हो गई। थोक मूल्य सूचकांक 540 जिंसों और जिंस समूहों पर आधारित है लेकिन सेवा और परिसंपत्ति जैसे आवास, रीयल स्टेट, अंशपूंजी इसमें शामिल नहीं हैं। इस परिसंपत्ति वर्ग की क़ीमतें पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती रही हैं। सामान्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति अपेक्षाएं ऊंची हैं। भारत सरकार और रिज़र्व बैंक दोनों ने मुद्रास्फीति रोकने के

उपाय किए हैं। भारत सरकार के राजकोषीय उपायों का उद्देश्य पूर्ति पक्ष की समस्याओं को काबू में रखना रहा है और इसके लिये करों और आवश्यक वस्तुओं के उत्पाद शुल्क में कटौती की गई जबकि रिज़र्व बैंक के मौद्रिक उपायों के जरिये ब्याज दर बढ़ा कर परिसंपत्तियों की क़ीमतों में बढ़ोतरी रोकने की कोशिश की गई।

मौद्रिक उपायों - खासतौर पर ब्याज दरों का आवास मूल्यों पर बहुत असर पड़ता है। रिज़र्व बैंक की कार्रवाई इस अंतरराष्ट्रीय साक्ष्य के अनुरूप है कि मुद्रास्फीति में कटौती के लिये 1970 और 1980 के दशकों में जो मुद्रा नीति अपनाई गई उसके परिणामस्वरूप आवास मूल्य बहुत बढ़ गए (आईएमएफ (2003) वर्ल्ड इकोनामिक आउटलुक)। कठोर मुद्रा नीति के वांछित परिणाम हुए और आवास, निजी एवं कार वित्तपोषण आदि क्षेत्रों में बढ़ते ऋण विकास पर नियंत्रण पा लिया गया। लेकिन, 90 के दशक के उत्तरार्ध के अनुभव के अनुसार कठोर मुद्रानीति से आशंकाएं बढ़ जाती हैं कि अर्थव्यवस्था की प्रगति मंद हो सकती है। मुद्रास्फीति और विकास में संबंधों के बारे में बहुत-सा साहित्य उपलब्ध है। सामान्य रूप से जब अर्थव्यवस्था कम वृद्धि से तेज़ वृद्धि की ओर अग्रसर होती है तो कम अवधि के लिये मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। कारण यह है कि मांग बढ़ जाती है और क्षमतावृद्धि में समय लगता है। औसत से अल्प समय के लिये, जब क्षमता बढ़ा ली जाती है तो धीरे-धीरे मुद्रास्फीति और मूल्यों पर दबाव कम होने लगता है। भारतीय संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद और मुद्रास्फीति में परस्पर संबंध है या नहीं, यह सिद्ध नहीं हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद विकास और मुद्रास्फीति में 1993-1994 से 2006-07 तक 0.013 प्रतिशत का अंतर्संबंध रहा (तालिका-1)। अल्प समय तक मुद्रास्फीति विकास दर पर प्रभाव भले सकारात्मक रहे, लेकिन औसत से अधिक समय तक ऊंची मुद्रास्फीति दर विकास प्रक्रिया पर बुरा असर डाल सकती है।

तालिका : 1
सकल घरेलू उत्पाद विकास एवं मुद्रास्फीति दर

वर्ष	सघउ विकास	मुद्रास्फीति दर
1993-94	5.7	8.4
1994-95	6.4	12.5
1995-96	7.3	8.1
1996-97	8.0	4.6
1997-98	4.3	4.4
1998-99	6.7	5.9
1999-00	6.4	3.3
2000-01	4.4	7.2
2001-02	5.8	3.6
2002-03	3.8	3.5
2003-04	8.5	5.4
2004-05	7.5	6.5
2005-06	9.0	4.4
2006-07	9.4	5.4

नोट- सघउ विकास 1999-00 के मूल्यों पर आधारित है और मुद्रास्फीति दर का आधार थोक मूल्य सूचकांक (1993-94=100) को बनाया गया है।

ग़रीबी पर मुद्रास्फीति अथवा बढ़ते मूल्यों का प्रभाव यह होता है कि उनकी क्रयशक्ति कम हो जाती है। भारतीय संदर्भ में ग़रीबी का अनुमान राज्य की ग़रीबी रेखा का मापदंड होता है जिसका निर्धारण दिए गए कैलोरी मापदंडों के आधार पर किया जाता है (2400 किलो कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों और 2100 किलो कैलोरी शहरी इलाकों में)। इसमें न्यूनतम गैर-भोजन ज़रूरतें भी, जैसे- वस्त्र, आश्रय, परिवहन आदि शामिल की जाती हैं। इन ग़रीबी रेखाओं को राज्य विनिर्दिष्ट कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण ग़रीबी रेखा(सीपीआईआईडब्ल्यू) और, औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी ग़रीबी रेखा(सीपीपीआईडब्ल्यू) के आधार पर अद्यतन किया जाता है। इस प्रकार ग़रीबी निर्भर करती है संभावित आय पर जिसका आधार होता है कुल और क्षेत्रवार अर्थव्यवस्था का विकास और मूल्य वृद्धि। आय अर्जन और खपत ढांचे में भी अंतरराज्यीय विभिन्नता होती है अत: ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग होती हैं जिसके कारण

तालिका-2
सीपीआई (आईडब्लू) और सीपीआई (एएल) का प्रभाव दर्शाने वाला चार्ट

समूह एवं उपसमूह	सीपीआई (आईडब्लू) 1982	सीपीआई(एएल) आधार 1986-87
1.अनाज पेय एवं तंबाकू	60.15	72.94
-अनाज	20.47	40.94
-दालें	3.59	3.39
-दूध	6.45	3.74
-खाद्य तेल	5.03	3.83
-सब्जियां	5.71	4.18
-फल	-	0.88
-चीनी	2.72	2.58
2. ईंधन और रोशनी	6.28	8.35
3. परिधान एवं जूते	8.54	6.98
4. आवास	8.67	-
5. विविध	16.36	11.73
-मनोरंजन	1.40	0.53
-व्यक्तिगत परिचर्या	3.31	2.04
-परिवहन एवं संचार	2.65	1.67
-शिक्षा	1.74	0.41
-चिकित्सा	2.59	4.38
-घरेलू ज़रूरी चीजें	4.67	2.70
6. योग	100.00	100.00

नोट: 1. उपसमूह 'सब्जियां एवं फल' या सीपीआई (आईडब्ल्यू) के लिये एक ही उपसमूह में मिला दिया गया है।
2. सीपीआई (एएल) के अंतर्गत आवास समूह नहीं है क्योंकि आधार वर्ष में कृषि श्रमिकों के मामले में आवास लागत नगण्य पाई गई थी।
3. महत्व दर्शाने का यह तालिका उन आंकड़ों पर आधारित है जो 1982-83 में सीपीआई (आईडब्लू) के लिये परिवार जीवन सर्वेक्षण और सीपीआई(एएल) के लिये गृहस्थ उपभोक्ता जांच द्वारा 1983 में इकट्ठा किए गए थे।

स्रोत : संलग्नक 11.2, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की रिपोर्ट सितंबर 2001, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन

मुद्रास्फीति का ग़रीबी पर भिन्न प्रभार पड़ता है। खपत ढांचे में खान-पान की चीजों और तंबाकू समूह को औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 60.15 प्रतिशत महत्व दिया जाता है और इसी के आधार पर ग़रीबी रेखा का अनुमान लगाया और अद्यतन बनाया जाता है। कृषि मज़दूरों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इसे 72.94 प्रतिशत महत्व मिलता है (तालिका-2)। खाद्य अनाजों को इनमें क्रमशः 20.47 प्रतिशत और 40.94 प्रतिशत महत्व दिया जाता है। ग़रीबी पर मुद्रास्फीति का प्रभाव सापेक्ष मुद्रास्फीति के संघटकों के अनुसार भिन्न-भिन्न होगा। मुद्रास्फीति का स्तर भले ही वही हो, लेकिन इसमें बढ़ोतरी अनाजों के कारण हुई है तो इसका असर ग़रीबों पर अधिक होगा लेकिन यह उछाल 'ईंधन या रोशनी' अथवा 'परिधान एवं जूतों' के कारण है तो यह ग़रीबों पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव छोड़ेगा।

भारत में ग़रीबी 1973-74 में 54.88 प्रतिशत से घट कर 2004-05 में 21.77 प्रतिशत पर आ गई (तालिका-3)। अखिल भारतीय स्तर पर मिक्स्ड रिकॉल पीरियड खपत आधार पर ग़रीबी 1999-00 में ग्रामीण, शहरी और सभी क्षेत्रों में क्रमशः 27.1 प्रतिशत, 23.62 प्रतिशत और 26.1 प्रतिशत थी जो 2004-05 में और गिरी तथा क्रमशः 21.8 प्रतिशत, 21.7 प्रतिशत और 21.8 प्रतिशत हो गईं। परिणामस्वरूप ग़रीबी गिरावट दर 3.57 प्रतिशत रही। 1999-00 और 2004-05 के ग़रीबी अनुमान सही अर्थों में पहले के ग़रीबी अनुमानों से तुलनीय नहीं हैं। लेकिन ग़रीबी गिरावट दर, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर और थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति से कुछ मोटे अनुमान लगाए जा सकते हैं।

तालिका-3

विभिन्न वर्षों के लिये ग़रीबी अनुमान (%)

वर्ष	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित
1973-74	56.44	49.01	54.88
1977-78	53.07	45.24	51.32
1983	45.65	40.79	44.48
1987-88	39.09	38.20	38.86
1993-94	37.27	32.36	35.97
1999-00	27.09	23.62	26.10
2004-05	21.79	21.70	21.77

नोट : 1999-00 के ग़रीबी अनुमान मिक्स्ड रिकॉल पीरियड खपत वितरण पर आधारित हैं।

स्रोत : योजना आयोग

1973-74 से 2004-05 तक ग्रामीण, शहरी और सभी क्षेत्रों के लिये ग़रीबी में गिरावट की दर 3.01 प्रतिशत, 2.47 प्रतिशत और 2.90 प्रतिशत रहने का अनुमान है और विकास की तुलना में ग़रीबी घटने के लचीलेपन की औसत दर क्रमशः 0.59, 0.47 और 0.57 होने का अनुमान लगाया गया है। इससे ज़ाहिर होता है कि विकास की अच्छी दर का शहरी की तुलना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर पड़ता है। 1993-94 और 1999-00 में बीच ग़रीबी की गिरावट दर और सकल आय वृद्धि - दोनों ही छह वर्षों में सबसे अधिक थी। इस दौरान ग़रीबी गिरावट का लचीलापन भी लगभग उतना ही देखा गया जितना 1983 से 1987-88 के बीच देखा गया था। क्या इसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि ग़रीबी निवारण के मामले में भी लाभ ऊपरी वर्ग से छन कर नीचे पहुंचने का सिद्धांत काम कर रहा है? सकल आय वृद्धि और ग़रीबी गिरावट दर (सभी क्षेत्र) के बीच सहसंबंध बहुत ज्यादा नहीं है (0.46)। लेकिन, इससे सबूत मिलते हैं कि ऊपर से छन कर नीचे पहुंचने का सिद्धांत टूट चुका है। यह सिद्धांत शहरी इलाकों पर लागू हो सकता है। सकल आय वृद्धि और ग़रीबी गिरावट दर में सह संबंध शहरी इलाकों के लिये 0.71 है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिये यह 0.35 है।

तालिका-4

ग़रीबी कमी दर, सघउ विकास एवं मुद्रास्फीति दर

अवधि	ग़रीबी कमी दर				1990 की क़ीमतों (प्रतिशत) पर सघउ विकास				सीपी आधारित मुद्रास्फीति			डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति		
	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त		कृषि	उद्योग	सेवाएं	योग	सीपीआईएएल	सीपीआईआईडब्लू	सभी जिंसें	प्रारंभिक वस्तुएं	ईंधन बिजली, रोशनी और सिंधक	औद्योगिक माल
1973-74 से 1977-78	1.53	1.98	1.66		3.91	6.00	5.10	4.72	6.85	7.34	7.9	7.3	16.9	6.8
1977-78 से 1983	2.48	1.71	2.36		2.81	4.44	5.21	3.98	8.35	9.18	9.5	9.4	13.0	9.1
1983 से 1987-88	3.80	1.63	3.32		0.02	4.98	6.90	3.99	4.93	7.64	6.2	6.7	6.3	6.0
1987-88 से 1993-94	0.79	2.73	1.28		4.81	5.64	6.37	5.68	10.12	9.61	9.6	8.8	10.7	9.8
1993-94 से 1999-00	5.18	5.11	5.21		3.40	6.66	8.36	6.51	8.40	8.84	6.5	8.0	8.4	5.5
1999-00 से 2004-05	4.26	1.68	3.57		1.76	6.65	7.66	6.01	2.14	3.96	5.2	3.6	11.9	3.9

अगर हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ग़रीबी गिरावट दर पर चर्चा करें तो देखेंगे कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब ग्रामीण ग़रीबी गिरावट दर शहरी दर के मुक़ाबले अधिक है। पहले भी इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी गई है। 1977-98 से 1983, 1983 से 1987-88 और 1993-94 से 1999-00 में यह बात खासतौर से ठीक पाई गई। 1999-00 से 2004-05 तक 2.54, 1983 से 1987-88 के दौरान की 2.34 की दर

कुछ ज्यादा है। ये दोनों कालावधियां भी लगभग उसी तरह की हैं जो 1983-84 से 1987-88 के बीच थीं जब औसत कृषि विकास दर 0.06 प्रतिशत और 1999-00 से 2004-05 के बीच 1.76 प्रतिशत रही। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 1999-00 और 2004-05 के बीच ग्रामीण ग़रीबों की संख्या 229.44 लाख घटी जब कि शहरी ग़रीबों की संख्या 11.93 लाख बढ़ गई। अगर हम 1973-74 से 1977-78 और 1987-88 से 1993-94 के समय को छोड़ दें, तो पाएंगे कि अन्य चार कालावधियों में ग्रामीण ग़रीबों की संख्या घटी है। हालांकि शहरी ग़रीबों की संख्या सिर्फ़ 1993-94 और 1999-00 के बीच कम हुई।

ग्रामीण और शहरी इलाकों में ग़रीबी घटने की दर पर सकल आर्थिक विकास का असमान प्रभाव पड़ने के क्या कारण हैं? जैसाकि पहले भी जिक्र किया गया है, ग़रीबी का आकलन उस राज्य विनिर्दिष्ट ग़रीबी रेखा से किया जाता है जिसे सीपीआईएल और सीपीआईआईडब्लू की वृद्धि के आधार पर अद्यतन बनाया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पर बारीकी से नज़र डालने से मालूम होगा कि जिन वर्षों में ग़रीबी गिरावट दर सबसे कम रही (1987-88 से 1993-94) उन्हीं वर्षों में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिये थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति सर्वाधिक थी। 1983 से 1987-88 और 1999-00 से 2004-05 के बीच ग़रीबी गिरावट दर ऊंची होने का मुख्य कारण यह था कि उन दिनों कृषि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धिदर मंद रही और ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक धीमी गति से बढ़ा।

ग़रीबी में कमी की दर में मुद्रास्फीति में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का भी हाथ होता है। मोटे तौर पर जिंस समूहों के थोक मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल ग़रीबी में कमी की दर और क्षेत्रीय मूल्यों के संबंधों के विश्लेषण के लिये किया जाता है। ग़रीबी में कमी की दर (सभी क्षेत्र) परोक्ष रूप से सभी जिंसों के थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी हुई है (सहसंबंध = -0.71)। लेकिन, ग़रीबी कमी दर का असर सभी जिंसों के थोक मूल्य सूचकांक पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अधिक होता है (सहसंबंध = -0.81) इसकी तुलना में शहरी इलाकों के लिये यह (सहसंबंध = -0.08) होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की ग़रीबी कमी दर में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के बीच सुदृढ़ परोक्ष संबंध से मालूम होता है कि मूल्यों में घट-बढ़ का ग्रामीण क्षेत्रों की ग़रीबी पर ज्यादा असर होता है, शहरी ग़रीबी पर कम। ग़रीबी कमी दर और थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के संबंधों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि अगर हम गैरखाद्य वस्तुओं - ईंधन, बिजली, रोशनी, चिकनाने वाले पदार्थों और तैयार औद्योगिक वस्तुओं को छोड़ दें तो स्पष्ट होगा कि मुद्रास्फीति का ग़रीबी कमी दर पर ग्रामीण क्षेत्रों में असर ज्यादा होता है (तालिका - 4)।

ग़रीबी कमी की देखी गई दर और सकल विकास एवं मुद्रास्फीति से जान पड़ता है कि जहां ग़रीबी कमी दर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत असर पड़ता है लेकिन शहरी इलाकों में सकल विकास का ऐसा ही प्रभाव होता है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति और विकास के अलग-अलग प्रभाव के संभावित कारण यह है कि ग्रामीण एवं शहरी ग़रीबों की आय में काफी अधिक अंतर है। कृषि क्षेत्र के धीमे विकास के कारण भी ग्रामीण ग़रीबी पर विकास का कम असर पड़ता है। सेवाएं हाल की आर्थिक विकास की शुरुआती चालक रही हैं और अब उद्योग भी इसकी सहायता कर रहे हैं। सेवाएं और उद्योग क्षेत्र अधिकांशत: शहर केंद्रित रहे हैं अत: ग्रामीण क्षेत्रों को हाल के आर्थिक विकास से तेज़ी से फायदा नहीं मिल पाया। मुद्रास्फीति, जिसका ग्रामीण निर्धनता पर अधिक प्रभाव पड़ता है, बढ़ गई है। ग्रामीण ग़रीबी से निपटने में आर्थिक नीतियों को एक नयी मिली-जुली नीति अपनाने को ज़रूरत है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की आय और कृषि विकास बढ़ाने पर ज़ोर देना चाहिए और सेवा तथा औद्योगिक क्षेत्रों को अपनी गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू करनी चाहिए। साथ ही, मुद्रास्फीति दर में कमी के उपाय होने चाहिए। इस संदर्भ में 11वीं योजना में कृषि विकास दर बढ़ा कर 4 प्रतिशत करने का लक्ष्य इसी दिशा में एक अच्छा कदम है और इससे ग़रीबी हटाने में मदद मिलेगी।

इस समय भारत की ग़रीबी की स्थिति के बारे में उपलब्ध विकास एवं मुद्रास्फीति प्रवृत्ति के बीच संबंधों से हमें क्या जानकारी मिलती है? ग़रीबी के बारे में अनुमानों के दो वर्ष बाद 2005-06 से 2006-07 के बीच देखी गई विकास प्रवृत्ति जहां बहुत प्रबल रही है, वहीं 2006-07 में मुद्रास्फीति दर (डब्लूपीआई और सीपीआई दोनों के आधार पर) भी काफी अधिक रही है। अब इसमें गिरावट है। अब तेज़ विकास से शहरी इलाकों में निश्चय ही ग़रीबों में कमी आएगी, यदि मुद्रास्फीति बढ़ी तो 1993-94 से 2004-05 के बीच ग्रामीण ग़रीबी में जो कमी आई है उसके लाभ खत्म हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर सरकार कृषि विकास दर बढ़ाने, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम और अन्य ग़रीबी निवारक कार्यक्रमों पर ज़ोर देती रही और ग्रामीण क्षेत्रों की आमदनी बढ़ाती रही तो इससे बढ़ती हुई क़ीमतों के कुछ दुष्प्रभाव दूर हो सकेंगे।❑

(लेखक फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एसोसिएट डायरेक्टर हैं।
ई-मेल:devendra.pant@fitchindia.com)

भारत में विकास और मुद्रास्फीति

❍ पुलाप्रे बालकृष्णन

लगभग 50 वर्ष पहले लैटिन अमरीका के आर्थिक आयोग ने एक सवाल उठाया था- आर्थिक विकास या मुद्रा स्थिरता! उन्होंने खुद ही इस प्रश्न का उत्तर भी दिया था कि यह असमंजस छद्म है। अर्थशास्त्र की दुनिया में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जो हमें यह रवैया बदलने को मज़बूर कर सके। वस्तुत: सभी अर्थव्यवस्थाओं में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दिखाए कि मुद्रास्फीति और विकास में स्पष्ट और स्थिर संबंध है। यह संबंध सशर्त है और कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है कि कोई अर्थव्यवस्था कितनी खुली है, उसमें वेतन निर्धारण किस प्रकार होता है और उत्पाद बाज़ार में किस हद तक प्रतिस्पर्धा है? यदि हम थोड़ा और व्यावहारिक ढंग से सोचें तो कह सकते हैं कि यह प्रत्यक्ष रूप से हो रहे विकास से दो प्रकार से जुड़ा हुआ है। ये हैं स्रोत और गठन। स्रोत का अर्थ है इसमें किए गए निवेश का सापेक्ष योगदान और गठन का अर्थ है कि इससे क्या मिला। आगे के अनुच्छेदों में हम इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे क्योंकि यह बात यह समझने के लिये ज़रूरी है कि इन दोनों के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं है।

हम शुरू में ही यह समझ लें कि विकास का गठन मुद्रास्फीति को किस प्रकार प्रभावित करता है। हम देख सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद की तेज़ वृद्धि दर और त्वरित विस्तारित हो रही कृषि मुद्रास्फीति को कम बढ़ावा देती है। इसका संबंध इस तथ्य से है कि भारत में आर्थिक गतिविधियां व्यय खपत के माहौल में चलाई जा रही हैं, यह बात खाद्य पदार्थों पर खासतौर से लागू होती है। कृषि मूल्यों के सूचकांक का एक प्रमुख घटक खाद्य पदार्थों के मूल्य होते हैं और यह मांग और आय वृद्धि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। इससे खाद्य पदार्थों के मूल्य में प्रत्यक्ष वृद्धि हो जाती है। अत: आर्थिक सिद्धांत में इस दृष्टिकोण के लिये कोई आधार नहीं बचता कि विकास और मुद्रास्फीति में कोई सीधा संबंध है। हालांकि यह सोच कर काफी चर्चा की जाती है कि इनमें संबंध है। अधिकांशत: ऐसा सोचने की प्रेरणा लोगों को मैक्रोइकोनॉमिक्स से मिलती है जहां मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी में संबंध दिखाने वाला फिलिप्स कर्व प्रमुख घटक माना जाता है। विकास और बेरोज़गारी के बीच संबंध प्रच्छन्न है। फिलिप्स क़र्व को यह पता लगाने के एक दशक के अंदर ब्रिटेन से गायब हो जाना चाहिए था कि वहां बेरोज़गारी और वेतन परिवर्तन संबंधी क़रीब एक शताब्दी के आंकड़े उपलब्ध हैं। 70 के दशक में यह साबित किया गया था कि कम से कम ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में ऐसा कोई संबंध नहीं था और संभवत: अमरीका के बारे में भी बस यही कहा जा सकता है क्योंकि इन्हीं दोनों अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता रहा है। यह भी संभव है कि पहले इन दोनों में कोई संबंध रहा हो और 70 के दशक में तेल मूल्य वृद्धि के पहले यह संबंध टूट गया हो। मुद्रास्फीति के सिद्धांत के साथ अध्ययन करने के लिये पूर्ति आघात नये मैक्रोइकोनॉमिक्स में एक नया आयाम था। फिलिप्स कर्व का संदर्भ सिर्फ़ यह बताने के लिये दिया गया कि मुद्रास्फीति और विकास के बीच किसी स्थिर संबंध की परिकल्पना ख़तरनाक हो सकती है। हम उस स्थिति की बात कहते हैं जो इस समय भारत में मौजूद हैं।

जहां यह स्वीकार किया जा रहा है कि इस समय अर्थव्यवस्था का विकास तेज़ी से हो रहा है, यह भी ज़रूरी है कि इस तेज़ी के कारण पर ध्यान दिया जाए। भारत में इस समय निर्माता क्षेत्र में निवेश का तेज़ क्रम चल रहा है। पिछले एक दशक से ज्यादा अरसे से यहां के सेवा क्षेत्र में तेज़ी जारी थी और इसका उस सकल घरेलू उत्पाद में साफ़ असर दिखाई दे रहा जो इस वक़्त जारी है। अब हम निर्माता क्षेत्र में ऐसी तेज़ी देख रहे हैं जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। यह अच्छी बात है, क्योंकि हम मानते हैं कि निर्माता क्षेत्र ही अकुशल श्रमिकों को रोज़गार के अवसर प्रदान कर सकता है जिसकी अधिकांश देश को ज़रूरत है। लेकिन निर्माता क्षेत्र के तेज़ विकास की ख़बर के साथ ही यह ख़बर भी आ रही है कि मुद्रास्फीति दर बढ़ रही है। इस समय यह 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष के आसपास है। इसे कुछ क्षेत्रों में अधिक गर्माहट कहा जाता है। इसे मैं सिद्धांत रूप में और नीति के रूप में भी सहायक नहीं मानता। जैसा कि मैंने इस लेख के शुरू में ही कहा है, अगर

निर्माता क्षेत्र की तरह कृषि की वृद्धिदर तेज़ होती तो हमारी विकास दर सिर्फ़ और तेज़ ही नहीं होती बल्कि मुद्रास्फीति दर भी वर्तमान दर से काफी कम होती। इस बात का भी महत्व होता है कि विकास में किस-किस घटक का योगदान है। मुद्रास्फीति की कई दरें ऐसी हैं जो सकल घरेलू उत्पाद की एक ही दर के साथ चल सकती हैं। एक बार यह बात मान लें, हम पाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि एक सीमा के बाद की वृद्धिदर मुद्रास्फीतिकारी है। पानी के उबलने के तापमान स्तर की तरह हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि इस सीमा के बाद की वृद्धिदर 'अत्यधिक गर्माहट' के कारण है।

अब हम सीधे उस बात पर आते हैं जो भारत में समस्या की जड़ बनी हुई है। 1990 के बाद से हमारे यहां खेती की विकास दर भिन्न-भिन्न रही है। कई वर्ष में यह काफी ज्यादा तो कई में यह औसत रही है। इस परिधि के अंदर हम कई विकृतियों की ओर इशारा कर सकते हैं। पिछले तीन महीने से मुद्रास्फीति का जो क्रम रहा है उससे कृषि क्षेत्र में कमज़ोरी के संकेत मिलते हैं। मुद्रास्फीति खाद्य पदार्थों की क़ीमतें बढ़ने के चलते बढ़ी। खासतौर से सब्ज़ियां महंगी हुईं। हालांकि अतीत में भी प्याज की क़ीमतों को लेकर जब तक आशंकाएं उभरती रही हैं, सब्जियों की क़ीमतों में लगातार बढ़ोतरी हमारे लिये नयी बात है। 80 के दशक तक मुद्रास्फीति ज्यादातर अनाज की क़ीमतों के कारण बढ़ती थी। इस परिवर्तन से एक मौसम परिवार की क्रय शक्ति का संकेत मिलता है। यह भी कि पहले खाद्य पदार्थों की खपत में अनाज़ों का प्रमुख स्थान होता था। इसके पहले कि हम मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपायों पर नीतिगत उपायों की चर्चा करें, और उन उपायों पर नज़र डालें जिन्हें मौजूदा संदर्भ में लागू किया गया है, निम्नलिखित गुण-दोष नज़र में आए हैं। पिछले 50 वर्षों के सुनियोजित विकास के बाद भी हमें आज खाद्य मोर्चे पर अभावों से जूझना पड़ रहा है। 1991 से क़रीब डेढ़ दशक बाद अब हम आराम से यह मान सकते हैं कि व्यापार, उद्योग और मैक्रोइकोनॉमिक नीतियों के क्षेत्र में हमने जिन सुधारों को लागू किया वे काफी नहीं थे। कृषि विकास पर जम कर ध्यान देने की ज़रूरत है।

जब उन कारकों की बात आती है जिनके जरिये मुद्रास्फीति का सामना करना होता है, तो इनमें उत्पादकता वृद्धि का विशेष स्थान होता है। भले ही इसका असर स्थायी होता हो, लेकिन यहां पर हम जिस उत्पादकता की बात कर रहे हैं वह श्रम उत्पादकता है। इसमें वृद्धि का अनूठा निहित परिणाम यह होता है कि बिना मूल्य वृद्धि को बढ़ावा दिए इसके कारण वेतन और लाभ में बढ़ोतरी होती है। दरअसल उत्पादक वृद्धि से क़ीमतों की वृद्धि रोकने में मदद मिल सकती है। सभी मुद्रास्फीति रोधी उपायों में यही बात इसे अनूठा बनाती है। अब तक की गई हमारी चर्चा के अनुसार, यह भी कहा जा सकता है कि उत्पादकता में वृद्धि की संभावना इस सुझाव को बेकार ठहरा देती है कि विकास और मुद्रास्फीति में निश्चय ही सीधा संबंध है। जहां विकास उत्पादकता वृद्धि के कारण होता है, वहीं आखिरकार यह मुद्रास्फीति रोधी साबित हो सकता है। अब विकास मुद्रास्फीति का इलाज़ बन गया है। यही बात ध्यान में रख कर मैंने शुरू में यह सवाल उठाया था कि क्या विकास के कारण मुद्रास्फीति पैदा होती है? यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि विकास का स्रोत क्या है? ध्यान देने लायक है कि इस मामले में विकास पूरी तरह उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से आया है। वैसे भी मुद्रास्फीति शून्यता विशुद्ध हितकारी नहीं होती।

अब हम मुद्रास्फीति रोधी उपाय के रूप में मुद्रा नीति की भूमिका की बात करें। हालांकि मुद्रानीति का उद्देश्य मुद्रावृद्धि की दर में कमी लाना होता है, यह काम ब्याज दर बढ़ा कर किया जा सकता है। मुद्रास्फीति को राजकोषीय नीति से घटाने की कोशिशें समयसाध्य और दुरूह होती हैं। ब्याज दर को वित्तपोषण की लागत माना जाता है, इसके जरिये निवेश व्यय पर रोक लगनी चाहिए और परिणाम होना चाहिए विकास। लेकिन कुछ मामलों में तो यह मूल्य वृद्धि रोकने में भी कामयाब नहीं होता। यह श्रमिकों द्वारा पारिश्रमिक एवं लागत एवं मूल्य की मौजूदगी के कारण होता है। इस प्रकार के परिदृश्य की उम्मीद औद्योगिक क्षेत्र में की जा सकती है और यह बात भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में खासतौर से मौजूद है। अब जहां वित्त की बढ़ती लागत निवेश परिव्यय और विकास अवरोध पर लगाम लगा सकता है, यह मुद्रास्फीति रोकने में अधिक सफल नहीं हो पाएगा। लागत-आधारित मूल्यों और मज़दूरी मोलभाव की मौजूदगी के कारण अर्थव्यवस्था में ठहराव आ सकता है। परंपरागत मैक्रोइकोनॉमिक नीति दायरों से बाहर यह बहुत पहले से माना जाता रहा है कि किसी प्रकार की 'आय नीति' मुद्रास्फीति को नीचे रखने में सहायक होती है। आय नीति वेतन एवं मूल्यों में वृद्धि को सीमा में रखने का काम करती है और इनकी वृद्धि पर अंकुश रखती है। इसके लिये ऐसी अवस्था की ज़रूरत होती है जो आर्थिक हितों के अनुकूल होती है। मांगजनित मूल्यों की उपस्थिति में (जैसा कि कृषि उपज और खासतौर पर अनाज के मामले में होती है) मुद्रानीति सिर्फ़ इस रूप में मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने का काम करती है कि वह मांग घटाने में सहायक होती है। यदि खपत के स्तर समान रूप से अधिक नहीं होते, तो यह कल्याणकारी दृष्टिकोण से देखने पर कुशल नीति नहीं कही जा सकती। मुद्रास्फीति के संदर्भ में मैंने अन्यत्र मुद्रानीति के विकल्पों का अध्ययन किया है और पाया है कि ये महत्वहीन हैं।

किसी खुली अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति प्रबंधन के लिये व्यापार एक और विकल्प पेश करता है। वह यह कि पूर्ति में वृद्धि की जाए। यह ऐसी हालत में अधिक प्रभावी होती है जब मांग-निर्धारित मूल्यों के बीच किसी जिंस की पूर्ति कम हो। आज भारत

सरकार कुछ महत्वपूर्ण उत्पादों पर आयात शुल्क घटा कर कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रही है। भारत में ऐसे भी अवसर आए हैं जब 50 और 60 के दशकों में आयात का मूल्यों पर ज़बरदस्त असर रहा है। उस समय अमरीका से आयात किया हुआ पीएल480 गेहूं घरेलू कमी दूर करने के लिये बेचा जाता था। उस समय भारत में जो कुछ हुआ और आज जो हो रहा है उसमें थोड़ा-सा अंतर है। अनाज के आयात का असर तब पड़ेगा जब आयातित माल मंडियों में पहुंचने पर वह वहां बिक रहे माल से सस्ता पड़े।

यह स्पष्ट नहीं है कि इस समय जिन चीजों के कारण मुद्रास्फीति बढ़ रही है उनके बारे में यह बात लागू होती है या नहीं। पीएल480 आयात के समय यह शर्त लागू नहीं होती थी क्योंकि यह आयात तब अमरीकी सरकार के ख़र्चे पर किया जा रहा था। इसी कारण यह अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं डालता था। इसीलिये जहां मुद्रास्फीति पर लगाम कसने के लिये आयात ज़रूरी है, वहीं भारत में इस समय की मुद्रास्फीति देश के लिये अधिक गतिशील खाद्य क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करती है। स्थिर मूल्य पर खाद्य उत्पादन बढ़ाने की चुनौतियां महत्वहीन नहीं हैं लेकिन वे ऐसी भी नहीं हैं कि उनका सामना करना असंभव हो। ❑

(लेखक भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझिकोड में प्रोफेसर हैं।
ई-मेल : pbkfishnan@yahoo.com)

समाचार

अर्थव्यवस्था की छलांग, महंगाई पर लगाम

जीडीपी वृद्धिदर 9.3 फीसदी, मुद्रास्फीति चार फीसदी से नीचे आई

देश के आर्थिक विकास की गाड़ी सरपट दौड़ रही है। चालू वित्त की पहली तिमाही में जीडीपी विकास दर 9.3 फीसदी दर्ज़ की गई। दूसरी ओर, मुद्रास्फीति की दर पंद्रह महीने के निम्न स्तर यानी चार फीसदी से नीचे आ गई है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि देश की विकास दर आगामी तिमाही में थोड़ी धीमी पड़ सकती है।

आर्थिक विकास की तेज़ी के पीछे उत्पादन, निर्माण और सेवा क्षेत्र की मुख्य भूमिका रही और समीक्षा अवधि में कृषि क्षेत्र ने क़रीब चार फीसदी की दर से विकास किया। उल्लेखनीय है कि बीते वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 9.4 फीसदी रही जो अट्ठारह साल में सबसे तेज़ थी। उधर, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और रिज़र्व बैंक के वित्तीय उपायों के चलते महंगाई की दर पर काफी हद तक लगाम लग गई है जिससे 18 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर घटकर 3.94 फीसदी पर आ गई। पंद्रह महीने में मुद्रास्फीति की यह न्यूनतम दर है। यद्यपि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 9.3 फीसदी की जीडीपी विकास दर बीते वित्त वर्ष की समान अवधि की 9.6 फीसदी के मुक़ाबले कम है, लेकिन शेयर बाज़ार में जीडीपी विकास दर के आंकड़ों को लेकर उत्साह देखा गया। वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि यद्यपि पहली तिमाही के दौरान 9.3 फीसदी के जीडीपी विकास का अस्थायी अनुमान बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि के मुक़ाबले थोड़ा कम है, लेकिन बाहरी परिस्थितियों को देखते हुए यह संतोषजनक है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने कहा कि सभी ने विकास दर में गिरावट की संभावना जताई थी। रिज़र्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिये साढ़े आठ फीसदी की विकास दर का अनुमान जताया है। इस तरह से 9.3 फीसदी की विकास दर अच्छी कही जाएगी। हालांकि कुछ विश्लेषकों, जैसे एचडीएफसी के मुख्य अर्थशास्त्री अभीक बरुआ ने चिदंबरम के विचार से असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि आने वाली तिमाहियों में विकास की रफ़्तार धीमी होगी।

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीती तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की विकास दर 11.9 फीसदी रही, जबकि वर्ष 2006-07 की पहली तिमाही में इस क्षेत्र की विकास दर 12.3 फीसदी थी। वहीं समीक्षा अवधि में कृषि क्षेत्र की विकास दर बीते वित्त वर्ष की समान अवधि के 2.8 फीसदी के मुक़ाबले बढ़कर 3.8 फीसदी रही। बीती तिमाही में व्यापार, होटल, परिवहन और संचार क्षेत्र ने बारह फीसदी की विकास दर हासिल की। जबकि वित्त, बीमा और रीयल एस्टेट क्षेत्र ने 11 फीसदी की रफ़्तार से विकास किया। श्री चिदंबरम ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि इस साल जीडीपी विकास दर नौ फीसदी के क़रीब रहेगी। इधर, सब्जी और फल जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं में तेज़ी के बावजूद मुद्रास्फीति की दर 18 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में घटकर पंद्रह महीने के निम्न स्तर 3.94 फीसदी पर आ गई। यह स्तर चालू वित्त वर्ष के लिये रिज़र्व बैंक के अनुमान से काफी कम है। इससे पूर्व सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर 4.10 फीसदी पर थी। समीक्षा अवधि में थोक मूल्य सूचकांक 0.1 फीसदी बढ़कर 213.6 अंक पर पहुंच गया। इस दौरान मसूर की क़ीमत में दो फीसदी, बाजरा और चना प्रत्येक में एक फीसदी, सब्ज़ियों में 1.3 फीसदी, फलों में 0.6 फीसदी और दूध की क़ीमत में एक फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज़ की गई। ❑

IAS / PCS-2008-09 हेतु कक्षाएं प्रारंभ

लोक प्रशासन

द्वारा **अनिल सिंह**

(एक मात्र टीचर जिन्हें प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों पर समानरूप से दक्षता प्राप्त)

लोक प्रशासन विषय ही क्यों?

- ★ एक मात्र Job Oriented Subject
- ★ सर्वाधिक छोटा पाठ्यक्रम - प्री. एवं मेंस का एक ही सलेबस।
- ★ किसी पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं।
- ★ आर्ट्स एवं साइंस दोनों वर्गों के अभ्यर्थियों हेतु समानरूप से उपयोगी।
- ★ अत्यंत व्यावहारिक विषय, दिन-प्रतिदिन की घटनाओं से संबंधित, अतः अत्यंत रूचिकर।
- ★ आप IAS बनना चाहते हैं। IAS, IPS के Role क्या हैं? आदि के बारे में जानकारी इसी विषय से प्राप्त होती है।
- ★ चयनित अध्ययन की अपार संभावनाएं।
- ★ हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों हेतु अत्यंत अंकदायी विषय।
- ★ Fringe Benefits-सामान्य अध्ययन में 180+ अंक का योगदान
  - (1-2) निबंध
  - साक्षात्कार में अत्यंत सहायक 80% प्रश्न इसी विषय से संबंधित पूँछे जाते हैं।

इस वर्ष हमारे संस्थान से Public Admn. में (हिन्दी माध्यम से) प्राप्त अंक
RAVI SINGH - 378 (196/182) • VIKASH SINGH - 371 (190, 181)

विगत वर्ष **Public Admn.** में (हिन्दी माध्यम से) प्राप्त अंक
- A.P. SINGH - 392 (195 + 197)
- O.P. GUPTA - 345
- R.K. SINGH - 339 (180 + 159)

इस वर्ष (P.T.) में Cut Off रहा - Pub. Ad. 64⁺ G.S.-70 Score-230⁺ (सामान्य वर्ग)

- ★ प्री. एवं मेंस हेतु अलग-अलग कक्षाओं का आयोजन।
- ★ Question Practice पर अत्यधिक बल।
- ★ सारगर्भित अध्ययन सामग्री।

मेंस की कक्षा अवधि - 2½ माह

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध

हिन्दी साहित्य

द्वारा **उमेश शुक्ला**

(5 वर्ष का अध्यापन-अनुभव)

- ★ उमेश शुक्ला के कुशल मार्गदर्शन में 3-4 माह में 350+ अंक लाना संभव
- ★ साहित्यिक एवं गैर साहित्यिक पृष्ठभूमि दोनों वर्गों अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत रूचिकर एवं अंकदायी विषय।
- ★ चयनित अध्ययन संभव परीक्षा के समय 40% पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सफलता अर्जित कर सकते हैं।
- ★ प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्यतः 180-200 अंक तक प्राप्त किये जा सकते हैं बशर्ते कि तैयारी वैज्ञानिक रीति से की जाए। यह प्रश्न पत्र अत्यधिक अंकदायी है।
- ★ द्वितीय प्रश्न पत्र साहित्यिक दृष्टिकोण नहीं बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से लिखे जाने की माँग करता है। ऐसा होने पर 150-170 अंक आसानी से इस पेपर में आ जाते हैं। इस प्रश्न पत्र में विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जिसे अध्यापक एवं विद्यार्थी के निकट संपर्क द्वारा ही विकसित किया जा सकता है। एक अध्यापक ही नहीं बल्कि मित्र एवं मार्गदर्शक की तरह भी, एक टीचर को होना चाहिए।
- ★ नियमित रूप से प्रश्नोत्तरों के मूल्यांकन की व्यवस्था।
- ★ विगत वर्षों में पूछे गये प्रश्नों पर परिचर्चा एवं आदर्श उत्तर-लेखन।
- ★ मित्रवत् वातावरण जिसमें आप निःसंकोच अपनी समस्याओं को सर के समक्ष रख सकते हैं।

मुख्य परीक्षा हेतु कक्षाएं प्रारंभ
10 अक्तूबर एवं 20 नवम्बर ★ समयावधि-3½ माह

लोक प्रशासन से

★प्रीलिम्स 100% गारंटी, अन्यथा पूरी फीस वापस (यदि G.S.&70⁺)
★मात्र 4 पुस्तकों का अध्ययन। शेष समय G.S. पर दें।

समयावधि-4 माह ★ कक्षाएं सप्ताह में 4 दिन

प्रीलिम्स हेतु
- **1st बैच : 7 अक्तूबर** (बैच समाप्त होने की तिथि: 15 फरवरी'08)
- **2nd बैच : 20 नवम्बर** (बैच समाप्त होने की तिथि: 25 मार्च'08)

NEW VISION IAS ACADEMY

303, Top Floor, A-29/30, Jaina House, Mukherjee Nagar, Delhi-9 Cell.: 9891147383, 9871142602

YH-10/07/11

मुद्रा प्रसार : कारण और समाधान

○ सी.एम. चौधरी

मुद्रा प्रसार वह स्थिति है जिसके अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में अधिक मुद्रा की पूर्ति होती है जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग अधिक होने से क़ीमतों में निरंतर वृद्धि होती है। इससे मुद्रा का मूल्य घटता है तथा महंगाई में वृद्धि होती है।

प्रोफेसर क्राउपर ने मुद्रास्फीति की परिभाषा देते हुए कहा है कि यह वह स्थिति है जिसके अंतर्गत क़ीमतों में वृद्धि होती है अर्थात मुद्रा का मूल्य घटता है। प्रोफेसर ए. सी. पीगू के अनुसार, जब मौद्रिक आय अर्जित क्रियाओं की तुलना में अधिक बढ़ती है, मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होती है।

इस प्रकार मुद्रास्फीति वस्तुओं तथा सेवाओं की क़ीमतों में निरंतर वृद्धि की ओर इंगित करती है जिससे मुद्रा का मूल्य घटता है तथा मध्यम एवं निम्न आय वर्ग को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

मुद्रास्फीति के कारण

मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न करने वाले दो प्रमुख घटक हैं जो निम्नांकित हैं :

- मौद्रिक आय में वृद्धि करने वाले घटक
- वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति में कमी करने वाले घटक

मौद्रिक आय में वृद्धि करने वाले घटक

मुद्रास्फीति जब लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है, तब उत्पन्न होती है। मौद्रिक आय में वृद्धि निम्न घटकों से प्रभावित होती है :

- **सार्वजनिक व्यय में वृद्धि :** विकासात्मक एवं गैर-विकासात्मक व्ययों में वृद्धि आर्थिक नियोजन के अंतर्गत होती है। प्रतिरक्षा व्यय में वृद्धि होती है। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग बढ़ने से क़ीमतें निरंतर बढ़ती हैं।
- **निजी व्यय में वृद्धि :** निजी व्यय निजी उपभोग तथा निजी निवेश के कारण बढ़ता है जिससे अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग बढ़ने से क़ीमतें बढ़ती हैं। व्यावसायिक दशाएं अनुकूल होने पर निवेशकर्ता नये-नये निवेश करते हैं जिससे उत्पादन के साधनों की मांग बढ़ती है, उनकी क़ीमतें बढ़ती हैं जिससे सामान्य क़ीमत स्तर भी बढ़ता है। वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग बढ़ने से इनकी क़ीमतें बढ़ती हैं।
- **निर्यातों में वृद्धि :** देश के उत्पादों की विदेशी बाज़ार में मांग के कारण निर्यात बढ़ते हैं और इससे घरेलू बाज़ार में इन वस्तुओं का स्टॉक कम होने के क़ीमतें बढ़ती हैं।
- **करों में छूट :** जब देश में सरकार सरलीकरण एवं विवेकीकरण के आधार पर करारोपण में कमी करती है तो लोगों की मौद्रिक आय बढ़ती है जिससे वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग बढ़ती है और मुद्रा प्रसार उत्पन्न हो जाता है।
- **सरकार द्वारा आंतरिक ऋणों की अदायगी :** जब सरकार आंतरिक ऋणों की अदायगी करती है तो लोगों की क्रय शामिल बढ़ती है जिसका उपयोग वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीदारी में किया जाता है। इससे मुद्रा स्फीति हो जाती है।
- **जनसंख्या में वृद्धि :** देश में जनसंख्या की निरंतर वृद्धि से वस्तुओं तथा सेवाओं की प्रभावी मांग में वृद्धि होती है जिसके परिणाम स्वरूप क़ीमतों में निरंतर वृद्धि होती है।
- **आसान ऋण की उपलब्धता :** विगत वर्षों में बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा साख की आपूर्ति आसान कर देने से लोगों द्वारा उपभोक्ता ऋण, कार ऋण, आवास ऋण लिये जा रहे हैं। इससे लोगों की मौद्रिक आय बढ़ने से वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग बढ़ी है और क़ीमतें निरंतर बढ़ी हैं। यह प्रदर्शनकारी प्रभाव का भी परिणाम है।

वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति कम करने वाले घटक : जब देश में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति घट जाती है तो इससे भी क़ीमतें बढ़ती हैं। यह निम्न तत्वों के कारण होती है :

- **उत्पादन के साधनों की कमी :** जब देश में उत्पादन के साधनों की कमी पूंजी, श्रम, कच्चा माल, शक्ति के कारण आती है तो वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति कम हो जाती है। इससे क़ीमतें बढ़ने लगती हैं।
- **कालाबाज़ारी और जमाखोरी की प्रवृत्ति :** जब देश में वस्तुओं तथा सेवाओं की कमी होती है और क़ीमतें बढ़ती हैं तो व्यापारी वर्ग वस्तुओं का अधिक संग्रह करते हैं तथा इनका कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर दिया जाता है। इससे पुन: क़ीमतें बढ़ने लगती हैं।
- **उपभोक्ताओं की संग्रह प्रवृत्ति :** क़ीमतों में वृद्धि होने पर उपभोक्ता भी वस्तुओं तथा सेवाओं का संग्रह करने लगते हैं जिससे इनकी आपूर्ति कम हो जाती है।

● **प्राकृतिक कारण :** भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। अतिवृष्टि, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, मौसम की ख़राबी आदि के कारण कृषि उत्पादन कम होता है। गेहूं, दालें, तिलहन, आलू, प्याज आदि की क़ीमतें निरंतर बढ़ने लगती हैं। कृषि पर आधारित उद्योगों - जूट, सूती वस्त्र, चीनी एवं तेल आदि का उत्पादन भी कम होता है। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है।

● **उत्पादन लागत में वृद्धि :** मज़दूरी में वृद्धि, उत्पादन करों में वृद्धि तथा लाभ में वृद्धि के कारण वस्तुओं की क़ीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा स्फीति उत्पन्न हो जाती है। उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है।

मुद्रास्फीति का समाधान

एक सीमा तक क़ीमतों में वृद्धि आर्थिक क्रियाओं - उत्पादन, निवेश, रोज़गार तथा विकास को प्रोत्साहन देती है लेकिन एक सीमा के पश्चात इस समस्या का दूरगामी प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों तथा समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आय के अधिक होने से असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत में विगत दो वर्षों की तुलना में मुद्रास्फीति बढ़कर 6.73 प्रतिशत की दर पर पहुंच चुकी है। दैनिक वस्तुओं तथा सेवाओं के भाव आसमान छू रहे हैं। मध्यम एवं निम्न आय वर्ग को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति की समस्या का समाधान तीन प्रमुख उपायों को अपनाकर किया जा सकता है। ये हैं :

(1) मौद्रिक उपाय

(2) राजकोषीय उपाय

(3) प्रत्यक्ष भौतिक नियंत्रण उपाय

मौद्रिक उपाय

सरकार मौद्रिक नीति के माध्यम से महंगी मुद्रानीति अपनाकर मौद्रिक आय में कमी करके बढ़ती क़ीमतों पर अंकुश लगा सकती है। ये उपाय निम्नवत हैं:

● **बैंक दर में वृद्धि :** देश के केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि करके ऋण साख को महंगा कर दिया जाता है। इससे व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण शक्ति कम हो जाती है तथा विभिन्न वर्गों एवं क्षेत्रों को साख व ऋण ऊंची ब्याज दर पर मिलने से वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग पर अंकुश लगता है। वर्तमान में भारत में बैंक दर 6 प्रतिशत वार्षिक है।

● **नकद कोषानुपात (सीआरआर) :** इससे व्यापारिक बैंकों को अपने मांग एवं आवधिक जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। इसमें वृद्धि करके साख सृजन की व्यापारिक बैंकों की क्षमता को कम किया जाता है जिससे बढ़ती क़ीमतों पर अंकुश लगता है। विगत दिनों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने

IAS PCS

JIGISHA
IAS ACADEMY
by J.P. SINGH

प्रिय भावी प्रशासको

आई.ए.एस.2008 की परीक्षा के लिए सजगता का समय आ चुका है। यही वह समय है, जब आपको कुशल रणनीति एवं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी आरम्भ कर देनी चाहिए।

सफलता की चाहत सभी में होती है, किन्तु सफलता के लिए आवश्यक है:-

1. कुशल रणनीति एवं कठिन परिश्रम का बेहतर समन्वय।
2. पाठ्यक्रम के निरंतरता एवं परिवर्तन के पहलुओं की अन्तः विषयी दृष्टिकोण के आधार पर बेहतर समझ।
3. समयबद्ध प्रबन्धन।
4. टॉपिक के केन्द्रीय महत्व के तथ्यों की समझ जो कि प्रारम्भिक परीक्षा की विषयवस्तु है।
5. उन केन्द्रीय महत्व के तथ्यों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संदर्भों में महत्व, समस्या एवं समाधान की बेहतर समझ जो कि मुख्य परीक्षा की विषय वस्तु है।

अतः केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है बल्कि **"ज्ञान के अनुप्रयोग" का कौशल** निर्णायक होता है।

हम आपकी सफलता के मार्ग को अपने बेहतर अनुभव के आधार पर अधिक सहज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ..... आपकी भावी शानदार सफलता के लिए। .....**अनन्त शुभकामनाओं के साथ**

जे.पी. सिंह

लोक प्रशासन
द्वारा जे.पी. सिंह

निःशुल्क कार्यशाला के साथ
बैच प्रारम्भ
16 अक्टूबर, सांय 5.30 बजे
एवं 1 नवम्बर, दोपहर 12.30 बजे

सामान्य अध्ययन
द्वारा जे.पी. सिंह एवं टीम

निःशुल्क कार्यशाला के साथ
बैच प्रारम्भ
16 अक्टूबर, सांय 3 बजे
और 1 नवम्बर, सांय 3 बजे

at Mukherjee Nagar, New Delhi
9810569158, 9911668047

YH-10/07/13

इस दर को 5.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। इससे अर्थव्यवस्था में 14,000 करोड़ रुपये पर अंकुश लगेगा जिससे मांग पर दबाव कम होगा।

- **वैधानिक तरलानुपात (एसएलआर) :** केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को रोकने के लिये इसमें वृद्धि करता है। प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपने कुल जमाओं का एक हिस्सा निवेश करना अनिवार्य है जो तरलतम हो। इससे व्यापारिक बैंकों की साख सृजन क्षमता पर अंकुश लगाया जाता है। भारत में वर्तमान में वैधानिक तरलानुपात कुल जमाओं का 25 प्रतिशत रखना अनिवार्य है।
- **सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय :** केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति रोकने के लिये सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करता है जिससे लोगों की मौद्रिक क्रय शक्ति कम हो जाती है। वस्तुओं तथा सेवाओं की बढ़ती मांग कम होती है।
- **उपभोक्ता ऋण की राशनिंग :** बढ़ती क़ीमतों पर अंकुश लगाने के लिये केंद्रीय बैंक आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के लिये ऋण की आपूर्ति पर अंकुश लगाता है। आवश्यक वस्तुओं के क्रय हेतु ऋण की राशनिंग की जाती है। कम एवं आसान ऋण न मिलने से वस्तुओं तथा सेवाओं की बढ़ती क़ीमतों पर अंकुश लगता है।

(6) साख सीमांतर में वृद्धि : व्यापारी वर्ग द्वारा व्यापारिक बैंकों से अपनी वस्तुओं के स्टॉक के आधार पर ऋण लिया जाता है। इस स्टॉक पर रिज़र्व बैंक साख सीमांतर निर्धारित करता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में रिज़र्व बैंक इस साख सीमांतर में वृद्धि कर देता है जिससे व्यापारियों की उधार लेने की क्षमता कम हो जाती है और वे आवश्यक वस्तुओं का अनावश्यक संग्रह करने में सफल नहीं होते हैं।

राजकोषीय उपाय

इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण एवं वित्तीय प्रबंध जैसे उपकरणों के माध्यम से बढ़ती क़ीमतों पर अंकुश लगाती है जो निम्न हैं :

- **सार्वजनिक व्यय में कमी :** बढ़ती हुई क़ीमतों पर अंकुश लगाने के सार्वजनिक व्यय में कमी आती है जिससे वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग कम होती है। इसके लिये सरकार प्रशासन में मितव्ययिता तथा फ़िज़ूलख़र्ची पर अंकुश लगाकर मुद्रास्फीति को रोकती है।
- **करारोपण में वृद्धि :** प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करों में वृद्धि करके व्यय योग्य आय में कमी की जा सकती है जिससे वस्तुओं तथा सेवाओं की बढ़ती मांग पर अंकुश लगाया जा सकता है। आयात करों में छूट देकर वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है और बढ़ती क़ीमतें कम की जा सकती हैं। निर्यात कर बढ़ाकर निर्यात को हतोत्साहित करके देश में वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है।
- **सार्वजनिक ऋण :** सरकार आंतरिक ऋण में वृद्धि करके लोगों की अतिरिक्त मौद्रिक आय कम कर सकती है। वह ऐच्छिक एवं अनिवार्य कदम उठाकर जनता से ऋण ले सकती है जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग में वृद्धि पर अंकुश लगाया जा सकता है।
- **अधिमूल्यन:** इसके अंतर्गत सरकार देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में वृद्धि करती है जिसके परिणामस्वरूप निर्यात महंगे तथा आयात सस्ते हो जाते हैं। महंगा होने से निर्यात घटेंगे और घरेलू बाज़ार में वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा बढ़ेगी। आयात सस्ते होने विदेशों से आसानी से वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होने से बढ़ती क़ीमतों पर अंकुश लगेगा।

प्रत्यक्ष भौतिक नियंत्रण उपाय

मुद्रास्फीति को रोकने के लिये प्रत्यक्ष भौतिक नियंत्रण उपाय काम में लाए जा सकते हैं। ये निम्न हैं :

- **मूल्य नियंत्रण एवं राशनिंग :** मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये मूल्य नियंत्रण एवं राशनिंग के उपाय भी किए जाते हैं। विगत दिनों में पेट्रोल के मूल्य में 2 रुपये तथा डीज़ल के मूल्य में 1 रुपये प्रतिलीटर कमी की गई। इससे यातायात लागत में बढ़त को कम किया जा सकेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुलभ कराकर बढ़ती क़ीमतों पर अंकुश लगाया जा सकता है। आधिक्य क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र में वस्तुओं तथा सेवाओं के स्वतंत्र गमन पर छूट देकर मुद्रास्फीति को नियमित किया जा सकता है। राशनिंग के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उचित क़ीमत पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं।
- **आयात करना :** जिन वस्तुओं की कमी है उनका आयात करके बढ़ती क़ीमतों पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस वर्ष देश में गेहूं का आयात किया गया है।
- **निर्यात पर प्रतिबंध :** विगत दिनों में भारत सरकार ने गेहूं तथा इससे संबंधित उत्पादों के निर्यात पर रोक लगा दी है। इससे देश में बढ़ती क़ीमतें रोकने में मदद मिलेगी।
- **उत्पादन में वृद्धि :** बेकार पड़ी उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करके उत्पादन मात्रा में वृद्धि होगी। बढ़ती हुई क़ीमतें रोकी जा सकेंगी। खाद्यान्न, आवास, कपड़ा तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिये और अधिक संसाधनों का आवंटन करके इनकी आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है। उदार आयात नीति के माध्यम से घरेलू वस्तुओं की कमी को दूर किया जा सकता है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिये मौद्रिक, राजकोषीय एवं प्रत्यक्ष भौतिक नियंत्रण उपायों को एक साथ लागू करने से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके लिये अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कदम उठाने पड़ेंगे जिसके लिये दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, सुदृढ़ प्रशासन तंत्र तथा जनसहयोग आवश्यक है। ❑

(लेखक आर्थिक प्रशासन एवं प्रबंधन विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में अवकाश प्राप्त प्रोफेसर रह चुके हैं)

सकल घरेलू उत्पाद क्या है?

सकल घरेलू उत्पाद (सघउ) अर्थव्यवस्था के आकलन का एक तरीका है। इसे अंग्रेज़ी के संक्षिप्त नाम 'जीडीपी' से भी जानते हैं। यह देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर निश्चित समय में सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन मूल्य से परिभाषित होता है। किसी वस्तु के अंतवर्ती स्वरूप को इसमें शामिल नहीं किया जाता। इससे पुन: गणना की संभावना समाप्त हो जाती है। सघउ में पूंजी स्टॉक का अवमूल्यन शमिल नहीं होता। सघउ से अवमूल्यन घटा देने से शुद्ध घरेलू उत्पाद (जीडीपी) प्राप्त होता है।

जीडीपी आकलन की विभिन्न विधियां क्या हैं?

जीडीपी आकलन का सबसे प्रचलित और सामान्य तरीका व्यय विधि है। इस विधि में जीडीपी ख़पत, व्यय, सरकारी ख़र्च और शुद्ध निर्यात (कुल निर्यात - कुल आयात) का कुल योग होता है। इसके अंतर्गत सामान्य खपत-व्यय, निजी-खपत और सरकारी ख़र्च में विभाजित होती है। निजी खपत के अंतगर्त, घरेलू सामग्री पर ख़र्च, खाद्य, भाड़ा, इलाज ख़र्च जैसे व्यय शामिल हैं। सरकारी ख़र्च में सरकारी कर्मचारियों का वेतन, सेना के लिये हथियारों की ख़रीद आदि शामिल हैं। इसमें कोई भी हस्तांतरित भुगतान, जैसे कि बेरोज़गारी लाभ शामिल नहीं है। निवेश-व्यय में उत्पादक व्यावहारिक पूंजी जैसे - संयंत्र और उपकरण खरीद, संपत्ति सूची में बदलाव शामिल हैं।

शुद्ध निर्यात का अर्थ हुआ, विदेशों में ख़पत के लिये देश में तैयार वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में से विदेशों में घरेलू ख़पत के लिये पैदा हुई वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घटाने से प्राप्त मूल्य।

जीडीपी का दूसरा आशय आमदनी से जुड़ा हुआ है। इस विधि में आकलन के लिये किए गए कार्यों में मज़दूरों द्वारा कमाई गई राशि का कुल योग, व्यापार से हुए लाभ का योग और ज़मीन के किराये से प्राप्त आमदनी को मिलाकर मूल्य निकालते हैं।

तीसरा मूल्यवर्धित तरीका है। इस विधि में जीडीपी का अंक हासिल करने के लिये अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, और वस्तुओं के वर्धित मूल्य को जोड़ दिया जाता है। अंतिम रूप से प्राप्त उत्पादन के मूल्य में से अंतवर्ती मूल्य को घटाने से वर्धित मूल्य प्राप्त होता है।

वर्धित मूल्य में विभिन्न वस्तुओं पर लगने वाले कर को जोड़ने, और कुल योग में से वस्तुओं पर मिली सब्सिडी घटा देने से जीडीपी प्राप्त हो जाता है।

सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है?

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (सीएनपी) राष्ट्र के नागरिकों द्वारा की गई सेवाओं तथा वस्तुओं के उत्पादन के मूल्य का कुल योग होता है। जीडीपी की तरह यह देश की सीमा के अंदर उत्पादन और सेवाओं के मूल्यों का योग नहीं होता। बल्कि इसमें विदेशों से अर्जित धनराशि का शुद्ध समापवर्तक मूल्य के साथ-साथ विदेशों में कमाई गई धनराशि में से ख़र्च के बाद स्वदेश आने वाली राशि भी शामिल होती है। समापवर्तक आमदनी कर्मचारियों के मुआवज़े, कॉर्पोरेट मुनाफ़ा और शुद्ध ब्याज के अनुसार आंकी जाती है।

सकल नियत पूंजी निर्माण क्या है?

सकल नियत पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) घरेलू अर्थव्यवस्था की संपत्ति में उद्यमों का संयोजन है। गणना काल में समाप्त की गई अचल संपत्ति को घटाने और उसी अवधि में गैर-उत्पादित अचल संपत्ति को घरेलू अर्थव्यवस्था में जोड़ देने से सकल नियत पूंजी निर्माण प्राप्त होता है। इस संदर्भ में अचल पूंजी को प्रवाहित पूंजी से अलग करना होगा। अचल यानी नियत पूंजी उसे कहते हैं जो माल के उत्पादन में ख़र्च नहीं होती यानी वस्तुओं के उत्पादन में इसका उपयोग नहीं होता है। इसके अंतर्गत संयंत्र, मशीनरी और भवन आदि शामिल हैं।

कार्ल मार्क्स और डेविड रिकार्डो जैसे जाने-माने अर्थशास्त्रियों के अनुसार, प्रवाहित पूंजी वह पूंजी है जो वस्तुओं के निर्माण और सेवा कार्यों में उपयोग में लाई जाती है। इनमें कच्चा माल और अंतवर्ती वस्तुएं शामिल हैं।

जीडीपी आकलन में क्या खामियां हैं?

जीडीपी में काला बाज़ारी का धन शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वहां धन व्यय को पंजीकृत नहीं किया जाता जिससे सकल घरेलू उत्पाद में असामान्य उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है।

उदाहरण के लिये, बड़े व्यापारिक देशों में अनौपचारिक कारोबार में स्थानीय अर्थव्यवस्था के अंश पंजीकृत नहीं हो पाते हैं। ऐसे में जीडीपी पर्यावरण, भरण-पोषण संबंधी उत्पादन और घरेलू कार्यों की उपेक्षा करता है।

ऐसा समझा जाता है कि यदि बगैर भुगतान के लिये गए कार्यों का अपवर्तन किया तो वह बिना मज़दूरी पाए मज़दूरों के साथ अन्याय होगा। ❑

RAU'S IAS

A name that Nation trusts

Amazing Success :

Our 2006 Exam Results : Seven positions secured by our students in first 20 and 34 in first 100 with overall 214 selections. As regards the past achievements, Study Circle has contributed nearly one-third of the total selections done for Civil Services by UPSC since 1953.

It is a well known fact that Rau's is the most trusted and recommended name all over the country for IAS & PCS coaching.

Unbeatable Strategy:

Answers that matter : The most crucial fact about coaching is that it should improve the quality of your answers in the minimum possible time. It is precisely this training on which we focus on at Rau's to give an extra edge to the answers you give / write in the Civil Services Examination.

Be Sure : We have no branches or associates anywhere in India except Jaipur. Our name which has become a legend among students for the highest standards in teaching, and hence has been copied by a lot of people across India, but no one can match our quality.

Programme Highlights :

Civil Services/PCS Exam - 2008

- **Personal Guidance (English Medium) is available for -**

  General Studies/ Essay, History, Sociology, Public Administration, Geography, Psychology, Law & Commerce.

- पर्सनल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) -

  सामान्य अध्ययन / निबंध, इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन एवं भूगोल में उपलब्ध।

- **Postal Guidance (English Medium) is available for -**

  General Studies, History, Sociology, Public Administration, Geography and Law.

- पोस्टल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) -

  सामान्य अध्ययन, इतिहास, लोक प्रशासन एवं भूगोल में उपलब्ध।

- **Hostel facility arranged.**

If you are taught by the stars, sky is the limit.

New batches for 2008 Exam, start from 26th October, 2007

Admission Open, Apply Now.

Contact personally or write for prospectus with a DD/MO of Rs. 50/- favouring

RAU'S IAS STUDY CIRCLE

Head Office : 309, Kanchanjunga Bldg., 18, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001
Phone : 011 - 23317293, 23318135-36, 23738906-07, 32448880-81, 65391202, Fax: 23317153

Jaipur Centre : 701, Apex Mall, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur - 302015, Ph.: 0141-6450676, 3226167, 9351528027

Website:www.rauias.com **E-mail : contact@rauias.com**

The Original Rau's - Since 1953

YH-10/07/2

हिंदी फिल्मों में 1857 का महाविद्रोह

❍ जवरीमल्ल पारख

हिंदुस्तान की आज़ादी का महत्वपूर्ण मुकाम होते हुए भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में 1857 पर बहुत कम फिल्में बनी हैं। 1857 के संग्राम की एक प्रमुख नेता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर 1953 में प्रमुख फिल्मकार सोहराब मोदी ने *झांसी की रानी* के नाम से फिल्म बनाई थी। इसके बाद 1960 में *लालकिला* फिल्म का निर्माण हुआ जिसे नानाभाई भट्ट ने निर्देशित किया था और जिसमें बहादुरशाह जफ़र के आखिरी दिनों का भी चित्रण किया गया है, जिसका संबंध 1857 के महाविद्रोह से था। उनकी इस फिल्म में जफ़र की लिखी दो ग़ज़लें जिन्हें मोहम्मद रफी ने गाया था, काफी लोकप्रिय हुई थीं। इसके लगभग 18 साल बाद 1978 में श्याम बेनेगल ने *जुनून* नाम की फिल्म का निर्माण किया और इसके भी लगभग 28 साल बाद 2005 में केतन मेहता ने *मंगल पांडे : दि राइजिंग* फिल्म का निर्माण किया। 1857 का थोड़ा-सा चित्रण मुजफ्फर अली की फिल्म *उमराव जान* (1981) में भी है। *उमराव जान* की कहानी लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही चलती है। कहानी भी उसी दौर की है जब अवध पर अंग्रेज़ों ने नियंत्रण किया था और बाद में 1857 के विद्रोह का जो मुख्य रणक्षेत्र बन गया था। लेकिन उस फिल्म की कहानी का सीधे तौर पर इस जनविद्रोह से कोई संबंध नहीं है। यह अवश्य है कि फिल्म उस दौर में सामंत वर्ग की पतनशीलता का चित्रण करती है, साथ ही यह भी बताती है कि स्त्रियों की दशा कैसी थी।

1857 के संदर्भ में अवध का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस संग्राम में अवध के सैनिकों और किसानों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया था। इस संघर्ष के शुरू होने के एक साल पहले ही अवध को अंग्रेज़ों ने हथिया लिया था। वहां के बादशाह वाजिदअली शाह को कलकत्ता में नज़रबंद रखा गया। अवध को हड़पने के लिये अंग्रेज़ों को एक भी गोली नहीं दागनी पड़ी थी। बिना किसी खून-ख़राबे के अवध की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली गई थी। अवध को हथियाने के अंग्रेज़ों की इसी चालबाजी पर सत्यजित राय ने 1977 में प्रख्यात फिल्म *शतरंज के खिलाड़ी* का निर्माण किया था। इस तरह ये चार फिल्में किसी-न-किसी रूप में 1857 से संबद्ध फिल्में हैं। 1857 के बारे में जो भी ऐतिहासिक जानकारी आज उपलब्ध है, उसके आलोक में यदि इन फिल्मों को देखें तो ये फिल्में कई अर्थों में काफी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि *जुनून* और *शतरंज के खिलाड़ी* साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। *जुनून* का निर्माण श्याम बेनेगल ने भारत के अंग्रेज़ी लेखक रस्किन बांड के उपन्यास *ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स* के आधार पर और सत्यजित राय ने शतरंज के खिलाड़ी का निर्माण इसी नाम की प्रेमचंद की कहानी के आधार पर किया था। जबकि शेष दोनों फिल्में ऐसी किसी साहित्यिक रचना पर आधारित नहीं है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे दोनों ही ऐतिहासिक पात्र हैं जबकि *जुनून* और *शतरंज के खिलाड़ी* के पात्र ऐतिहासिक नहीं बल्कि काल्पनिक हैं।

शतरंज के खिलाड़ी फिल्म में मुख्य कहानी मीर रौशन अली और मिरज़ा सज्जाद अली की है जो काल्पनिक चरित्र हैं और जिन्हें प्रेमचंद ने अपनी कहानी के लिये गढ़ा है। लेकिन उसी कहानी में वाजिदअली शाह एक ऐतिहासिक पात्र हैं और अंग्रेज़ी सेना के सामने बिना लड़े आत्मसमर्पण कर देना भी एक ऐतिहासिक सच्चाई है। मंगल पांडे एक ऐतिहासिक चरित्र है और 8 अप्रैल 1857 में बैरकपुर छावनी में अंग्रेज़ों ने उसे बलवे का अपराधी मानकर फांसी दे दी थी। *मंगल पांडे: दि राइजिंग* में मंगल पांडे के जीवन में जिन घटनाओं को होते हुए दिखाया गया है उनमें से ज्यादातर का संबंध मंगल पांडे से रहा होगा इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। *जुनून* फिल्म के लगभग सारे मुख्य पात्र काल्पनिक हैं लेकिन 1857 का घटनाक्रम पूरी तरह से ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, खासतौर पर रुहेलखंड के इलाके में जो घटनाएं 1857 के दौरान घटी थीं, उनको ध्यान में रखते हुए फिल्म में उन्हें पेश किया गया है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि लक्ष्मीबाई की शादी बचपन में ही बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ाते गंगाधर राव से कर दी गई थी और आज की

दृष्टि से इसे किसी स्त्री पर बहुत बड़ा अत्याचार ही कहा जाएगा। लेकिन सोहराब मोदी इस अमानवीय कृत्य को देशभक्ति की भावना के बरक्स महिमामंडित करने का प्रयास करते हैं। देशभक्ति की इसी भावना के कारण यह कुकृत्य न केवल फिल्म में सुकृत्य बन जाता है बल्कि यह उन ऐतिहासिक तथ्यों पर भी पर्दा डालने का काम करता है जो बताते हैं कि लक्ष्मीबाई का वैवाहिक जीवन सुखद नहीं था।

सत्यजित राय, श्याम बेनेगल और केतन मेहता तीनों ही फिल्मकारों ने इन फिल्मों का निर्माण करते हुए व्यावसायिक सिनेमा के लोकप्रिय कलाकारों को ही नहीं लिया बल्कि इन फिल्मों को बड़े बजट और गीत, संगीत और नृत्य जो हिंदी के व्यावसायिक सिनेमा की पहचान कहे जो सकते हैं, उनका समावेश करते हुए बनाया है। *शतरंज के खिलाड़ी* में व्यावसायिकता सबसे कम है तो *मंगल पांडे : दि राइजिंग* में सबसे ज्यादा। इन सभी फिल्मों में फिल्म की दृष्टि से देखें तो इतिहास को प्रस्तुत करना कथावस्तु का केंद्रीय मुद्दा नहीं है। *शतरंज के खिलाड़ी* में मीर और मिरज़ा के शतरंज खेलने के जुनून की कहानी है जिसे वाज़िदअली शाह के समय के साथ और अवध के पतन के साथ जोड़ कर पेश किया गया है। *जुनून* में जावेद खान (शक्ति कपूर) और अंग्रेज़ लड़की रूथ (नफीसा अली) की प्रेम कहानी के इर्द-गिर्द फिल्म की कहानी विकसित होती है। लेकिन इस प्रेम कहानी का सीधा संबंध 1857 के महाविद्रोह में अंग्रेज़ों की जीत और हार से है। *मंगल पांडे : दि राइजिंग* में मंगल पांडे (आमिर खान) और हीरा (रानी मुखर्जी) की प्रेमकथा भी चलती है और मंगल पांडे और अंग्रेज़ कैप्टेन विलियम गोर्डन (टॉबी स्टीफन्स) की दोस्ती की कहानी भी चलती है। जुनून में तो यह उपन्यास का केंद्रीय प्रसंग है जबकि *मंगल पांडे : दि राइजिंग* में यह फिल्मकार की अपनी कल्पनाशीलता का नतीज़ा है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि मंगल पांडे का किसी नाचने-गाने वाली स्त्री से कोई संबंध रहा था या उसका कोई अंग्रेज़ दोस्त था। लेकिन फिल्म के अंत में फिल्मकार इतिहास का उदाहरण देकर बताता है कि गोर्डन नाम के अंग्रेज़ सिपाही ने भी भारतीयों की तरहफ से इस महाविद्रोह में भाग लिया था। हीरा-मंगल पांडे की प्रेमकथा के प्रसंग के कारण वे लोग जो अपने को मंगल पांडे का वंश बताते हैं, फिल्मकार के विरुद्ध कोर्ट में भी गए। उनका आरोप था कि मंगल पांडे को जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया है उससे ऐतिहासिक मंगल पांडे की छवि को आघात पहुंचा है।

1857 पर बनी किसी भी फिल्म के संदर्भ में दो भिन्न दृष्टिकोण को ध्यान में रखना जरूरी है। बहुत से इतिहास लेखक भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में 1857 को अधिक महत्व नहीं देते क्योंकि उनकी दृष्टि में 1857 का महाविद्रोह पतनशील सामंतवादी शक्तियों का एक बार फिर भारत की सत्ता को अपने हाथ में लेने का प्रयास भर था। उनका विचार था कि अंग्रेज़ वास्तव में आधुनिकता के वाहक थे। इस आधार पर कुछ लेखक अब भी मानते हैं कि 1857 का विद्रोह यदि कामयाब हो जाता तो इसकी बंजर कोख से "जिस विकलांग राष्ट्रवाद का जन्म होता वह विनायक दामोदर सावरकर के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 'स्वधर्म' और 'स्वराज्य' के रास्ते हिंदू राष्ट्रवाद तक पहुंचता" (वीरेंद्र यादव, पृ. 153)। यहां इस तथ्य को भुला दिया जाता है कि इसी 1857 की असफलता के बाद ही अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट की मुहिम चलाई और जो अंततः देश के दो टुकड़े कराने में कामयाब हुई। यदि 1857 कामयाब हो जाता तो भारत के दो बड़े धर्मावलंबियों के बीच एक स्वाभाविक भाईचारा और बलवती होता। यही नहीं, ये ही सैनिक जिन्होंने अपनी इच्छा से बहादुर शाह ज़फर को जबरन सिंहासन पर बैठने के लिये मज़बूर किया था, वे ही ऐसे शासकों को उखाड़ फेंकने में कामयाब हो जाते जो जनता के हित में काम नहीं करते। ऐसा होता तो क्या होता या वैसा होता तो क्या होता का प्रश्न बेमानी है।

1857 पर सबसे पहले बनी *झांसी की रानी* राष्ट्रवादी भावना से बनाई गई फिल्म है और तब तक उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप यह काफी हद तक इतिहास के प्रति ईमानदार रहते हुए बनाई गई है। लेकिन कथा के केंद्र में लक्ष्मीबाई (फिल्म अभिनेत्री महताब ने लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाई थी) ही रहती है। फिल्म न तो 1857 के विद्रोह की पड़ताल करती है, न ही झांसी के शासक और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सत्ता को लेकर चल रहे संघर्ष को व्यापक परिप्रेक्ष्य में पेश करती है। फिर भी यह फिल्म लक्ष्मीबाई के शौर्य और बलिदान, हिंदू-मुस्लिम एकता और अंग्रेज़ों के विरुद्ध उनके सामूहिक संघर्ष का प्रभावी चित्रण करने में कामयाब रहती है। फिल्म की सीमा यह है कि एक स्त्री के रूप में लक्ष्मीबाई की आंतरिक वेदना और संघर्ष को बिल्कुल नहीं छूती। एक बूढ़े आदमी गंगाधर राव (मुबारक) से शादी और युवावस्था में कदम रखते ही विधवा हो जाने की पीड़ा को फिल्म की कहानी का हिस्सा नहीं बनाया गया है। यही नहीं, झांसी के राजगुरू (खुद सोहराब मोदी ने यह भूमिका निभाई थी) जो इस विवाह में निमित्त बनता है, उसे फिल्म महिमामंडित करती है जबकि अब लक्ष्मीबाई के वैवाहिक जीवन के बारे में कई नयी जानकारियां प्राप्त हो चुकी हैं। यह भी ज्ञात हो चुका है कि उनकी स्त्री सेना में झलकारी बाई नामक एक दलित (कोइरी) स्त्री भी थी जो दिखने में लक्ष्मीबाई जैसी लगती थी और जिसका साहस और बलिदान लंबे समय तक इतिहास की किताबों के नीचे दबा रहा। फिल्म की इन सीमाओं के लिये निचश्य ही सोहराब मोदी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐतिहासिक फिल्मों के लिये प्रख्यात सोहराब

मोदी ने जिस दौर में यह फिल्म बनाई थी उस दौर में उनके लिये स्त्री और दलित मुक्ति प्रश्नों को फिल्म की कथा में जोड़ना संभव नहीं था। देशभक्ति और हिंदू-मुस्लिम एकता जैसे तत्कालीन सवालों को उन्होंने शामिल किया था। इस तरह के ऐतिहासिक पात्रों को केंद्र में रखकर फिल्म में भी लक्ष्मीबाई इसी तरह की नायिका है और राजगुरु के रूप में उसी तरह का नायकत्व निर्मित किया गया है जो कई राष्ट्रवादी इतिहासकार और लेखक चाणक्य के जरिये करते रहे हैं।

सोहराब मोदी की तुलना में सत्यजित राय, श्याम बेनेगल और केतन मेहता राजनीतिक-सामाजिक दृष्टि से अधिक प्रगतिशील और फिल्मकार की दृष्टि से अधिक रचनात्मक और कलात्मक फिल्में बनाने के लिये जाने जाते हैं। सत्यजित राय बांग्ला फिल्मकार थे और *शतरंज के खिलाड़ी* उनकी पहली फिल्म है जिसे उन्होंने हिंदी में बनाया। इसके लिये उन्होंने प्रेमचंद की कहानी *शतरंज के खिलाड़ी* को चुना। *शतरंज के खिलाड़ी* एक छोटी लेकिन प्रख्यात कहानी है जिसमें प्रेमचंद ने वाजिदअली शाह के जमाने के सामंती लखनऊ की पतनशील संस्कृति को उज़ागर किया है। मीररौशन अली और मिरज़ा सज्जाद अली नाम के दो जमींदारों के शतरंज खेलने की लत को केंद्र में रखकर उन्होंने इस विडंबना को उजागर किया कि जो सामंत शतरंज के बादशाह और वजीर के लिये एक-दूसरे की जान ले लेते हैं वे अपने वतन की रक्षा के लिये एक बूंद खून बहाने को तैयार नहीं हैं। इसी विडंबना को सत्यजित राय ने प्रेमचंद की ही कहानी से संकेत लेकर अवध को हथियाने की लार्ड डलहौजी की चालों और वाज़िदअली शाह द्वारा लखनऊ को बचाने की दयनीय कोशिशों के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद ने यह कहानी यद्यपि मिरज़ा सज्जाद अली और मीर रौशन अली के शतरंज खेलने की लत पर केंद्रित की है, लेकिन इस कहानी की पृष्ठभूमि में वाज़िदअली शाह का लखनऊ है।

ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह एक-एक कर भारत की बड़ी-बड़ी रियासतों को हड़प रही थी, उसकी आखिरी कड़ी अवध पर नियंत्रण था। 7 फरवरी, 1856 को अवध ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। वह एक स्वाधीन राज्य की बजाय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अवध के शासक वाजिदअली शाह को गिरफ्तार कर कलकत्ता भेज दिया गया। यह सही है कि वाज़िदअली शाह और उसकी सेना ने अंग्रेज़ों का प्रतिरोध नहीं किया था, लेकिन वाज़िदअली शाह ने उस संधिपत्र पर हस्ताक्षर करने से भी इंकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि वह खुशी से अपनी सल्तनत कंपनी को देने के लिये राज़ी है (सुंदरलाल, पृ. 801)। कंपनी की अंग्रेज़ सरकार ने वाजिदअली शाह पर यह आरोप लगाया था कि उसके शासन में अव्यवस्था और अराजकता फैली हुई है। प्रेमचंद्र ने अपनी कहानी में इस अव्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है।

कहानी को पढ़ने से यह साफ़ हो जाता है कि प्रेमचंद इस बात में यकीन करते थे कि लखनऊ की तत्कालीन दुर्दशा के लिये वाजिदअली शाह का शासन जिम्मेदार था। फिल्म में सत्यजित राय ने कमोबेश यही रवैया अपनाया है, हालांकि इतिहासकार अब इस मत से पूरी तरह सहमत होते नज़र नहीं आते। इतिहासकार रुद्रांग्शु मुखर्जी ने अवध को हथियाने की कार्रवाई का विवेचन करते हुए लिखा था कि लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में ही अवध को हड़पने का मंसूबा बांध रखा था। उसने अवध के राज को चेरी की संज्ञा दी थी जो एक-न-एक दिन उनके मुंह में टपक पड़ेगा। सत्यजित राय ने लार्ड डलहौजी के इस रूपक का उल्लेख एनिमेशन के जरिये अपनी फिल्म में भी किया था। रुद्रांग्शु मुखर्जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि अवध राज्य पर्याप्त रूप में अक्षम और भ्रष्ट था। लेकिन उनका यह मानना भी था कि इसका कारण सिर्फ़ यह नहीं था कि बादशाह में शासन करने की योग्यता नहीं थी जैसाकि डलहौजी सोचता था, बल्कि इसका कारण उस गठबंधन में निहित था जिससे अवध कंपनी के साथ बांध था (*अवध इन रिवोल्ट : 1857-1858*, पृ. 32)।

प्रेमचंद ने जिस समय कहानी लिखी थी तब उनके सामने वाजिदअली शाह के शासन के बारे में ब्रिटिश शासकों द्वारा फैलाया हुआ प्रचार ही मौजूद था। इस प्रचार में मुख्य बल इस बात पर था कि वाजिदअली शाह एक नकारा शासक था जो शासन करने की बजाय अपने को नाच-गानों में डुबोए रखता था। प्रेमचंद ने अपनी कहानी में इसी को आधार बनाया है। हालांकि कई इतिहासकार और विद्वान वाजिदअली शाह को ऐसा नकारा शासक नहीं मानते। पंडित सुंदरलाल का तो मानना है कि "वाजिदअली शाह की ऐशपरस्ती की निस्बत जितनी बातें कही जाती हैं, उनमें 90 फीसदी कल्पित और झूठी हैं" (*भारत में अंग्रेज़ी राज*, द्वितीय भाग, पृ. 802)। अगर हम बहुत विस्तार में न भी जाएं तो इस ऐतिहासिक तथ्य को नहीं भुलाया जा सकता कि अवध की जनता पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। अवध की जनता अपने राजा की दुर्दशा पर अधिक दुखी थी, जिसे अपना वतन छोड़ना पड़ा था। इस घटना पर लोकगीत रचे गए।

अवध पर नियंत्रण के लिये लॉर्ड डलहौजी ने भले ही वाजिदअली शाह के कुशासन को कारण के रूप में पेश किया हो, लेकिन नियंत्रण के दूसरे दिन ही डलहौजी ने यह साफ़ कर दिया था कि अवध को कब्ज़े में लेने के पीछे असली मंशा क्या थी। "हमारी दयालु महारानी के पास कल से पचास लाख अधिक प्रजा और तेरह लाख पौंड अधिक राजस्व हो गया है" (*डलहौजी टू बार्ट*, 8 फरवरी, 1856 : बेयर्ड, *लेटर्स ऑफ डलहौजी*; पृ. 369; *अवध इन रिवोल्ट* : 1857-1858 से उधृत, पृ. 35)। उस समय

अंग्रेज़ों यह मानना था कि दुनिया में भारत के अलावा शायद ही कोई देश और भारत में अवध के अलावा शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसे पूंजी निवेश की दृष्टि से बेहतर कहा जा सके। प्रेमचंद ने अंग्रेज़ों की इस लूट की ओर संकेत किया है। सत्यजित राय ने फिल्म में अंग्रेज़ों की इस लूट का जिक्र किया है। यहां तक कि अवध के टुकड़े केक की तरह काट कर अंग्रेज़ सरकार को खुश करने के लिये भेंट में चढ़ा दिए जाते थे, इस बात को भी नेरेटर (अमिताभ बच्चन) की टिप्पणियों के माध्यम से कहलाया गया है।

इन नये तथ्यों ने प्रेमचंद की कहानी के महत्व को कम नहीं किया था बल्कि और बढ़ा दिया था इसीलिये सत्यजित राय ने अवध के पतन के लिये एक स्वतंत्र फिल्म बनाने की बजाय प्रेमचंद की कहानी को ही आधार के रूप में चुना। इसका कारण यह था कि प्रेमचंद की तरह सत्यजित राय भी तत्कालीन सामंतों के उतने ही आलोचक थे। प्रेमचंद जिस समय कहानी लिख रहे थे, उस समय आज़ादी की लड़ाई एक ऐसे मुक़ाम पर पहुंच गई थी जहां साम्राज्यवाद से मुक्ति ही मुख्य लक्ष्य नहीं रह गया था बल्कि आज़ाद भारत कैसा हो यह भी एक अहम लक्ष्य बनता जा रहा था। जिस लोकतांत्रिक भारत की संकल्पना सामने आ रही थी, उसमें सामंतवाद के लिये कोई जगह नहीं थी। प्रेमचंद जैसे प्रगतिशील लेखक इसी लोकतांत्रिक भारत के निर्माण की परिकल्पना अपनी रचनाओं द्वारा प्रस्तुत कर रहे थे। इसका स्वाभाविक अर्थ यह भी था कि सामंतवाद की प्रति भी वे राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक दृष्टि से विचार करते। इस मामले में सत्यजित राय प्रेमचंद के दृष्टिकोण से सहमति रखते हैं और इसलिये वे फिल्म में वाजिदअली शाह के समय की पतनशीलता का विस्तार से चित्रण करते हैं।

प्रेमचंद के विपरीत सत्यजित राय वाजिदअली शाह के निजी शौकों पर भी विस्तार से प्रकाश डालते हैं। वाजिदअली शाह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था और वह हिंदू और मुस्लिम त्यौहारों में समान रूप से भाग लेता था। साहित्य और कला में उसकी गहरी रुचि थी और उसका अधिकांश समय उसी में बीतता था। वह स्वयं कवि, गायक, नर्तक था। वह संगीत और नृत्यनाटकों की रचना भी करता था। इससे इतना तो ज़ाहिर है कि सत्यजित राय ने फिल्म के लिये वाज़िदअली शाह के बारे में प्रामाणिक जानकारी हासिल की थी। इसके बावजूद भी उसके शासन के प्रति उन्होंने वही दृष्टिकोण अपनाया था जो प्रेमचंद ने अपनाया था। इसे उनका अंतर्विरोध कहा जाना चाहिए या सामंतवाद की ऐतिहासिक भूमिका के प्रति उनकी स्पष्ट सोच। चाहे यह सोच प्रतिशत में वाज़िदअली शाह के बारे में शत-प्रतिशत खरा न उतरता हो।

फिल्म का अंत कहानी से अलग है। कहानी में मीर और मिरज़ा शतरंज को लेकर एक-दूसरे से भिड़ जाते हैं। अपनी-अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और इस तरह वे लड़ते हुए एक-दूसरे को मार डालते हैं। कहानी के इस अंत की व्याख्या प्राय: इस रूप में की गई है कि प्रेमचंद ने इस मरणासन्न सामंतवाद की मौत को एक ऐतिहासिक सच्चाई के रूप में रखा है जबकि सत्यजित राय ने उन्हें दुबारा शतरंज खेलते हुए दिखाकर यह बताना चाहा है कि जिस सामंतवाद के मरने की भविष्यवाणी प्रेमचंद ने अपनी कहानी के जरिये की थी, वह दरअसल मरा नहीं था। आज़ाद भारत में भी यह सामंतवाद पूंजीवाद के साथ गठजोड़ कर अपने को बचाए और बनाए हुए है। यदि प्रेमचंद ने अपने ढंग से एक ऐतिहासिक सच्चाई को पेश किया था तो सत्यजित राय ने उसी सच्चाई को अपने वर्तमान संदर्भों में पुनर्व्याख्यायित करने का प्रयास किया है।

कहानी और फिल्म दोनों की सीमा यह है कि इनमें अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद की भूमिका को कम कर आंका गया है। अवध पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण इतिहास के एक अध्याय की समाप्ति का सूचक है। भारतीय सामंतवाद का अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद के सामने यह आखिरी समर्पण था। अब यदि कोई भी प्रतिरोध हो सकता था तो वह भारतीय जनता के जरिये ही। प्रेमचंद ने भारतीय इतिहास के इस महत्वपूर्ण मोड़ की विडंबनात्मक तस्वीर को अपनी इस कहानी के जरिये पेश किया है। इस दृष्टि से यह एक ऐतिहासिक महत्व की महाकाव्यात्मक कहानी है। किसी कहानी में महाकावात्मक की संभावना पैदा करना प्रेमचंद जैसे कालजयी रचनाकार द्वारा ही संभव था। इसके इसी ऐतिहासिक और रचनात्मक महत्व को समझकर ही सत्यजित राय ने इसे एक महाकाव्यात्मक फिल्म के लिये चुना।

मंगल पांडे: दि राइजिंग 1857 को अंग्रेज़ों के विरुद्ध शक्तिशाली जन-उभार के रूप में प्रस्तुत करती है। 1857 का संबंध अवध से बहुत गहरा है। 7 फरवरी, 1856 को जब लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कब्ज़ा किया उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज़ में अवध के सैनिक बहुत बड़ी संख्या में भर्ती होने लगे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में जिसे बंगाल आर्मी के नाम से जाना जाता था, उसके बारे में आमतौर पर यह कहा गया है कि उसके अधिकांश सैनिक अवध से आते थे। 1857 की 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में जिस मंगल पांडे नाम सैनिक ने अंग्रेज़ अधिकारियों पर गोली चलाई थी, उसके बारे में भी यही माना जाता है कि वह अवध क्षेत्र का रहने वाला था। इस मंगल पांडे को 1857 का पहला शहीद कहा गया है (वी. डी. सावरकर, *दि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस* , 1857, पृ. 101 -06) और यह माना जाता है कि 1857 की शुरुआत मंगल पांडे की शहादत से ही हो गई थी।

मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी को 34वीं बंगाल नेटिव इंफेंट्री की पांचवीं कंपनी का एक सिपाही था। वह 29 मार्च, 1857 को रविवार के दिन दोपहर के बाद लगभग चार

डॉ. मनमोहन सिंह
माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार

नयी परियोज
कृषि जगत उ

राष्ट्र

- योजना के मु
  - → कृषि अ
  - → यह सु उपलब
  - → महत्वपू उत्पाद
  - → यह सु
  - → कृषि अ
  - → कृषि अ
- योजना के त प्रदान करने

कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि मंत्रालय
भारत सरकार

समृद्ध किसा

ाएँ नया दौर
नति की ओर

श्री शरद पवार
माननीय कृषि, उपभोक्ता मामले,
खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
भारत सरकार

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

- इसका उद्धेश्य वर्ष 2011–12 तक 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं और 2 मिलियन टन दालों का अतिरिक्त उत्पादन करना है ताकि खपत मांग को पूरा किया जा सके और देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।
- देश में 16 राज्यों के 305 जिलों में लगभग 250 लाख किसानों के लाभान्वित होने की आशा है।
- कुछ क्षेत्रों जिनमें किसान मिशन के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता पाने के पात्र हो सकते हैं, में शामिल हैं :–
  - → बेहतर गुणवत्ता वाले बीज।
  - → फार्म मशीनरी।
  - → खेत पर जल प्रबंधन।
  - → कीटनाशियों के कुशलतम प्रयोग हेतु समेकित कीट प्रबंधन।
  - → मृदा स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए समेकित पोषक तत्व प्रबंधन।
- किसानों को लाभ पहुंचाने वाले अन्य क्रियाकलापों में शामिल हैं :–
  - → बड़े पैमाने पर क्षेत्र प्रदर्शनों के जरिए उन्नत पैकेज पद्धतियों का प्रदर्शन।
  - विस्तार समर्थन प्रदान करने के लिए कृषक फील्ड स्कूलों (एफएफएस) का आयोजन।

कृषि विकास योजना

देश्य हैं:–

बद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों को आर्थिक प्रोत्साहन।

त करना कि जिलों/राज्यों की कृषि योजनाएं कृषि जलवायुवीय परिस्थितियों, प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक संसाधनों की आधार पर तैयार की जाती है।

लों में उपज के अन्तर को कम करना और संकेन्द्रित एवं समग्रवादी पहलों के जरिए कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में उत्पादन और को बढ़ाना।

करना कि जिलों/राज्यों की कृषि योजनाओं में स्थानीय जरुरतें/फसलें/प्राथमिकताएं बेहतर रुप से प्रतिबिम्बित हैं।

बद्ध क्षेत्र स्कीमों के नियोजन और कार्यान्वयन में राज्यों को लचीलापन और स्वायत्ता प्रदान करना।

बद्ध क्षेत्रों में किसानों की आय को अधिकतम करना।

न्द्र से सहायता हेतु पात्रता आधारमूल से ज्यादा व्यय के लिए कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों हेतु राज्य के योजना बजट की धनराशि ाज्य सरकार पर निर्भर होगी।

dav 01101/13/0027/0708

YH-10/07/15

बजे अपनी बंदूक और तलवार लेकर परेड मैदान में आ गया। उस समय उसने धोती और सिपाहियों द्वारा पहनी जाने वाली लाल जैकेट पहन रखी थी। उसके एक हाथ में बंदूक थी और दूसरे हाथ में तलवार थी। वहां वह ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर अपने साथियों को आवाज़ देने लगा। उसने अपने साथियों को आवाज़ देकर बाहर आने के लिये ललकारा और कहा कि 'मुझे तो बाहर भेज दिया ओर अब खुद बाहर क्यों नहीं आते। अंग्रेज़ यहां है। अपने धर्म की रक्षा के लिये बाहर आओ। इन कारतूसों को काटने से हमारा धर्म चला जाएगा। तैयार हो जाओ।' किसी सिपाही द्वारा इस तरह की हरकत बहुत असामान्य थी और वहां मौजूद नायक ने अपने गोरे अधिकारी सार्जेंट मेजर जेम्स ह्युसन को इस बात की इत्तिला दी। इसके बाद उसे पकड़ने की कोशिश हुई। इस कोशिश में अंग्रेज़ अफसरों और मंगल पांडे के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में अंतत: जब उसने अपने को घिरा हुआ पाया तो अपनी बंदूक से अपने को मारने की कोशिश की। घायलावस्था में उसे पकड़ लिया गया। बैरकपुर छावनी में ही छह अप्रैल को मंगल पांडे पर मुकदमा चलाया गया और दो दिन बाद 8 अप्रैल, 1857 को सुबह साढ़े पांच बजे उसे फांसी दे दी गई। जिस जमादार ईश्वरी पांडे ने मंगल पांडे को गिरफ़्तार करने का आदेश मानने से इंकार कर दिया था उसे भी कुछ दिनों बाद फांसी दे दी गई। पंडित सुंदरलाल के अनुसार मंगल पांडे को बैरकपुर में कोई फांसी देने के लिये तैयार नहीं हुआ। इस काम के लिये कलकत्ते से चार आदमी बुलाए गए (*भारत में अंग्रेज़ी राज*, द्वितीय खंड, पृ. 831)। शेख पलटू जिसने मंगल पांडे को पकड़ लिया था, उसको मुक़दमा खत्म होने से पहले ही तरक्की दे दी गई (*मंगल पांडे: ब्रेव मार्टयर ऑर एक्सिडेंटल हीरो?*, पृ.49)। मंगल पांडे और ईश्वरी पांडे को फांसी देने तक ही यह घटना नहीं रुकी। बाद में 21 अप्रैल को 34वीं बंगाल नेटिव इंफेंट्री से हथियार रखवा लिये गए। इससे एक सप्ताह पूर्व 19वीं रेजिमेंट से भी हथियार छीन लिए गए थे। 19वीं रेजिमेंट ने हथियार छीने जाने का किसी भी तरह से प्रतिरोध नहीं किया था जबकि मंगल पांडे की रेजिमेंट ने अपनी टोपियां ज़मीन पर फेंक दी और अपने अफसरों के सामने ही उनको पैरों तले कुचल कर अपना रोष प्रकट किया।

मंगल पांडे के जीवन की इतनी ही कहानी है लेकिन 1857 के महाविद्रोह ने मंगल पांडे को भारत की आज़ादी की लड़ाई का पहला सेनानी और शहीद बना दिया। उसने 29 मार्च को अकेले जो कृत्य किया उसे बाद के इतिहासकारों ने एक चिनगारी की तरह लिया। *मंगल पांडे : दि राइजिंग* में भी फिल्मकार केतन मेहता की दिलचस्पी ऐतिहासिक मंगल पांडे में उतनी नहीं जितनी उस मिथकीय मंगल पांडे में है जिसकी एक खास प्रतिमा 1857 के महाविद्रोह ने बना दी थी। खास बात यह है कि यह प्रतिमा उन अंग्रेज़ अधिकारियों और इतिहासकारों ने बनाई थी जिन्होंने मंगल पांडे के व्यक्तिगत विद्रोह की ही एक कड़ी के रूप में 1857 के महाविद्रोह को देखा था। केतन मेहता ने फिल्म का निर्माण करते हुए उनसे संबंधित इतिहास की गहरी छानबीन की है। उसमें से उन्होंने अपनी फिल्म के लिये प्रसंग, पात्र और इतिहास की दृष्टि भी चुनी है। लेकिन ऐसा करते हुए भी वे इतिहास के प्रसंगों और पात्रों को कच्चे माल की तरह ही इस्तेमाल करते हैं और फिल्म में इतिहास को यथावत पेश करने की बजाय अपनी फिल्म की ज़रूरत के मुताबिक उसकी पुनर्रचना करने की कोशिश करते हैं। इतिहास की पुनर्रचना स्वयं इतिहास में से नि:सृत हुई है इसलिये प्रश्न इतिहास के प्रति ईमानदार रहने का उतना नहीं है जितना कि इतिहास की पुनर्रचना की अपनी प्रासंगिकता और फिल्म के रूप में उसकी सार्थकता का है।

केतन मेहता ने फिल्म बनाते हुए अपने को उस मंगल पांडे तक सीमित नहीं रखा जिसके बारे में बहुत ही सीमित जानकारी उपलब्ध है कि बल्कि उन्होंने उसे 1857 के महविद्रोह की चिंगारी के रूप में ही ग्रहण किया। इसलिये उन्होंने व्यक्ति मंगल पांडे की बजाय उस सामूहिक चेतना को अपना नायक बनाया जो मंगल पांडे के व्यक्तिगत विद्रोह के पीछे मौजूद थी। इसलिये *मंगल पांडे: दि राइजिंग* फिल्म के नायक को व्यक्ति मंगल पांडे की बजाय उस मंगल पांडे के रूप में देखना चाहिए जो 1857 के महाविद्रोह का प्रेरणा स्रोत और पथप्रदर्शक कहा जा सकता है। 29 मार्च, 1857 को जब उसने अंग्रेज़ अधिकारियों पर गोली चलाई तब उसने यह देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर नहीं किया था और न ही उस समय तक 'राष्ट्र' जैसी कोई परिकल्पना ही उभरी थी। अगर ऐसा होता तो ये सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती ही क्यों होते। उनके लिये उनका मुल्क उनका अपना गांव था और जिस भूमि पर उनके बाप-दादा खेती करते थे वही उनका वतन था। (*मंगल पांडे: ब्रेव मार्टयर और एक्सिडेंटल हीरो?*, पृ. 52)। रुद्रांग्शु मुखर्जी ने इस संदर्भ में उचित ही कहा है कि मंगल पांडे और दूसरे भारतीय सैनिक सिपाहियों के वेश में किसान थे। इन किसानों के लिये कंपनी की सेना में भर्ती होने के पीछे कई तरह के प्रोत्साहन निहित थे। उससे गांव और समाज में उनकी साख बढ़ती थी, आर्थिक लाभ था और अपने समाज में प्रभाव भी बढ़ता था (वही, पृ. 13)। यदि उन्होंने विद्रोह किया था तो इसके पीछे ठोस कारण यह था कि अंग्रेज़ों की फौज़ में काम करते हुए जो अपमान और उत्पीड़न उन्हें झेलना पड़ रहा था, वह इक्का-दुक्का सैनिकों को नहीं बल्कि सभी भारतीय सैनिकों को झेलना पड़ता था।

ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के विद्रोह के पीछे धर्म और जाति को ही कारण के रूप में पेश किया जाता रहा है जबकि कुछ बुनियादी कारण भी थे। अवध जहां से सबसे

अधिक सैनिक भर्ती होते थे, उस पर कब्ज़ा करने के बाद अंग्रेज़ों द्वारा जो नयी नीतियां (महालवाड़ी व्यवस्था) अपनाई गईं उसने वहां के तालुकेदारों और किसानों दोनों के आर्थिक हितों को गहरी चोट पहुंची थी (*अवध इन रिवोल्ट: 1857-1858*, पृ. 63)। अपने हितों की रक्षा के लिये कुछ राजा, नवाब, सामंत और जागीरदार भी शामिल थे। इन सब वर्गों ने यह समझ लिया था कि हमारे दुखों का कारण विदेशी सत्ता है और इसे उखाड़ फेंकना ज़रूरी है। इसलिये 1857 के महाविद्रोह को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इसे ऐसे राष्ट्रीय महाविद्रोह के रूप में देखना चाहिए जिसमें यदि ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक शामिल थे तो किसान जनता भी शामिल थी। इसी परिप्रेक्ष्य में जैसाकि कार्ल मार्क्स ने समझा था, यह 'राष्ट्रीय क्रांति' थी और इसी अर्थ में यह साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष भी था (इरफ़ान हबीब, पृ. 11)। मंगल पांडे पर बनी केतन मेहता की फिल्म को देखते हुए इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को सामने रखना आवश्यक है।

गाय और सूअर की चर्बी लगे जिन कारतूसों का उल्लेख फिल्म में किया गया है और जिनके कारण हिंदू और मुसलमान सैनिकों को अपना धर्म और जाति चले जाने का ख़तरा पैदा हो गया था, और जिनको वे हर तरह का ख़तरा उठाकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, वही कारतूस विद्रोह के दौरान उन्हीं सैनिकों द्वारा अंग्रेज़ों को मारने के लिये धड़ल्ले से इस्तेमाल किया गया। इस बात को 1857 के बाद चले मुकदमे के दौरान खुद अंग्रेज़ अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया गया। फिल्म में इस बात को मंगल पांडे के माध्यम से कहलाया गया है। इस फिल्म में 1857 की तैयारी का भी एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। सिपाहियों की रात को होने वाली गुप्त बैठकें, अजीमुल्ला खां, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई और तात्यां टोपे जैसे 1857 के नेताओं का मिलना और विद्रोह की तैयारी करना, उसके लिये एक दिन मुकर्रर करना जैसे कई पक्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। फिल्म में मंगल पांडे के साथ जो साथी सबसे ज्यादा सक्रिय नज़र आते हैं उनमें एक मुसलमान सिपाही भी है। 1857 के संदर्भ में हिंदू-मुस्लिम एकता को प्राय: सभी इतिहासकारों ने रेखांकित किया है। यह एकता इसलिये नहीं थी कि अंग्रेज़ शासकों द्वारा हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म पर आघात किया जा रहा था बल्कि इसलिये थी कि उस समय तक भारतीय जनता में सांप्रदायिक विभाजन की कोशिशें नहीं हुई थीं। ऐसी कोशिशें अंग्रेज़ों के ही संरक्षण में अंग्रेजों के मातहत काम करने वाले मध्यवर्गीय भारतीयों के द्वारा की गई थी। इसलिये कई इतिहासकार 1857 के महाविद्रोह में हिंदू और मुसलिम एकता को सामंतों की एकता के रूप में देखते हैं। लेकिन इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि फिल्मकार ने मंगल पांडे को सामंतशाही समर्थक के रूप में नहीं बल्कि उसके आलोचक के रूप में प्रस्तुत किया है। अजीमुल्ला खां और तात्यां टोपे के साथ होने वाली बैठक में मंगल पांडे और उनके साथी ही ये सुझाव देते हैं कि विद्रोह का नेता मुगल बादशाह बहादुरशाह ज़फ़र होंगे। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि 10 मई, 1857 को विद्रोह के बाद सैनिक सीधे दिल्ली पहंचते हैं और अनिच्छा के बावजूद बहादुरशाह को वे इस महाविद्रोह का नेता घोषित कर देते हैं। दिल्ली पर सिपाहियों की जीत और बहादुशाह ज़फ़र के नेता बनाए जाने का प्रतीकात्मक महत्व था। इसने हिंदुस्तान की जनता को यह भरोसा दिया कि अब अंग्रेज़ों को इस देश में भगाया जा सकता है। और इसी के बाद विद्रोह की चिंगारी पूरे उत्तर भारत में फैल जाती है। मंगल पांडे का भी इसी तरह का प्रतीकात्मक महत्व था।

मंगल पांडे: दि राइजिंग फिल्म में सैनिकों और किसानों में बढ़ते असंतोष के कारणों को तलाशने की कोशिश की गई है। इसमें वे घटनाएं भी शामिल हैं जिनमें किसानों को ज़बरन अफ़ीम उगाने के लिये मज़बूर किया जाता है और बंद में अफ़ीम उगाने के लिये उन्हें दंडित किया जाता है। दंड के फलस्वरूप उनके गांवों में आग लगा दी जाती है, उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं। इस फिल्म में उन कारणों को शामिल नहीं किया गया है जो उत्तर भारत के किसानों में अंग्रेज़ी राजसत्ता के प्रति असंतोष के रूप में व्यक्त हो रहे थे और जिन पर अब इतिहासकारों ने काफी काम किया है और जिनका उल्लेख इसी आलेख में पहले किया जा चुका है। लेकिन फिल्म इस बात को बताने में कामयाब रही है कि अंग्रेज़ों के प्रति भारतीय जनता में असंतोष बहुत व्यापक था जिनमें सिर्फ़ सिपाही ही नहीं बल्कि किसान और मेहनतकश जनता भी शामिल थी।

केतन मेहता ने फिल्म बनाते हुए उस मंगल पांडे को अपना नायक नहीं बनाया था जिसकी कुरबानी के समय भविष्य की घटनाएं काल के गर्भ में छुपी हुई थी। लेकिन उसी मंगल पांडे को राष्ट्रीय नायक बनाकर जब फिल्म में पेश किया गया तब हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली लड़ाई के इतिहास के कई अध्याय सामने आ चुके थे। एक अच्छे फिल्मकार के लिये यह मुमकिन ही नहीं था कि वह मंगल पांडे की प्रतिमा गढ़ते हुए उस इतिहास को भुला दे। मंगल पांडे की प्रतिमा इसी इतिहास के ईंट-गारे से ही बन सकती थी। लेकिन इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा इतिहास से नहीं बल्कि वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता के द्वारा ही संभव थी। *मंगल पांडे: दि राइजिंग* यदि एक ओर वर्तमान की हमारी चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में आज़ादी की पहली लड़ाई को देखने के लिये प्रेरित करती है तो दूसरी ओर यह भूमंडलीकरण के इस दौर में साम्राज्यवाद की नयी चुनौतियों के प्रति भी आगाह करती है। ❑

(लेखक जाने-माने मीडिया विशेषज्ञ और वर्तमान में नयी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मानविकी विद्यापीठ के निदेशक हैं। ई-मेल : jparakh@hotmail.com)

दस्तावेज़

हिंसा से बुराई बढ़ती है

महात्मा गांधी अहिंसा को अपना धर्म मानते थे। इसलिये असहयोग आंदोलन के दौरान हिंसा भड़कने पर उन्होंने आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। आंदोलन वापस लेने के बाद गिरफ़्तारी के लिये चले मुक़दमें में न्यायालय के समक्ष 18 मार्च, 1922 को दिया गया महात्मा गांधी का बयान इस संदर्भ में उनकी सोच का एक बिंब प्रस्तुत करता है

अहिंसा मेरे विश्वास का पहला नियम है। यही मेरे विश्वास का अंतिम नियम भी है। लेकिन मुझे अपना विकल्प तय करना है। या तो मुझे उस प्रणाली (व्यवस्था) के प्रति समर्पण करना होगा, जिसके बारे में मेरे विचार हैं कि उसने मेरे देश को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है, या फिर मुझे अपने देशवासियों के पागलपन भरे उस गुस्से को झेलना होगा जो मेरे होठों से निकले सत्य को समझने के बाद फूटेगा। मुझे पता है कि मेरे देशवासी कभी-कभी पागल-से हो जाते हैं। इसका मुझे बहुत दुख है; और मैं इसीलिये यहां उपस्थित हूं। मैं किसी हल्की सज़ा की मांग नहीं करता, बल्कि सर्वाधिक दंड चाहता हूं। मैं दया की मांग नहीं करता।

मैं यहां किसी तरह की सफ़ाई देने नहीं आया हूं। मैं यहां इसलिये आया हूं कि मैं सबसे बड़े अधिकारी के समक्ष उस काम के लिये अपने को सज़ा देने के लिये समर्पण कर सकूं जो कानून की निग़ाह में जानबूझ कर किया गया अपराध है। यह मुझे एक नागरिक के परम कर्तव्य के रूप में दिखाई देता है। अत: न्यायाधीश महोदय, जैसा कि मैं अपने बयान में कहने जा रहा हूं, आपके सामने केवल दो ही रास्ते हैं। या तो आप इस्तीफा दे दें या फिर, यदि आपको विश्वास है कि जिस व्यवस्था और प्रणाली की आप सहायता कर रहे हैं, वह लोगों के लिये अच्छी

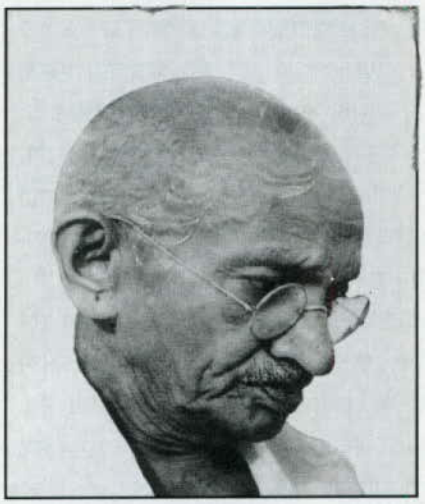

है, तो मुझे सज़ा दे दें। मैं उस तरह के परिवर्तन की आशा नहीं करता। लेकिन जब मैं अपना बयान समाप्त करूंगा, संभवत: तब तक आप को उस बात की झलक मिल जाएगी जो मेरे सीने में उबाल भर रही है और पागलपन की हद तक उस ख़तरे को उठाना चाहती है, जिससे आमतौर पर बुद्धिमान लोग बच कर निकल जाना चाहते हैं।

वास्तव में, मुझे यकीन है कि मैंने भारत और इंग्लैंड को असहयोग के रूप में उस अप्राकृतिक स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है, जिसमें दोनों ही अपने आप को पा रहे हैं। मेरी विनम्र राय में, बुराई के साथ असहयोग, उतना ही बड़ा कर्तव्य है जितना कि अच्छाई के साथ सहयोग। परंतु अतीत में, असहयोग बुराई करने वाले के प्रति जानबूझ कर हिंसा के रूप में ही अभिव्यक्त होता रहा है। मैं अपने देशवासियों को यह दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि हिंसक असहयोग से कई तरह की बुराइयां बढ़ती ही जाती हैं; और चूंकि बुराई को केवल हिंसा के बल पर कायम रखा जा सकता है, इसलिये बुराई को समर्थन न देने के लिये ज़रूरी है हिंसा से पूरी तरह दूर रहना। अहिंसा में बुराई से असहयोग के लिये दंड भुगतने के लिये अपने को समर्पण करना अंतर्निहित है।

अत: मैं यहां अपने को सर्वोच्च सत्ता को खुशी-खुशी समर्पित करता हूं और उस कार्य के लिये अधिकतम दंड की मांग करता हूं जो कानून के लिहाज़ से तो जानबूझ कर किया गया अपराध है, परंतु मुझे एक नागरिक का सर्वोत्तम कर्तव्य लगता है। न्यायाधीश महोदय और अन्य (जूरी सदस्य), यदि आपको लगता है कि जिस कानून को लागू करने के लिये आपको कहा गया है वह एक बुराई है और मैं वास्तव में निर्दोष हूं तो आप के लिये एक ही रास्ता बचा है कि आप पद से त्यागपत्र देकर अपने को उस बुराई से दूर कर लें और यदि आप समझते हैं कि जिस कानून और व्यवस्था को लागू करने में आप मदद कर रहे हैं, वह देश के लोगों के लिये अच्छी है, और इसलिये मेरा काम जनहित के लिये घातक है तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ❑

गांधी का निम्नवर्गीय चिंतन

महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रवाद का निम्नवर्गीय प्रसंग

○ रश्मि चौधरी

भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में महात्मा गांधी का आगमन एक बड़ी घटना के रूप में देखा जाता है। स्वाधीनता आंदोलन में गांधी सिर्फ़ पढ़ी-लिखी, मध्यमवर्गीय और साधन संपन्न भारतीय जनता का ही नेतृत्व नहीं करते हैं, बल्कि गांव की कृषक जनता का भी नेतृत्व करते हैं तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में उन्हें भागीदार बनाते हैं। यहां तक कि वे भारतीय समाज में व्याप्त असमानता और अस्पृश्यता का विरोध करते हुए स्वाधीनता आंदोलन में निम्नवर्गीय समाज की भूमिका को भी महत्वपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। यद्यपि गांधी के सपनों के भारत में उस समाज की तस्वीर दिखाई पड़ती है, जो गांव में रहता है तथा अपनी पारंपरिक सभ्यता, संस्कृति और स्वाधीनता बोध में एक अच्छे नागरिक का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि निम्नवर्गीय इतिहासकारों में रणजीत गुहा, ज्ञानेन्द्र पाण्डेय, शाहिद अमीन के बीच गांधी, गांधी की संस्कृति और जनता के साथ उनके संबंधों को समझने की कोशिश तो दिखाई पड़ती है, परंतु राष्ट्रवादी जन-आंदोलनों की लोकप्रिय चेतना के निर्माण की प्रक्रिया में जनकाव्य, जनसाहित्य, जनकलाओं आदि के माध्यम से राष्ट्रवाद की संरचना को समझने का प्रयास कम ही दिखाई पड़ता है, जबकि 1919 के बाद के स्वाधीनता आंदोलन में जनसाहित्य अथवा अन्य जनकलाओं के माध्यम से निर्मित जनचेतना राष्ट्रवाद को एक नया अर्थ प्रदान करती है। ज़ाहिर है, इसमें महात्मा गांधी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है क्योंकि आम जनता, उनसे सबसे अधिक प्रभावित होती है तथा जन-समाज में उनके राष्ट्रवादी आंदोलनों को लेकर अद्भुत उत्साह दिखाई पड़ता है, जिनकी तरफ जनकविताएं भी संकेत करती हैं। गांधीजी के सपनों के भारत में 'पृथ्वी पर एक ऐसे स्वर्ग' की परिकल्पना है जो न किसी का गुलाम होगा और न ही किसी पर निर्भर करेगा। *मेरे सपनों का भारत* में इस आशय को प्रकट करते हुए वह लिखते भी हैं :

"मैं ऐसे भारत के लिये कोशिश करूंगा, जिसमें उच्च और निम्न वर्गों का भेद नहीं होगा और जिसमें विविध संप्रदायों में पूरा मेलजोल होगा। ऐसे भारत में अस्पृश्यता के; या शराब और दूसरी नशीली चीज़ों के अभिशाप के लिये कोई स्थान नहीं हो सकता। उसमें स्त्रियों को वही अधिकार होंगे, जो पुरुषों को होंगे। चूंकि शेष सारी दुनिया के साथ हमारा संबंध शांति का होगा, यानी न तो हम किसी का शोषण करेंगे और न किसी के द्वारा अपना शोषण होने देंगे, इसलिये हमारी सेना छोटी-से-छोटी होगी। ऐसे सब हितों का, जिनका करोड़ों मूक लोगों के हितों से कोई विरोध नहीं है, पूरा सम्मान किया जाएगा, फिर वे हित देसी हों या विदेशी। अपने लिये तो मैं यह भी कह सकता हूं कि मैं देसी और विदेशी के फ़र्क से नफ़रत करता हूं।"

दरअसल गांधी के सपनों के भारत की वही तस्वीर है, जिसमें आम जनता की जिंदगी, उनके संघर्ष, उनकी आकांक्षाएं, शेष दुनिया के साथ उनके संबंध आदि की चेतना दिखाई पड़ती है। सबसे बड़ी बात है कि इस चेतना और जनचेतना के बीच के संबंधों को लेकर राष्ट्रवादी इतिहासकारों के राष्ट्रवाद के निर्माण की प्रक्रिया में दो तरह के विचारों को प्रकट किया है - एक 'गांधीवादी राष्ट्रवाद' जिसे निम्नवर्गीय इतिहासकार 'अभिजन राष्ट्रवाद' कहते हैं और दूसरा 'लोक अथवा जन-राष्ट्रवाद' जिसे संयुक्त प्रांत में सविनय अवज्ञा संबंधी गतिविधियों पर शोध की प्रक्रिया में ज्ञानेन्द्र पाण्डेय 'किसान राष्ट्रवाद' कहकर भी संबोधित करते हैं। 'लोक संस्कृति में राष्ट्रवाद' के इस प्रसंग में बद्रीनारायण ने एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठाया है कि अभिजन राष्ट्रवाद में क्या और किस प्रकार के अंत:संबंध रहे हैं? इनके बीच आलोचनात्मक अंत:संवाद का क्या स्वरूप है। इसके साथ ही बद्रीनारायण ने यह भी सवाल उठाया है कि दोनों (अभिजन राष्ट्रवाद और किसान राष्ट्रवाद या जन-राष्ट्रवाद) के मध्य विरोधों का सामंजस्य कैसे और कहां-कहां स्थापित हो रहा था एवं उनके बीच बातचीत की प्रक्रिया में वे कौन-सी चीजें थीं जो निर्मित और विखंडित हो रही थीं?

ये सवाल महत्वपूर्ण हैं तथा अपने शोध प्रबंध 'लोकसंस्कृति में राष्ट्रवाद' में इन सवालों पर विमर्श की प्रक्रिया में बद्रीनारायण 1920 के बाद के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, गांधी और जन-आंदोलनों के बीच के आपसी संबंधों एवं संवादों के केंद्र में लोककवि कैलाश को खड़ा करते हैं तथा उनके माध्यम से राष्ट्रवाद की संरचना पर विचार करते हैं। पर मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद की निर्मिति की प्रक्रिया को, उस दौरान रचित उन जन-कविताओं के माध्यम से और अधिक गहराई के साथ समझा जा सकता है, जो गांधी के आंदोलनों के बहाने जन-समाज के विचार और मुक्तिकामी संघर्ष को प्रस्तुत करती हैं। क्योंकि उस दौरान (1919-1947) हिंदी और उनकी बोलियों में जो जनसाहित्य रचा गया। उसका गहरा संबंध महात्मा गांधी और उनके आंदोलनों के साथ है, चाहे वह चौरीचौरा का आंदोलन हो अथवा सन् 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें जन-समाज स्वत: राष्ट्र की मुक्ति निर्माण और इस प्रक्रिया में अपने ऊपर आए संकटों का सामना करने के लिये स्वत:स्फूर्त पहल करता है। यद्यपि इस प्रक्रिया में कई बार जन-समाज हिंसा का भी सहारा लेता है जैसा कि चौरीचौरा के प्रसंग में दिखलाई पड़ता है। पर यहां सवाल समाज की अस्मिता की रक्षा का भी है जिसके समर्थन में स्थानीय समाज उठ खड़ा होता है।

यहां इस बात का उल्लेख करना भी ज़रूरी है कि इस काल (1919-1947) में रचित जनकविताओं में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की अनेक तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं, परंतु उन तस्वीरों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तस्वीर है गांधी के राष्ट्रवाद के जनरूप की पुनर्रचना और पुनर्निर्माण की अभिव्यक्ति की। इस पुनर्रचना और पुनर्निर्माण की अभिव्यक्ति में गांधी और उनकी संस्कृति तथा उनके आंदोलनों का वही रूप नहीं दिखाई पड़ता है, जिसे मुख्यधारा के इतिहासकार दिखाना चाहते हैं। इन तस्वीरों पर राष्ट्रीय नेतृत्व के समानांतर विकसित स्थानीय नेतृत्व का असर दिखाई पड़ता है जैसा कि ज्ञानेन्द्र पाण्डेय और शाहिद अमीन अपने अध्ययनों में संकेत करते हैं। कपिल कुमार भी 'किसान विद्रोह' का कांग्रेस और अंग्रेज़ी राज्य में कुछ इसी प्रकार के निष्कर्ष निकालते हैं। पर इसमें दो राय नहीं है कि यह स्थानीय नेतृत्व, कई बार स्वत:स्फूर्त दिखाई पड़ता है तो कई बार गांधी अथवा राष्ट्रीय नेतृत्व से प्रभावित। इसलिये 1919 के बाद के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की अनेक अंतर्धाराएं दिखलाई पड़ती हैं; कहीं वह निम्नवर्गीय समाज की समस्याओं को लेकर विकसित होती दिखाई पड़ती है तो कहीं मुख्यधारा के समाज के साथ संवाद करने लगती है। एक तरह से कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का यह दौर गांधी से प्रभावित होते हुए भी कई बार गांधी के अहिंसा जैसे विचारों से मुक्त दिखाई पड़ता है और आम जनता गांधी के नाम पर हिंसा भी करती है; जैसा कि चौरीचौरा की घटना में होता है और जिसकी तरफ रणजीत गुहा अपने अध्ययनों में संकेत भी करते हैं। भारतीय संस्कृति, स्वाधीनता आंदोलन, गांधी की संस्कृति और उसमें हिंसा के सवाल पर विचार करते हुए रणजीत गुहा ने लिखा है :

"हमारा राष्ट्रवादी जन-आंदोलन, हमारा जनवादी कृषक आंदोलन, हमारे प्रतिरोध के तरीके, ये सब एक विशिष्ट अर्थ में हमारे अपने हैं। मैं यह कहूंगा कि ये सारे सांस्कृतिक हैं, हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं। मेरा मानना है कि भारतीय किसान विद्रोह पर काम करके मैंने भारतीय संस्कृति में योग दिया है। मैंने सभी पूर्वग्रहों से हटकर, इतिहास लेखन के स्थापित चलन के विरुद्ध जाकर यह दिखाने का प्रयास करना चाहा कि भारत केवल अहिंसा का प्रतिनिधि नहीं है। जब सत्ता का सवाल आता है तो वह हिंसा का भी प्रतिनिधित्व करता है। हिंसा हमारी संस्कृति का उतना ही महत्वपूर्ण भाग है जितना कि अहिंसा, धर्म आदि। एक सतही आलोचक किसान विद्रोह पर मेरे काम का अध्ययन एक स्तरीय इतिहास लेखन के रूप में करता है। मगर यह भारतीय संस्कृति पर किया गया काम है। मैंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि भारतीय संस्कृति विषम तत्वों से युक्त है। गांधी उसका हिस्सा हैं एक महत्वपूर्ण हिस्सा, मगर सब कुछ नहीं हैं। हमारी संस्कृति में गांधी की प्राथमिकता का दावा करना अत्यंत संदेहास्पद है। मुझे लगता है कि यह समझने के लिये अभी हम पर्याप्त समझदार नहीं हो पाए हैं, पर एक दिन यह सब ज़रूर समझेंगे। हमारी संस्कृति में हिंसा की मौजूदगी ही दलितों से संबंधित हिंसा के लिये जिम्मेदार है क्योंकि स्थापित संहिता का उल्लंघन करने पर हमेशा दंडित किया जाता है।"

निस्संदेह भारतीय संस्कृति में हिंसा और गांधी की संस्कृति में हिंसा की संभावनाओं पर विचार करते हुए रणजीत गुहा ने जिन सवालों को उठाया है वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 1919 के बाद के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रदर्शन और विरोध के दौरान अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां हिंसा होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हिंसा वे लोग करते हैं जो गांधी के प्रभाव में थे और आम जनता जब हिंसा करती है तब क्या गांधी उसकी आलोचना करते हैं? कहना न होगा कि इन्हीं सब सवालों पर विचार करते हुए रणजीत गुहा भारतीय संस्कृति के विषम तत्वों की तरफ संकेत करते हैं और गांधी के अहिंसा संबंधी विचार को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। मुझे लगता है इन सवालों को समझने में जनसाहित्य में मौजूद ऐतिहासिक घटनाएं मदद कर सकती हैं। कारण, इस प्रकार के

जनसाहित्य गांधी और आम जनता के बीच के संबंध को नहीं दिखलाते हैं, बल्कि अंग्रेज़ों के दमन और शोषण का प्रतिकार भी करते हैं। इसलिये 1919 के बाद के भारतीय राष्ट्रवाद को समझने में साहित्य की यह धारा एक महत्वपूर्ण उपादान हो सकती है क्योंकि इनमें एक तरफ जहां गांधी के राष्ट्रवाद का जनरूप दिखलाई पड़ता है वहीं दूसरी तरफ साम्राज्यवादी छल के खिलाफ़ सामान्य जन के प्रतिरोध और गुलामी से मुक्त राष्ट्र का पुनर्निर्माण भी दिखलाई पड़ता है।

1919 से 1947 के बीच खड़ी बोली हिंदी और भोजपुरी में जो जनकविताएं लिखी गई, उनके माध्यम से राष्ट्रवाद की न समग्र निर्मितियों पर विचार करें जो गांधी और उनकी संस्कृति के माध्यम से जनता के मन में बनती हैं। दूसरी बात, इस दौरान अनेक ऐसी जनकविताएं भी लिखी गईं, जिनमें गांधी की उपस्थिति नहीं के बराबर है और यदि कहीं वह है भी तो उसमें उनकी 'अहिंसावादी' छवि नहीं है। कई जगह तो गांधी हैं ही नहीं; चाहे वह 1919 की जलियांवाला बाग पर केंद्रित जनकविताएं हों अथवा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कविताएं। यहां जनता की राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी और उसमें मन में स्थित 'राष्ट्र' एवं 'राष्ट्रवाद' की छवि को जनकवियों ने रचना का केंद्र बनाया है। इस बात का अध्ययन करना मुझे ज़रूरी लगता है क्योंकि जनकाव्य के माध्यम से अभी तक इस प्रकार के प्रयास नहीं के बराबर हुए हैं। यहां यह देखना भी आवश्यक लगता है कि गांधीवादी राष्ट्रवाद से जन-राष्ट्रवाद के संबंध का स्वरूप क्या और कैसा है तथा तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ने वाले प्रभावों के विश्लेषण में जनकाव्य कहां तक मददगार हो सकते हैं।

गांधी के राष्ट्रवाद का जनरूप

दरअसल राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में जिस समय मोहनदास करमचंद गांधी का आगमन होता है, उस समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ़ बालगंगाधर तिलक और ऐनी बेसेंट जैसे राष्ट्रवादी नेताओं का होमरूल आंदोलन (1916) ज़ोरों पर था। इस आंदोलन में मुख्यत: बुद्धिजीवी और देश के पढ़े-लिखे मध्यमवर्गीय लोग ही शामिल थे। आम जनता की हिस्सेदारी इस आंदोलन में नहीं के बराबर दिखाई पड़ती है। यद्यपि सेनफ्रांसिस्को से प्रकाशित *देशभक्ति के गीत* (1916) से पता चलता है कि आम जनता के अंदर राष्ट्रीयता के विकास में राष्ट्रवादी गतिविधियों सहित जनकविताओं की भी एक बड़ी भूमिका थी, परंतु आम जनता को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ने वाली कोई ऐसी सतत प्रक्रिया नहीं दिखाई पड़ती है जो संघर्ष को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा सके। 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना, 1917 में बिहार के चंपारण के नील की खेती करने वाले मज़दूरों की समस्याओं से जूझने, 1918 में खेड़ा के किसानों द्वारा सूखे के कारण लगान न दे पाने की विवशता के कारण किया गया सत्याग्रह एवं 1918 में ही अहमदाबाद के कपड़ा मज़दूरों की समस्याओं के समाधान के लिये गांधी द्वारा किए गए प्रयासों का आम जनता के ऊपर काफी गहरा असर पड़ा तथा लोगों को लगा कि उनको सुनने और समझने वाला कोई आ गया है। इन आंदोलनों में महत्वपूर्ण बात यह उभरकर सामने आती है कि गांधी की छवि एक ऐसे नेता एवं मनुष्य के रूप में बनने लगती है जो लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुनता है और उनके समाधान के लिये बिना किसी छिपाव एवं दुराव के प्रयास करता है। वह जो भी गतिविधियां शुरू करना चाहता है, उनका निर्णय अचानक नहीं लेता है। बल्कि लोगों के साथ विचार-विमर्श करके संघर्ष का रास्ता तय करता है और जन-आंदोलन को सीधा देश के गली-कूचों में ले जाता है। क्योंकि गांधीजी का विचार था, 'जब तक देश के लाखों-लाख निवासी, सचेत रूप से इस स्वाधीनता संग्राम से नहीं जुड़ते तब तक यह स्वाधीनता संग्राम आगे नहीं बढ़ सकता।' कथाकार भीष्म साहनी ने लिखा है :

"गांधीजी के स्वाधीनता संग्राम की सारी परिकल्पना ही नयी और अनूठी थी। उनका विश्वास शस्त्रास्त्रों में नहीं था। वह अहिंसात्मक ढंग से लड़ाई लड़ने के हक़ में थे। इस संघर्ष में हिंसा का प्रयोग कदापि न हो, देशभक्त भले ही स्वयं यातनाएं झेलें, पर विरोधी पर हमला नहीं करें, बल्कि अपनी कुर्बानी द्वारा उसे इस बात का यकीन दिलाएं कि विरोधी का व्यवहार अन्यायपूर्ण है। वह विरोधी का हृदय परिवर्तन करने में विश्वास रखते थे। गांधी का विश्वास आत्मबल में था - एक ओर जहां वह ब्रिटिश सरकार के कानून भी नहीं मानना चाहते थे और उनका डटकर विरोध करते थे, दूसरी ओर वह किसी प्रकार की हिंसा का प्रयोग भी नहीं करना चाहते थे।"

स्पष्टत: राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में गांधी की यह वही संघर्ष की संस्कृति है जिसकी तरफ रणजीत गुहा संकेत करते हैं। क्योंकि संघर्ष की इस संस्कृति में जिस जन-राष्ट्रवाद की निर्मिति होती है उसके केंद्र में जन-आंदोलन, जनवादी कृषक-आंदोलन और प्रतिरोध के अहिंसात्मक तरीके शामिल हैं। इस संघर्ष में गांधी के साथ जो आम जनता शामिल होती है उसमें गांव के लोगों की संख्या सबसे अधिक है तथा वह गांधी के संघर्ष में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करती है। गांधी के संघर्ष के इस स्वरूप की चर्चा करते हुए सुमित सरकार ने लिखा है :

"कुल मिलाकर, जैसाकि हम देखेंगे, गांधीजी एवं गांधीवादी कांग्रेस ने जिस

अनिवार्यत: एकताकारी और 'छतरी' वाली भूमिका को अपनाया था, उसके केंद्र में अहिंसा का ही सिद्धांत था। इस भूमिका के तत्व थे - आंतरिक, सामाजिक संघर्षों में मध्यस्थता करना, विदेशी शासन के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ा योगदान करना, किंतु साथ ही जिसमें कभी-कभी पीछे भी हटना पड़ता था, और जिसके फलस्वरूप कभी-कभी बड़े भारी धक्के भी लगते थे।"

यहां सुमित सरकार गांधी के अहिंसा संबंधी सिद्धांतों को केंद्र में रखते हुए आम जनता के साथ उनके संबंधों का बयान करते हैं। वह इस बात की तरफ भी संकेत करते हैं कि गांधी के इस अहिंसावाद में आम जनता मध्यमार्ग अपनाती है तथा इसलिये कई बार विदेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में उसे पीछे भी हटना पड़ता है। यहां इस बात पर विचार करना ज़रूरी है कि गांधी के इस अहिंसावाद की मुख्य कार्यशैली क्या है तथा जनता के मन में उस कार्यशैली के प्रति किस प्रकार के विचार थे? दूसरी बात, यहां पर यह भी देखना ज़रूरी है कि इस दौरान रचित जनकाव्य में इस अहिंसा की छवि क्या है तथा आम जनता किस प्रकार उस छवि के सहारे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में भाग लेती है तथा इस प्रकार वह एक नये प्रकार के 'राष्ट्रवाद' को निर्मित करती है। क्योंकि 1920 से 1922 के बीच के असहयोग आंदोलन अथवा बाद में भी गांधी, राष्ट्रीय आंदोलन में अहिंसा को एक मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। खासकर, वह जनता को भी अपनी अपीलों द्वारा इस बात के लिये तैयार करते हैं कि जब तक ब्रिटिश शासन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करती है, तब तक जनता को ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा संचालित सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं का बहिष्कार करना चाहिए क्योंकि यदि इस प्रकार की संस्थाएं अगर जनता की मुश्किलों को दूर नहीं करती हैं, उनके साथ ख़राब व्यवहार करती हैं तो उनके साथ असहयोग करना ही 'सक्रिय स्थिति' है। 1919 से 1922 और उसके बाद के राष्ट्रीय आंदोलनों में गांधी असहयोग और अहिंसा को 'सक्रिय स्थिति' मानते हुए उनके माध्यम से राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का एक नया इतिहास रचते हैं। यह गांधी की वही गतिशील चेतना है जो उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के निम्नवर्गीय प्रसंगों से जोड़ती है। कहना न होगा कि गांधी के राष्ट्रवाद के निम्नवर्गीय प्रसंग की अवधारणाओं को लेकर इतिहासकारों के बीच अब भी भिन्न-भिन्न तरह के मत हैं। परंतु रणजीत गुहा, शाहिद अमीन और ज्ञानेन्द्र पाण्डेय जैसे इतिहासकारों का यह स्पष्टत: मानना है कि गांधी और उनके आंदोलनों में किसानों की भागीदारी राष्ट्रवाद की दुनिया का विस्तार करती है। यह एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर अब नये इतिहासकारों का ध्यान जा रहा है। ❑

(लेखिका रंगश्री नामक एनजीओ की अकादमिक संयोजक हैं।
ई-मेल: rashmichoubey@hotmail.com)

IAS/PCS JRF/NET
संवाद
... The Achievers
हिन्दी साहित्य
कुमार "अजेय"
(B.P.S.C. Topper)
सफलता का प्रतिमान :
UPSC : अभिषेक, अशोक कुमार, सुनील अग्रवाल, संजय कुमार ....
UPPCS : श्रवण कुमार यादव, राकेश कुमार, मनोज सिंह ....
BPSC : राजेश कुमार, बालमुकुन्द यादव, (Dy. Coll.)
रवीश कुमार (Dy. Sp.), कामेश्वर ठाकुर (DAO)
R.P.S.C : सुरेश कु. मीणा
U.P.S.C. में औसत प्राप्त अंक
182 + 171 = 353
173 + 169 = 342
167 + 165 = 332
विशिष्ट पहलू :
1. भाषा खंड एवं व्याख्या की विशेष कक्षा
अन्य विषय : सा॰ अध्ययन, निबन्ध साक्षात्कार, सा॰ हिन्दी भूगोल, Law
2. उत्तर लेखन की वैज्ञानिक प्रविधि (चार्ट, सारणी, आदि) : 350+अंक
3. गुणवत्ता विकास (Quality Improvement)/लेखन सुधार हेतु विशेष कक्षा
4. विगत एवं संभावित 200 प्रश्नों के उत्तर प्रारुप पर विशेष कक्षायें
5. राज्य लोक सेवा आयोगों के पाठ्यक्रम का भी अध्यापन (नि:शुल्क)
6. परिष्कृत अध्ययन सामग्री (I.A.S./PCS/JRF/NET)+मॉडल प्रश्नोत्तर प्रारुप
कक्षा समय/कार्यक्रम
व्याख्या एवं भाषा खंड की विशेष कक्षाएँ
टेस्ट सिरीज़ 272 → 353 अंक
प्रत्येक शनिवार
क्रैश कोर्स
निबंध : विशेष सत्र + मॉडल प्रारूप ⇒ (110 + अंक) प्रत्येक रविवार
FOR WORKING STUDENTS CLASSES ON SAT. & SUN.)
नया बैच प्रारंभ (2008-09)
सामान्य अध्ययन (P.T. और मुख्य)
पत्राचार पाठ्यक्रम :
हिन्दी साहित्य, सा॰ अध्ययन, निबंध, भूगोल, सा॰ हिन्दी
B-10, तृतीय तल, (Above महाराष्ट्र बैंक) मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
9213162103, 9891360366
सफलता का मानक सफल शिक्षक के मार्गदर्शन में ही संभव है।
YH-10/07/8

कश्मीर का वास्ता

○ संजय शर्मा

वर्तमान भारत-पाक शांति प्रयास, पुंछ-रावलकोट मार्ग का खोला जाना, 2005 के भूकंप के दौरान सेना की मदद और इसी तरह के कुछ अन्य सकारात्मक घटनाएं, इस बात की ओर इशारा करती हैं कि जम्मू-कश्मीर के अवाम ने आतंकवाद को पूरी तरह से नकार दिया है। शांति और विकास के लिये उनकी तड़प का यह एक जीता-जागता प्रमाण है। सेना आमतौर पर, और रोमियो फोर्स खासतौर पर क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाती आई है। आतंकवाद विरोधी अभियानों में पारदर्शिता बरतते हुए वे अर्थपूर्ण विकास प्रयासों का लक्ष्य निर्धारित

कर रहे हैं। इससे क्षेत्र में शांति की तमन्ना रखने वाले लोगों को बल मिला है।

उपर्युक्त लक्ष्यों को हासिल करने के पीछे बड़ी कड़ी मेहनत लगी है। सद्भावना अभियान के तहत शुरू की गई आम जनता की हितैषी विकास परियोजनाओं से सेना का मानवीय चेहरा झलकता है। अतीत में आतंकवाद से भयावह रूप से ग्रस्त लोगों का जीवन धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगा है। क्षेत्र में शांति के लाभ दिखाई देने लगे हैं। मखमली दस्तानों में छिपी फौलादी मुट्ठी के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, नारी सशक्तीकरण, पनबिजली और सौर ऊर्जा परियोजनाओं में सुधार के लिये 2 करोड़ 16 लाख की लागत से सद्भावना अभियान के दोहरे प्रयासों से सेना के प्रति स्थानीय लोगों के रवैये में स्पष्ट बदलाव आया है। आतंकवादियों का विरोध करने का साहस लोगों में बढ़ने लगा है, और अब स्थानीय लोग आतंकवादियों के ठिकानों और उनकी चालों के बारे में जानकारी देने के लिये आगे आने लगे हैं। आतंकवादी भी अब सुरक्षात्मक खेल खेलने लगे हैं तथा सीधे सेना से भिड़ने से बचते हैं। इन सब कारणों से सामान्य स्थिति की बहाली का माहौल बना है जिससे नागरिक-प्रशासन को काम करने का मौका मिला है। वे अनेक शिक्षा संस्थाएं, सरकारी कार्यालय, औषधालय और बाज़ार, चाहे वे दूरदराज़ के गांवों में हों या शहरों में, जहां कभी वीरानी छाई रहती थी, उनमें काम-काज़ ज़ोर पकड़ने लगा है।

नागरिक प्रशासन जो आतंकवाद के कारण पंगु-सा हो गया था, अब प्रभावी ढंग से दक्षतापूर्वक काम कर रहा है। महिलाओं सहित अधिकाधिक लोग अब ग्राम रक्षा समितियों से जुड़ना चाहते हैं और

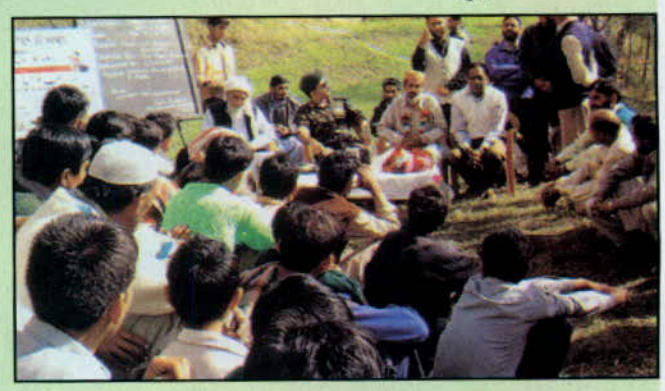

अपनी रक्षा के लिये हथियार चलाना सीखना चाहते हैं। इन दोनों जिलों में इस समय 10 ग्राम रक्षा समितियां काम कर रही हैं। अवाम में विकास के मुद्दों के प्रति जागृति आई है और वे सरकार और सेना की ओर से शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक उद्धार के क्षेत्र में दिए जा रहे अवसरों का लाभ उठाने के लिये आगे आ रहे हैं। ❑

घाटी में हलचल
कश्मीर में संगीत की बहार

कश्मीर अब एक नवीन संगीत से गुंजायमान हो रहा है और वहां के युवा अब रॉक म्यूजिक, पश्चिमी लोकप्रिय संगीत की दुनिया में सराबोर हो रहे हैं। युवा कश्मीरी डॉक्टर अमित वांचू ने, बरसों से हिंसा में डूबे और मनोरंजन से महरूम कश्मीर में राहत की दरिया बहाने की गरज से एक 'रॉक बैंड' शुरू किया है। पांच सदस्यों वाले 'इमर्शन' नाम के इस बैंड में एक महिला भी है। 'इमर्शन' का कहना है कि उसके संगीत का उद्देश्य युवा कश्मीरियों के ज़ख्मों और दर्द को मिटाना है। अमित कहते हैं कि "उन्होंने बहुत कुछ सहा है और वे मनोरंजन के लिये तरस रहे हैं।" अमित जो स्वयं इस बैंड के गीतकार भी हैं, कहते हैं कि "हम उनके ज़ख्मों को भरने की कोशिश कर रहे हैं।" वे कहते हैं कि हम गिटार, ड्रम्स और की बोर्ड की ध्वनियों के इर्द-गिर्द प्रेम और शांति की धुन की दुनिया बुनना चाहते हैं और इसे लोगों का सहयोग मिला है। हमारे कार्यक्रमों में युवाओं की भीड़ उमड़ रही है।"

मदर इंडिया... *श्रीनगर के बाहरी इलाके में स्थित एक सैन्य परिसर में जन्म-कश्मीर लाईट इंफैंट्री के जवानों के पासिंग आउट परेड में अपने बेटे को चूमती मां*

इमर्शन की महिला कलाकार महमीत सैयद कहती हैं कि "बैंड ने यतीमों, ग़रीबों और बीमारों की मदद और मनोरंजन के लिये भी कार्यक्रम किए हैं।"

दुख और दर्द का हरेक शब्द अमित के परिवार के रक्त से सराबोर है। उसके पिता एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे, 1992 में आतंकवादियों के हाथों वह मारे गए थे। अमित कहते हैं कि "लाखों कश्मीरी मनोवैज्ञानिक रोग और मानसिक दबावों से ग्रस्त हैं, लेकिन उन्हें दवाओं और गोलियों की ज़रूरत नहीं है। वे मानसिक मनोरंजन चाहते हैं। ❑

सदियों पहले चीन पहुंची कश्मीरी कला

चीन की गुफाओं में मौजूद कुछ पेंटिंगों पर कश्मीर कलाकारों की छाप साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिससे पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत और चीन के बीच संस्कृति, कला और धर्म के क्षेत्र में नजदीकी संबंध रहे हैं। हाल ही में उत्तरी सिल्क रूट पर चीन और तिब्बत के मुख्य सांस्कृतिक स्थलों की फोटोग्राफी करके लौटे जानेमाने कला इतिहासकार और फिल्ममेकार विनय के बहल ने यह बात कही है।

बहल ने बताया कि मैंने इस बात को बखूबी पहचाना कि तुनहुआंग की मोकाओ गुफाओं की कुछ पेंटिंगों पर कश्मीरी कलाकारों का विशेष प्रभाव है। ये गुफा चीन की मशहूर बौद्ध कला का प्रतीक हैं। बहल एशियाई देशों में बौद्ध और हिंदू कला पर व्यापक शोध करने के लिये जाने जाते हैं। उन्होंने सिल्क रूट पर 14 हज़ार किलोमीटर में फैले 34 अहम सांस्कृतिक स्थलों के फोटो लिये। उन्होंने कहा कि किजी की गुफाओं में बहुत-सी अनमोल पेंटिंगें हैं, जो भारतीय कला शैली से नज़दीकी तौर पर जुड़ी हैं। साफ है कि भारत और चीन के बीच प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक, कलात्मक और धार्मिक आदान-प्रदान वाले काफी गहरे रिश्ते रहे हैं। वह बताते हैं कि चौथी सदी में कुमारजीवा चीन में बुद्ध धर्म की शायद सबसे महान हस्ती थी। कुमारजीवा भारतीय थे। उन्हें बहुत कम उम्र में ही बुद्ध धर्म और संस्कृत का अध्ययन करने कश्मीर भेज दिया गया था। जब वह लौटे तो अपने अनुवादों के जरिये बहुत नाम कमाया।

बहल इससे पहले जापान, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमा, श्रीलंका, भूटान और नेपाल की शुरुआती कलाओं पर रिसर्च कर चुके हैं। अनुमान है कि वह 2006 तक दुनिया के अलग-अलग देशों में एक लाख 60 हज़ार किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। उन्होंने 26 फिल्में भारतीय पेंटिंगों पर और 26 फिल्में भारतीय मूर्तिकला पर बनाई हैं। तिब्बत के बारे में बहल कहते हैं कि इस देश के कला इतिहास को समझने के लिये हमें बहुत-सी जगहें मिली। हमने वहां भारतीय कलाकारों के काम को देखा। ❑

हरी झंडी... दक्षिण कश्मीर के बड़गाम से काकापोरा के बीच रेलगाड़ी के पहले परीक्षण चालन को आगे बढ़ने का संकेत देता रेलकर्मी। इस साल के अंत तक कश्मीर में पहली रेलगाड़ी दौड़ने लगेगी

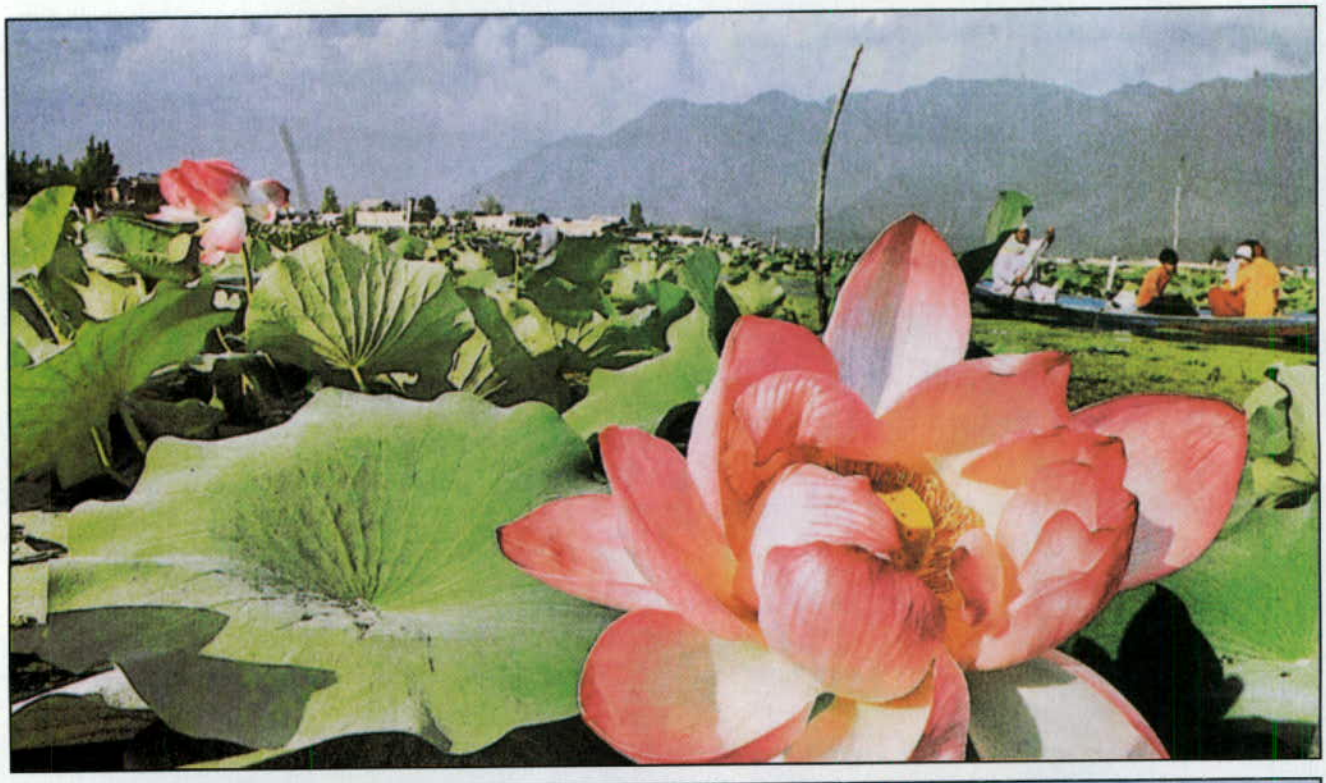

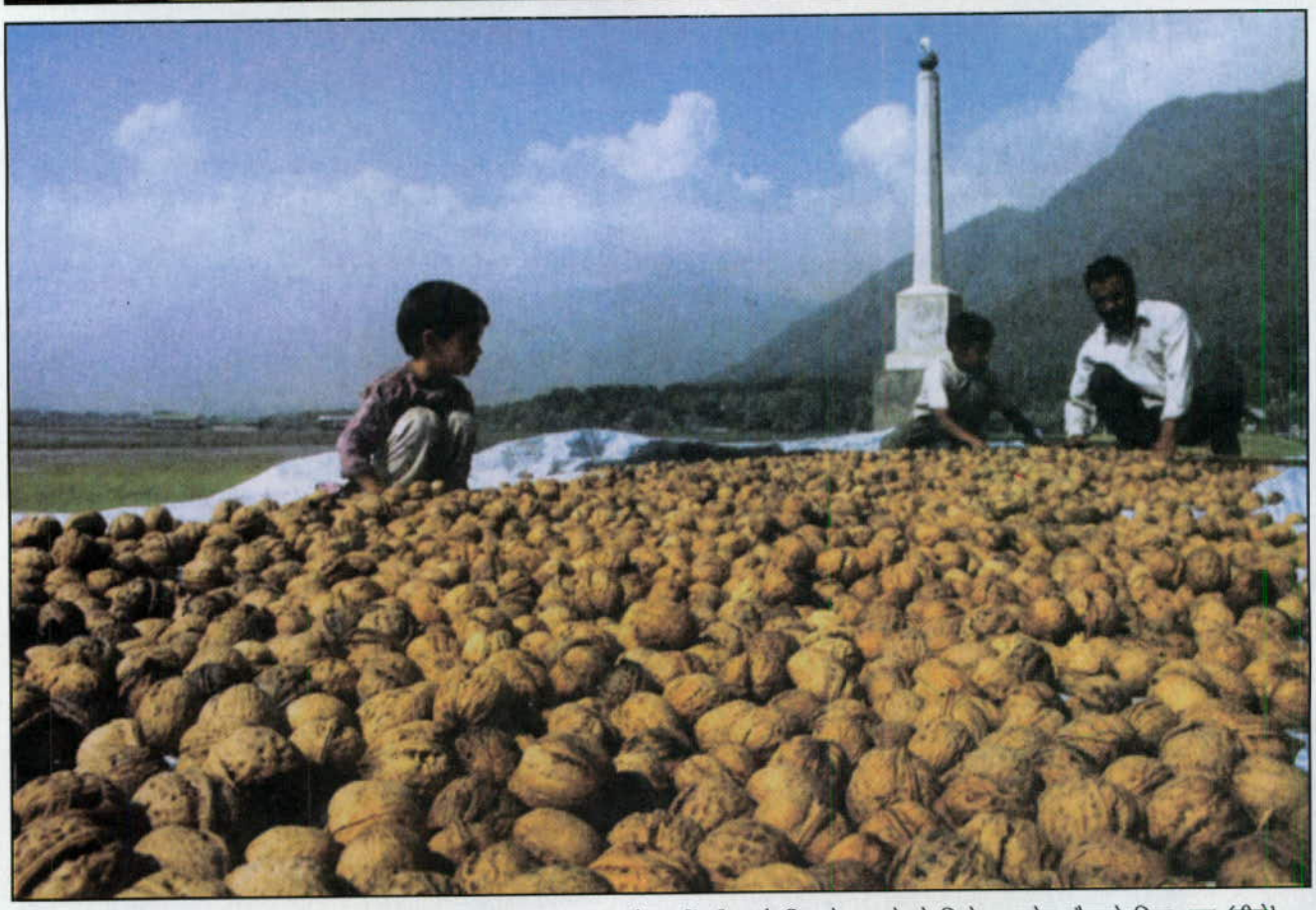

श्रीनगर के डल झील में खिले कमल के मनमोहक फूल (ऊपर) और वहीं झील के किनारे सुखने के लिये अखरोट फैलाते पिता–पुत्र (नीचे)

आत्मनिर्भरता के बीज

○ अनीता पैलूर

मालनाड गृह वाटिका और बीज आदान–प्रदान कार्यक्रम ने कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में गृह वाटिका की अवधारणा को एक विस्तृत फलक प्रदान किया है। यहां लगाई गई हरी गृह वाटिकाओं ने जैव विविधता के संरक्षण में मदद की है और अपने मालिकों को जीविकोपार्जन का साधन भी उपलब्ध कराया है

गृह वाटिकाएं कर्नाटक के मालनाड इलाके की महिलाओं के लिये कोई नयी बात नहीं है। हर क्षेत्र की तरह उनके भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने तौर-तरीके हैं। हर मौसम में वहां उत्पादकता और उपयोगिता के हिसाब से उगाई जाने वाली सब्जियों की विविधता बदल जाती है। शाक वाटिकाओं में सब्ज़ियां, औषधीय पौधे और फलों वाले पेड़ होते हैं। इस जिले में मौजूद घने जंगलों ने भी यहां के सुरुचिपूर्ण खान-पान के तरीकों में योगदान किया है। यहां की महिलाओं ने आपस में समझौता किया हुआ है जिससे आदान-प्रदान के जरिये उन्होंने सब्जी बाज़ार पर आत्मनिर्भरता कम कर ली है।

"इन छोटे बीजों ने हमारे परिवार की आजीविका बढ़ा दी है। मात्र एक मुट्ठी बीज पूरे समुदाय का काम चला सकते हैं। वे जो कुछ दिखते हैं उससे काफी ज्यादा महत्व के होते हैं। इसीलिये मैं खुद अपने इस्तेमाल और बिक्री के लिये सब्जियां उगाती हूं।" यह कहना है उत्तर कन्नड़ जिले की सिरसी की रहने वाली गंगा मोहन चन्नैया का जो अपने ही तरीके से जैव-विविधता का संरक्षण कर रही हैं। उनकी अनेक पड़ोसिनें भी यही करती हैं। उनका ख्याल है कि अधिक बीज विविधता से गांवों का भविष्य बेहतर होगा। ये महिलाएं मालनाड गृह वाटिका एवं बीज आदान-प्रदान कार्यक्रम नेटवर्क से जुड़ी हैं।

गंगा के पास लगभग एक एकड़ ज़मीन होगी। वह पिछले 25 वर्षों से बीज उगा रही है। वह घूम-घूम कर सब्जी बेचती है। उसने खेतिहर मज़दूर का काम इसीलिये छोड़ दिया था ताकि वह सब्जी के बग़ीचे में अधिक समय लगा सके। वह सालभर में पांच क्विंटल सब्जी बेच लेती है। उसने कहा कि मालनाड गृह वाटिका नेटवर्क से उसे नैतिक सहायता मिली है और उसकी आमदनी बढ़ गई है।

इस सामुदायिक योजना का शुभारंभ 2001 में हुआ था। इसका उद्देश्य मालनाड और तटीय कर्नाटक के अन्य भागों में सब्जी बग़ीचा आंदोलन को बढ़ावा देना है। यह संगठन कर्नाटक को गृहवाटिकाओं में मिलने वाली जैव विविधता को लिपिबद्ध करना चाहता है। इससे क्षेत्र में वह विविध प्रकार की सब्जियों के बीजों का आदान-प्रदान कर सकेगा।

यहां की महिलाओं का कहना है कि सब्जियों से होने वाली उनकी आमदनी कुल आय की 15 से 20 प्रतिशत तक बैठती है। उत्तर कन्नड़ जिले की यल्लापुर के पास रहने वाली एक आदिवासी महिला सुगंधा गवाड़े के अनुसार, सब्जियां उगाने से सिर्फ़ आमदनी ही नहीं बढ़ती, बल्कि परिवार की तंदुरुस्ती भी ठीक रहती है। जैसे-जैसे सब्जी की खेती वाला क्षेत्रफल बढ़ता है, अनेक लोगों ने पानी की बचत भी शुरू कर दी है। सब्जी के बग़ीचे का चलन बढ़ने से अनेक क्षेत्रों में नालियां और तालाब बनाए गए हैं जिनसे पानी का समुचित इस्तेमाल हो पाता है।

इसके कारण वित्तीय आत्मनिर्भरता और परिवार में हैसियत बढ़ी है। जैसा कि सुगंधा का कहना है उन्होंने समझ लिया है कि बीज आत्मनिर्भरता के आधार हैं।

इन्हीं गतिविधियों के विस्तार के रूप में मनोरमा जोशी जैसी महिलाओं ने पापड़, अचार, सूखे केले, कोकम, घी और पिसी हल्दी जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने शुरू कर दिए हैं। ये सभी पदार्थ मिलावट रहित होते हैं। इसीलिये व्यापार मेलों जैसे अवसरों पर ये हाथों-हाथ बिक जाते हैं। पिछले कई वर्षों से उन्होंने प्राकृतिक रंग बनाने शुरू कर दिए हैं जिनकी होली पर बहुत मांग होती है। ❑

(लेखिका नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया से संबद्ध हैं।
ई-मेल: anitapailoor@gmail.com)

किसानों के हित में जारी।

सावधान !

कृषक सुनें यह संदेश

शुद्ध कीटनाशक, उचित मात्रा, खुशहाल देश

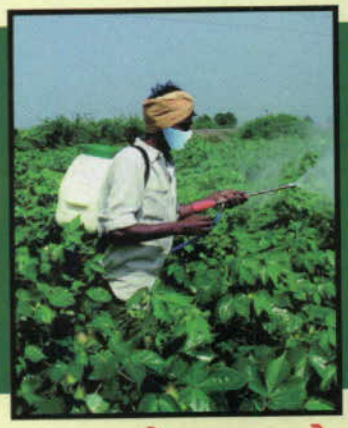

सावधान हो सुनें किसान
कीटनाशक की करें पहचान
जिसकी शुद्धता का हो ज्ञान
करें प्रयोग उसे, रोके जो कीड़ों से नुकसान

जागो किसान जागो !

कीटनाशक/रोगनाशक फ़सलों की पैदावार बढ़ाने में सहायक है।
लेकिन दवा खरीदने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

1. दवा खरीदने से पहले कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें। इसके लिए स्थानीय कृषि कार्यालय व कृषि अधिकारी से सम्पर्क करें।
2. उत्पाद पंजीकृत डीलर से ही खरीदें।
3. दवा सील बंद, मूल पैकिंग में ही खरीदें। पैकिंग की सील टूटी हो अथवा छेड़छाड़ की गई हो, तो उसे न खरीदें।
4. पैकिंग पर निर्माता कम्पनी का नाम व पूरा पता लिखा होना चाहिए।
5. उत्पाद को खरीदते समय, नकद रसीद अवश्य लें जिसमें डीलर का नाम, दवा का नाम, बैच नं०, निर्माण की तिथि (लाइसैंस, सेल टेक्स नं० आदि) साफ साफ छपे हों।
6. पैकिंग पर निर्माण व इस्तेमाल की अंतिम तिथि, प्रयोग की विधि, प्रयोग हेतु मात्रा इत्यादि का समुचित उल्लेख हो।
7. नकद रसीद पर डीलर / विक्रेता के हस्ताक्षर व मुहर अवश्य होनी चाहिए।
8. यदि दुकानदार / डीलर उपरोक्त अनुसार दवा न दें तो तुरन्त कृषि विभाग से इसकी शिकायत करें।

सत्यमेव जयते

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी

अधिक जानकारी के लिए निकटतम केन्द्रीय एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन केन्द्र, राज्य सरकार के कृषि विभाग अथवा **किसान काल सेंटर फोन नं० 1551** पर सम्पर्क करें।

dcvp 01101/13/0034/0708

YH-10/07/16

समान अवसर आयोग के गठन का फैसला किया सरकार ने

मुसलमानों की स्थिति की पड़ताल करने के लिये बनी राजेंद्र सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशों पर अमल के बारे में रपट पेश करते हुए सरकार ने मुसलमानों के साथ भेदभाव की शिकायतों पर गौर करने के लिये समान अवसर आयोग के सैद्धांतिक गठन का फैसला करने की घोषणा की है। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा व सरकारी नौकरियों में मुलसमानों के कम प्रतिनिधित्व की कमेटी की चिंताओं को दूर करने के लिये परिसीमन कानून की समीक्षा करने और सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने का निर्देश दिया है।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री अब्दुल रहमान अंतुले ने लोकसभा में सच्चर समिति की सिफ़ारिशों पर अमल के लिये सरकार की ओर से उठाए गए विभिन्न कदमों का ब्यौरा देने वाले अपने बयान को सदन के पटल पर रखा। बयान में कहा गया है कि परिसीमन अधिनियम की समीक्षा करने के लिये एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है और मुसलमानों के प्रतिनिधित्व में विसंगतियों के संबंध में सच्चर समिति की ओर से व्यक्त की गई चिंताओं पर समिति द्वारा विचार किया गया है।

सच्चर समिति की सिफ़ारिशों पर उठाए गए कदम

- लोकसभा के पटल पर रखी गई सच्चर समिति की सिफ़ारिशों पर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत किया गया है।
- संसद और विधानसभाओं में मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व में मौजूदा विसंगतियों को दूर करने के लिये उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया। यह समिति परिसीमन अधिनियम की समीक्षा करेगी।
- समान अवसर आयोग के गठन की दिशा में काम शुरू।
- सरकारी सार्वजनिक उद्यमों और बैंकों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के दिशानिर्देश जारी।
- देश के 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में समग्र विकास के लिये होगा लक्षित हस्तक्षेप।
- अल्पसंख्यक जनसंख्या के घनत्व वाले 338 नगरों/शहरों की लिये विशेष योजना पर अंतरमंत्रालयी कार्यबल।
- अल्पसंख्यकों को सरलता से ऋण उपलब्ध हो - इसके लिये भी एक अंतर मंत्रालयी समूह कर रहा है विचार-मंत्रणा।
- मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये एक बहुआयामी कार्यनीति।
- अल्पसंख्यकों के लिये तीन नयी छात्रवृत्ति योजनाओं का प्रस्ताव।
- वक्फ़ कानून में होगा जल्द संशोधन।
- अल्पसंख्यकों के मद्देनज़र बनेगा राष्ट्रीय डेटा बैंक और एक स्वायत्त मूल्यांकन एवं निगरानी प्राधिकरण।

श्री अंतुले ने इस बयान को एक ऐतिहासिक अवसर बताते हुए यह भी कहा कि सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों आदि में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिये पहले ही दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

श्री अंतुले ने कहा कि मुसलमानों के साथ भेदभाव संबंधी शिकायतों को देखने के लिये एक समान अवसर आयोग के गठन का भी सिद्धांत रूप से निर्णय किया गया है। उन्होंने बताया कि शिनाख्त किए गए 90 अल्पसंख्यक बहुल जिले, जो विकासात्मक मानदंडों पर पिछड़े हैं, उनमें मूलभूत सुविधाओं और आर्थिक सुविधाओं में सुधार के लिये विशेष प्रयास किए जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बहुल 338 नगरों और शहरों में नागरिक सुविधाएं और आर्थिक अवसरों में कमी में सुधार करने के लिये समुचित उपाय किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि मुसलमानों की बहुलता वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिक शाखाएं खोलेंगे जिससे वित्तीय संस्थाएं अल्पसंख्यकों में, विशेषकर महिलाओं में, माइक्रो वित्त को बढ़ावा देंगी। ❑

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का स्वास्थ्य बीमा दो अक्तूबर से

सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना दो अक्तूबर से लागू की जाएगी। सूचना प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी ने बताया कि दो अक्तूबर से स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी। इससे असंगठित क्षेत्र में ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाले श्रमिकों और परिवारों को फायदा मिलेगा। इस योजना के लाभार्थियों को पहचान के लिये स्मार्ट कार्ड ज़ारी किया जाएगा। दासमुंशी ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने असंगठित क्षेत्र और श्रमिक सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2007 को संसद के मौजूदा सत्र में पेश करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने प्रवासी रोज़गार संवर्धन परिषद के गठन के सरकार के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। यह परिषद विश्व के श्रम बाज़ार में रोज़गार की संभावनाओं का अध्ययन निगरानी, अनुसंधान और विश्लेषण करेगी।

सूचना प्रसारण मंत्री ने बताया कि सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति को 11वीं योजना के दौरान भी ज़ारी रखने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि मैट्रिक के बाद की सभी उच्च शिक्षाओं में दाखिला पाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिलेगी। सरकारी कॉलेजों के अलावा निजी कॉलेजों की फ्री सीटों पर दाखिला पाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को भी यह छात्रवृत्ति मिलेगी। उन्होंने बताया कि इन छात्रों की जितनी भी फीस होगी उसका भुगतान केंद्र सरकार करेगी। ❑

स्वातंत्र्य चेतना का संवाहक डाकघर

○ ऋषिकेश

भारत में डाक व्यवस्था के 150 वर्ष और संचार प्रेषण के सदियों पुराने सफ़र का दस्तावेज़ है भारतीय डाक : सदियों का सफ़रनामा

डाक, डाकिया और चिट्ठी हमारे जीवन से वैसे ही जुड़ी है जैसे मोह, इच्छा और जिजीविषा। संचार क्रांति के इस उत्तर आधुनिक दौर में भी इनकी ज़रूरत और उपयोगिता अपनी जगह बदस्तूर कायम है। तकनीक और प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में कई मानकों को स्थापित करने वाले इस प्रगतिशील देश में चिट्ठियों की अहमियत कम नहीं हुई है। प्रेषण के ढंग से भले ही उत्तरोत्तर विकासोन्मुखी परिवर्तन हुआ है, परंतु डाक की मूल आत्मा यानी संदेशों का आदान-प्रदान अपने उसी मूल रूप में कायम है, जैसा कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजते समय था अथवा ई-मेल भेजते समय कंप्यूटर पर उंगलियां फिराते वक़्त। चिट्ठियों की बात आते ही काफ़्का की याद स्वाभाविक है। काफ़्का द्वारा पिता को लिखा गया पत्र जर्मन साहित्य का दस्तावेज़ माना जाता है। इसी तरह टालस्टाय द्वारा लिखे पत्र ने रोमां रोला की जीवनधारा ही बदल दी थी। जार्ज बर्नार्ड शॉ के पत्र भी बेहद चर्चित रहे। नेहरू की चिट्ठियों का संकलन *पिता का पत्र पुत्री के नाम* एक ऐतिहासिक पुस्तक का स्थान पा चुका है। कहानी तथा कविताओं में भी पत्रों को भरपूर जगह मिली है। पत्र शैली में लिखी गई राजकमल चौधरी की कहानी *परमप्रिय निर्मोही बालम मेरे प्राणपति* का संवेदनात्मक पत्र, स्थितियों का चित्रण वास्तविक और सजीव है। पत्र शैली में लिखी गई यह कहानी व्यापक असर पैदा करती है और इसकी अनुगूंज पाठकों को देर तक कंपित करती है। बच्चन से लेकर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और उसके बाद भी कई रचनाकारों की कुछ रचनाओं के केंद्र में पत्र रहे हैं।

9 अक्तूबर, विश्व डाक दिवस पर विशेष

संचार के तमाम साधनों के विकास के बावजूद चिट्ठियों का जो सहज प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है वैसा प्रभाव संदेशों के आधुनिक तकनीकी माध्यमों का तो कतई नहीं है। तकनीकी माध्यमों के पत्रों से संवेदना का मन को छूनेवाला तत्व और वह खास अपनेपन की गंध, जो चिट्ठियों में होती है, गायब रहता है।

संदेशों का प्रेषण कब शुरू हुआ? संभवत: मानव अस्तित्व के साथ ही। मीडियाकर्मी अरविंद कुमार सिंह अपनी पुस्तक *भारतीय डाक सदियों का सफ़रनामा* में बताते हैं कि संकेतों, चित्रों, ध्वनियों के सहारे शुरू हुई संकेत भाषा ने मानव सभ्यता के विकास के साथ ही लिखित संवाद का रूप लिया। इसी उत्तरोत्तर विकास की अत्याधुनिक परिणति हैं ई-मेल, फैक्स आदि।

संदेशों के प्रेषण-माध्यम संबंधी कई रोचक वृतांत मिलते हैं। घोड़ों और सांढ़ों के साथ-साथ कबूतरों आदि के माध्यम से संदेशों के प्रेषण संबंधी कई प्रमाण उपलब्ध हैं, संदेशवाहकों का अस्तित्व सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी था, *ऋग्वेद संहिता* में भी संदेशवाहकों का उल्लेख मिलता है।

डाक व्यवस्था को वास्तविक गति मिली हरकारों के सहारे ही। हज़ारों वर्षों तक संदेश पहुंचाने का काम हरकारों ने ही किया, तमाम ज़ोखिमों और विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए, संचार क्रांति के इस अत्याधुनिक दौर में भी भारत के कतिपय पहाड़ी और दुर्गम इलाके में आज भी हरकारों का अस्तित्व कायम है। जम्मू-कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में पद्म (जंस्कार) सहित कई जगहों पर आज भी डाक हरकारों द्वारा ही पहुंचाई जाती है। मध्य युग में डाक व्यवस्था को गति मिली। मुहम्मद बिन कासिम की सिंध तथा मुल्तान क्षेत्र में जीत के बाद घोड़ों तथा पैदल हरकारों के सहारे भारत-इराक के बीच एक प्रभावी संचार-तंत्र विकसित हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के

शासनकाल में हर तीन-तीन मील की दूरी पर डाक चौकियों के होने का उल्लेख मिलता है। हरकारे मुख्यत: नौजवान तथा बादशाह के विश्वासपात्र होने के अलावा बहादुर होते थे तथा राह की तमाम बाधाओं से जूझते थे। यह जानना बेहद आश्चर्यजनक है कि सिंध से दिल्ली तक के 810 मील का सफ़र पैदल हरकारे 5-6 दिन में पूरी कर लेते थे। अकबर के शासनकाल में पैदल हरकारे हर 10 मील पर बदले जाते थे तथा आगरा से अहमदाबाद डाक 5 दिनों में पहुंच जाती थी। पैदल हरकारों की तेज़ रफ़्तार का एक नायाब उदाहरण है, जहांगीर की मौत की सूचना 1600 किमी. दूर दक्कन में महज 20 दिनों में बनारसी नामक हरकारे द्वारा पहुंचा देना। भारत में अपनी डाक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिये ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरकारा प्रथा को ही अपनाया तथा उन्हें 'पोस्ट ब्वाय' का नाम दिया। हर 8 मील बाद हरकारों को विश्राम दिया जाता था तथा वहां से दूसरा हरकारा चलता था। रात में मशालची और डुगडुगी बजाने वाला साथ चलता था। उन दिनों हरकारों को 7 रुपये प्रतिमाह तथा मशालची और डुगडुगी बजानेवाले को 3-3 रुपये प्रतिमाह मज़दूरी मिलती थी। सन् 1822 में अंग्रेज़ों ने डाक घुड़सवारों को उपयोग में लाने का फैसला किया। आगे चलकर वैकल्पिक और तेज़ साधनों की सुगमता के कारण हरकारों की संख्या लगातार घटती गई। आंकड़े बताते हैं कि फरवरी 1931 में जहां 14,813 हरकारे सेवारत थे, सन् 1954 तक उनकी संख्या घटकर 7,320 रह गई। तमाम साधनों के उपलब्ध होने के बावजूद आज भी हरकारों का अस्तित्व बरकरार है। सदियों तक भारतीय डाक व्यवस्था की रीढ़ रहे हरकारों की ज़िंदगी कभी भी सुगम नहीं रही। डाक व्यवस्था की आधारशिला रखने वाले हरकारे समर्पित निष्ठा के एक जीवंत प्रतीक रहे।

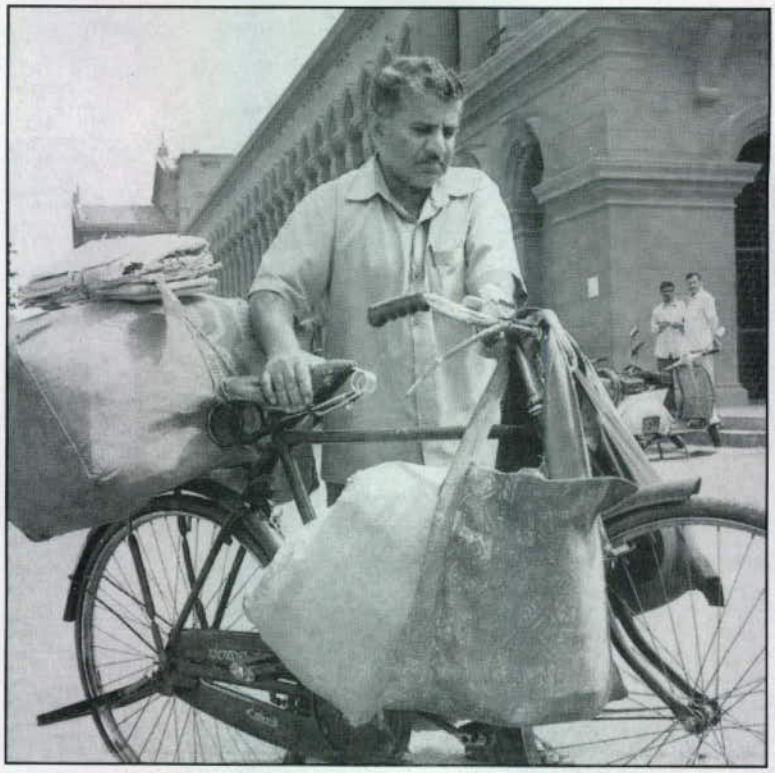

व्यावसायिक हितों को केंद्र में रखते हुए अंग्रेज़ों ने बंबई में पहला डाकघर सन् 1688 में खोला। 31 मार्च, 1774 को कलकत्ता जीपीओ की स्थापना के बाद पहली बार आमजनों को अपनी चिट्ठी भेजने का अवसर प्राप्त हुआ था। सन् 1837 में भारतीय डाक अधिनियम द्वारा डाक व्यवस्था पर सरकारी एकाधिकार तथा निजी डाक सेवा की समाप्ति के फैसले के साथ अखिल भारतीय प्रणाली हेतु पहल किया गया। इस अधिनियम के तहत सभी निजी डाक पर प्रतिबंध लगाया गया, परंतु जिला डाक (जमींदार डाक) की समानांतर व्यवस्था पुलिस थानों की मदद से चलती रही। जमींदारी डाक कर से चलने वाले जिला डाक में पुलिस थाने डाकघर की, थानेदार पोस्टमास्टर की और सिपाही, चौकीदार आदि डाकिये की भूमिका में रहे। इस व्यवस्था में पत्र पाने वाले को दो पैसा प्रति पत्र चौकीदार या सिपाही को अदा करना होता था। जिला डाक व्यवस्था अप्रैल 1906 तक अस्तित्व में रही।

पहली अगस्त, 1854 को केंद्रीकृत डाक व्यवस्था के नये युग का प्रारंभ हुआ और इंपीरियल पोस्ट ऑफिस एक्ट लागू किया गया। सन् 1853 में बंबई से ठाणे तथा 1854 में हावड़ा से हुगली के बीच रेल सेवा प्रारंभ हुई जो आगे विकसित होकर संचार क्रांति की बेहद मज़बूत वाहक बनी।

सन् 1854 में केंद्रीकृत डाक व्यवस्था की नींव रखे जाने के वक़्त 652 से ज्यादा रजवाड़ों की निजी डाक प्रणालियां अस्तित्व में थीं। रजवाड़ों की निजी डाक व्यवस्था को केंद्रीकृत डाक व्यवस्था में शामिल करने संबंधी एकीकरण वार्ताओं और तमाम कोशिशों के बाद भी 1920-21 तक 15 रियासतें डाक एकीकरण अभियान से अलग रहीं। आज़ादी मिलने तक कई राज्यों, मसलन- इंदौर, ओरछा, त्रावणकोर, हैदराबाद की अलग डाक व्यवस्था कायम रही। सबसे अंत में हैदराबाद डाक-तार प्रणाली का एकीकरण सन् 1953-54 में हुआ और इसके बाद भारतीय डाक का अखिल भारतीय स्वरूप स्थापित हो गया।

रियासतों की डाक व्यवस्था में हैदराबाद निज़ाम तथा मैसूर रियासत की डाक व्यवस्था बेहतर थी और उनका तंत्र बेहद मज़बूत तथा विकसित था। इन दोनों रियासतों के पास देहाती डाक सेवा का भी मज़बूत और कुशल तंत्र था।

अंग्रेज़ों के आगमन के बाद तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व के सभी तथ्यों के सूक्ष्म

विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अंग्रेज़ों की दिलचस्पी के केंद्र में उनका व्यावसायिक हित और सैन्य गतिविधियां ही थीं। उन्होंने अपनी सुविधा का ध्यान रखा तथा यूरोपीय आबादी वाले इलाकों में डाकघर खोला और विदेशी डाक पर भारी धनराशि अनुदान के रूप में दीं। डाक विभाग के अधीन डाक बंगले तथा पालकी सेवाएं भी रहीं। परंतु पालकी सेवा इतनी महंगी थी कि आम आदमी इनके उपयोग की बाबत सोच भी नहीं सकता था, इस तरह पालकी सेवा राजसी सेवा के रूप में ही चर्चित रही।

भारतीय डाक सेवा का जनोन्मुखी विकास वास्तव में आज़ादी के बाद ही हुआ। भारत-पाक विभाजन के पूर्व सन् 1947 में कुल 26,269 डाकघर थे तथा विभाजन के बाद भारत में कुल 23,344 डाकघर बचे थे। यह जनोन्मुखी नीतियों का ही परिणाम है कि जुलाई 2005 तक कुल 1,41,814 गांवों को डाकघर सेवा के दायरे में ले आया गया है तथा देश के डाकघरों का 89 प्रतिशत से अधिक देहातों में अवस्थित है। आज भारतीय डाक विभाग स्पीड पोस्ट सेवा, मनीआर्डर सेवा, ई-पोस्ट सेवा आदि तमाम तरह की सेवाएं प्रदान कर व्यापक होते जाते प्रौद्योगिकी की लहर में अपना संतुलन बनाए चल रहा है।

डाकघर बचत बैंक का प्रारंभ जहां सन् 1882 में हुआ वहीं डाक जीवन बीमा की शुरुआत सन् 1884 में हुई। सन् 1972 में ऐतिहासिक पिन कोड प्रणाली प्रारंभ होने से पत्रों को मानो पंख लग गए। सन् 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई तथा डाक ग्रीटिंग कार्ड का प्रारंभ सन् 2000 में हुआ और सन् 2004 से ई-पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई।

यह जानना विस्मयकारी है कि भारतीय डाक बचत बैंक में खातों की कुल संख्या 14.44 करोड़ है और इसमें लगभग 3,23,396 करोड़ रुपये की राशि सन् 2004 तक जमा थी। डाकघर बचत बैंक की शाखाओं की संख्या विश्व के किसी भी बैंक की शाखाओं की संख्या से अधिक है। समय के साथ-साथ राशि जमा करने तथा निकासी की व्यवस्था में सरलता लाई गई है और यह आमजनों के लिये ज्यादा सुगम हो गया है।

आमजनों के हित में भारतीय डाक द्वारा प्रदान की जा रही तीन तरह की सेवाएं उल्लेखनीय मानी जा सकती हैं, यथा पोस्टकार्ड, मनीआर्डर और बचत बैंक। भारतीय पोस्टकार्ड ही संचार का सबसे सस्ता और सुलभ साधन है। आज भी महज 50 पैसे में अपनी पाती देश के एक कोने से दूसरे कोने में पोस्टकार्ड के माध्यम से भेजी जा सकती है, आंकड़ों के अनुसार सन् 2003 में पोस्टकार्ड की खपत 163.4 करोड़ थी। मज़दूर वर्ग के ग़रीबों के लिये मनीआर्डर से रुपया भेजना सबसे सुगम और भरोसेमंद है। मज़दूरी कमाने गए लोगों और उनके सगों की मनीआर्डर पर निर्भरता इतनी अधिक है कि कुछ राज्यों के खास क्षेत्रों में कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी मनीआर्डर की अर्थव्यवस्था ही कायम है।

डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ होने के साथ ही भारतीय डाक की दुनिया में नये युग का सूत्रपात हुआ। उसके साथ ही टिकटों के संकलन का शौक भी पनपा। क्या आप जानते हैं कि विश्व का पहला डाक टिकट 'पेनी ब्लैक' 6 मई, 1840 को ब्रिटेन में ज़ारी हुआ था? एक पेनी मूल्य वाले काले रंग के इस डाक टिकट पर महारानी विक्टोरिया का रेखाचित्र था। एशिया महाद्वीप का पहला डाक टिकट, पहला भारतीय डाक टिकट था। यह 1 जुलाई, 1852 को तत्कालीन सिंध प्रांत में अस्तित्व में आया। सत्तर वर्षों की लंबी अवधि तक डाक टिकटों की छपाई विदेशी प्रेस में होते रहने के बाद सन् 1926 से इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक में डाक टिकट छपना शुरू हुआ। समय के साथ-साथ टिकटों के डिज़ाइन, रंग आदि में भी उल्लेखनीय परिवर्तन होता रहा। नयी दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने के अवसर पर 1 फरवरी, 1930 को चार विशेष चित्रात्मक डाक टिकट जारी हुए। भारतीय डाक के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका में शामिल हरकारा, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, जलयान आदि को दर्शाते हुए विशेष शृंखला के डाक टिकट 1937 में जारी किए गए। इन कुछ अपवादों को छोड़कर स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारतीय डाक टिकटों पर मुख्यत: महारानी और महाराजा के तस्वीर ही छाए रहे।

स्वतंत्रता के पश्चात सन् 1947 में जय हिंद शृंखला के तीन स्मारक डाक टिकट जारी किए गए। इसी शृंखला में राष्ट्रीय ध्वज फहराता आज़ाद भारत का पहला डाक टिकट शामिल था। विश्व डाक संघ के सम्मान में सन् 1949 में चार विशेष श्रेणी के डाक टिकट जारी किए गए। इसी वर्ष अजंता, कोणार्क, त्रिमूर्ति, बोधिसत्व, सांची-स्तूप, बोध गया, नटराज, लालकिला आदि ऐतिहासिक धार्मिक और पुरातात्विक महत्व के स्थानों पर केंद्रित ऐसे डाक टिकट जारी हुए जिनमें हमारी सामाजिक-सांस्कृतिक धरोहर और विरासतों की मनोहारी झलक मिलती है। 26 जनवरी, 1950 को संप्रभु भारतीय गणराज्य के सम्मान में चार टिकटों की शृंखला जारी हुई। रेल शताब्दी वर्ष तथा डाक शताब्दी वर्ष के अवसर पर क्रमश: 1953 एवं 1954 में विशेष डाक टिकट जारी किए गए।

विषयवस्तु के लिहाज़ से भारतीय डाक टिकट दुनिया के संपन्न डाक टिकटों की श्रेणी में आते हैं। भारतीय डाक टिकटों में सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहरों, संपदाओं आदि को ही नहीं,बल्कि राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के नेताओं और राष्ट्र निर्माण हेतु बने लेखक, पत्रकार, चित्रकार, उद्यमी, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, समाज सुधारक, कलाकार समेत संत-मनीषी आदि को भी प्रमुखता मिली है।

डाक टिकटों की दो कोटियां हैं - पारंपरिक कार्य में प्रयुक्त होने वाले नियत डाक टिकट और सामाजिक सरोकारों से जुड़े स्मारक डाक टिकट। स्मारक डाक टिकट किसी जीवित व्यक्ति पर जारी नहीं

होता है, एकमात्र अपवाद 1980 में मदर टेरेसा के सम्मान में जारी डाक टिकट है। भारतीय दुल्हन शृंखला, समकालीन कला शृंखला, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष शृंखला, भारत के किले शृंखला, इंदिरा गांधी पर केंद्रित शृंखला, भारतीय वृक्षों, वन्यजीवों, भारत के नगर, भारतीय महिला, महान सामाजिक-राजनीतिक व्यक्तित्व, ऐतिहासिक व्यक्तित्व, परमवीर चक्र विजेता आदि तमाम शृंखलाओं के भारतीय टिकट बेहद लोकप्रिय हुए और इन्हें भारतीय डाक विभाग की सार्थक पहल माना जा सकता है।

रेल डाक सेवा (आरएमएस) ने भारतीय डाक प्रणाली को अधिक गतिशील बनाने में अहम भूमिका निभाई है। 18 सितंबर, 1854 को कलकत्ता जीपीओ के सीमा क्षेत्र में रेलवे से डाक की ढुलाई शुरू हुई। सन् 1900 तक भारतीय रेल लाईन का विस्तार 23,572 किलोमीटर हो गया। रेलों के विस्तार के साथ ही रेलवे से ढोई जानेवाली डाक में भी वृद्धि हुई। रेलवे मेल सर्विस का वर्तमान नाम 1 अगस्त, 1880 को दिया गया। आज़ादी के बाद आरएमएस को ट्रेनों में कोच दिए गए तथा स्टेशनों पर विश्राम की व्यवस्था हुई। रेलवे मेल सेवा डाक विभाग की बेहद गतिशील सेवा है तथा यह कथन अप्रासंगिक नहीं है कि भारतीय रेल ही भारतीय डाक की जीवनरेखा है। विगत डेढ़ शताब्दी में यातायात के कई साधनों का उल्लेखनीय विकास और विस्तार हुआ है। परंतु भारतीय डाक के उत्तरोत्तर विकास और अभिवृद्धि में भारतीय रेल का योगदान सर्वाधिक है।

दुनिया की पहली सरकारी हवाई डाक सेवा 21 फरवरी, 1911 को 6,500 पत्रों को साथ लेकर उड़ने के साथ ही शुरू हुई। हालांकि भारत में नियमित हवाई डाक सेवा का प्रारंभ सन् 1920 में हुआ। महात्मा गांधी की पहली पुण्य तिथि के अवसर पर शुरू हुई ऑल अप स्कीम से वायु डाक सेवा में उल्लेखनीय सुधार हुआ। स्पीड पोस्ट तथा ऐसी कई प्रीमियम सेवाएं हवाई डाक सेवा के सहारे ही साकार हो सकीं।

अमरीकी डाक सेवा में उपयोग में आ रही जिप मेल की तर्ज़ पर पिन कोड प्रणाली का प्रारंभ 15 अगस्त, 1972 को होने के बाद से डाक सेवा की गति में उल्लेखनीय

तेज़ी आई। छह अंकों के इस कोड में पहला अंक राज्य और दूसरा अंक इलाका बताता है तथा आखिरी दो अंक संबंधित डाकघर, पिन कोड के लिहाज से पूरे देश को आठ भागों में बांटा गया है।

दूरसंचार के क्षेत्र में नयी तकनीकों के आगमन और निजी क्षेत्र के प्रवेश के साथ ही दुनियाभर में अद्भुत प्रगति हुई और भारत भी इस परिवर्तन से अछूता नहीं रहा। सन् 1995 में भारत में संचार क्रांति के दौर की शुरुआत और कूरियर सेवा के आगमन से परंपरागत डाक सेवा के सामने चुनौतियां बढ़ी हैं। इन चुनौतियों का सामना करने हेतु डाक विभाग भी आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हुआ है तथा विभिन्न प्रकार के कार्य व्यापारों में प्रौद्योगिकी और तकनीक को शामिल कर डाक घरों को आधुनिक रूप देने की सार्थक पहल की गई है।

भारतीय डाक: सदियों का सफ़रनामा नामक अरविंद कुमार सिंह की 44 अध्यायों में विभाजित पुस्तक की उपादेयता इसी बात से प्रमाणित होती है कि भारतीय डाक से जुड़ा ऐसा कोई पक्ष नहीं है, जो अनछुआ रह गया हो। प्रत्येक घटना क्रम और डाक से जुड़े सभी पक्षों की इतनी सघन और बारीक पड़ताल महज डाक प्रणाली के विकास और उसकी कार्यशैली की ही नहीं, बल्कि भारतीय डाक के विकास क्रम के तमाम पड़ावों, उनसे जुड़े सूक्ष्म कारकों के विशद और तथ्यपरक गहन अध्ययन का परिणाम है। इसे महज संदर्भ ग्रंथ कहना इस पुस्तक की उपादेयता को कम करना है। यह एक विशद ऐतिहासिक ग्रंथ है, आनेवाले समय के लिये एक धरोहर। इस पुस्तक को प्रकाशित कर नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। आलोच्य पुस्तक के लेखक अरविंद कुमार सिंह पत्रकार होने के साथ ही एक संवेदनशील कवि भी हैं। इस पुस्तक के लिये तथ्यों और आंकड़ों के संग्रह का श्रमसाध्य और दुष्कर कार्य करने के लिये जिन दुर्गम पथों से उन्हें गुज़रना पड़ा होगा, उसका सहज अंदाजा मुश्किल है। यह पुस्तक एक समर्पित निष्ठा का प्रतीक है; तमाम अवरोधों, दुर्गमताओं और विपरीत परिस्थितियों की परवाह किए बगैर महज अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ते हरकारे-सी समर्पित निष्ठा का प्रतीक। ❑

(लेखक एक साहित्यिक पत्रिका का संपादन कर चुके हैं।
ई-मेल : rishikesh_dec@yahoo.co.in)

दिल्ली सरकार
टीम दिल्ली – सपने करे साकार
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
DIP/860/07/08
बुलंदियों के साठ वर्ष
स्वतन्त्रता दिवस की शुभकामनायें।
श्रीमती शीला दीक्षित
मुख्यमंत्री, दिल्ली
डा. अशोक कालिया
डा. योगानंद शास्त्री
श्री मंगतराम सिंघल
श्री राजकुमार चौहान
श्री हारून युसुफ
श्री अवतेश्वर सिंह लवली
सूचना एवं प्रचार निदेशालय

YH-10/07/4

ख़बरों में

- **केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले**

असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के लिये सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2007 के संशोधित मसौदे पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी है। सरकार अब इस विधेयक को संसद के इसी सत्र में पेश करेगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने 2 अक्तूबर से इसी क्षेत्र के मज़दूरों के लिये एक स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है।

इन निर्णयों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्यमंत्री प्रियरंजन दासमुंशी ने कहा कि यह स्वास्थ्य बीमा योजना ग़रीबी-रेखा के नीचे के मज़दूरों और उनके परिवारों के लिये उपलब्ध होगी।

कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने अनुसूचित जातियों के लिये चल रही केंद्र पोषित पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को जारी रखने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिये पांच हज़ार करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है।

केंद्र के बायो-टेक्नोलॉजी विभाग के अधीन हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 98 करोड़ रुपये की लागत से एक ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।

कैबिनेट ने सीपीओई के गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। यह संस्था दुनियाभर में रोज़गार की संभावनाओं को न केवल तलाशेगी बल्कि उन पर शोध भी करेगी और नज़र भी रखेगी।

कैबिनेट ने पासपोर्ट जारी करने की समूची प्रक्रिया में व्यापक सुधारों के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके तहत अब पासपोर्ट जारी करने से जुड़ी फ्रंट-एंड एक्टिविटीज की आउटसोर्सिंग की अनुमति होगी। सरकार देशभर में 68 पासपोर्ट सुविधा केंद्र खोलेगी।

सीसीईए ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम को 31 मार्च, 2008 तक ज़ारी रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

- **भारत के बीपीओ निर्यात में 47 फीसद की बढ़ोतरी**

देश का बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग (बीपीओ) कंपनियों का कारोबार 2006-07 के दौरान 47 फीसद बढ़कर 20,890 करोड़ रुपये हो गया। आईटी पत्रिका डेटाक्वेस्ट के किए गए 20 प्रमुख कंपनियों के सर्वेक्षण के मुताबिक जेनपैक्ट ने 2,220 करोड़ रुपये की आय के साथ अपना अव्वल स्थान बनाए रखा है।

इसके बाद ट्रांसवर्क्स (1,510 करोड़), आईबीएम दक्ष (1,260 करोड़), टीसीएस (1,107 करोड़) और कैम्ब्रिग साल्यूशंस (1,000 करोड़ रुपये) का स्थान है।

- **उर्दू की मशहूर लेखिका कुर्रतुल ऐन हैदर नहीं रहीं**

विख्यात उर्दू कथाकार और उपन्यासकार कुर्रतुल ऐन हैदर का 21 अगस्त की सुबह नोएडा में निधन हो गया। वे 80 वर्ष की थीं। उनके निधन से उर्दू ही नहीं समूचे भारतीय साहित्य जगत में शोक छा गया।

ऐनी आपा के नाम से जानी जाने वाली कुर्रतुल ऐन हैदर का जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। उनके पिता सज्जाद हैदर यल्दरम उर्दू के जाने-माने लेखक थे। ऐनी आपा ने विवाह नहीं किया था और बहुत छोटी उम्र में लिखना शुरू कर दिया था। उनका पहला कहानी संग्रह *शीशे के घर* 1945 में प्रकाशित हुआ जब वे 18 वर्ष की थीं और पहला उपन्यास *मेरे भी सनमखाने* 19 वर्ष की उम्र में छप गया था।

उन्हें *आग का दरिया* उपन्यास के जरिये दूसरी भाषाओं के पाठकों के बीच बखूबी जाना जाने लगा। इस उपन्यास में दो हज़ार साल के इतिहास का विस्तृत फलक लिया गया है। 1989 में उन्हें *आखिरी शब के हमसफ़र* के लिये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इससे पहले उन्हें 1967 में *पतझड़ की आवाज़* उपन्यास के लिये साहित्य अकादेमी पुरस्कार मिल चुका था। उन्हें पद्मश्री और पद्मभूषण सम्मान, इक़बाल सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और ग़ालिब सम्मान से भी नवाज़ा गया। उनके दूसरे प्रमुख उपन्यासों में *दास्तान-ए-अहदे गुल, सफीन-ए-गमे-दिल, गर्दिशे-रंगे-चमन, चांदनी बेगम* शामिल हैं। उनके चार कहानी संग्रह हैं- *सितारों से आगे, शीशे का घर, पतझड़ की आवाज़*, रोशनी की रफ़्तार।

- **मौद्रिक सख़्ती से नियंत्रित हुई महंगाई**

बीते साल मौद्रिक सख़्ती का ज़ोरदारी से मुक़ाबला करने वाली मुद्रास्फीति की दर 18 अगस्त को समाप्त सप्ताह के दौरान घटकर महज 3.94 प्रतिशत रह गई है। महंगाई के बढ़ने की मौजूदा दर पिछले 15 महीने के दौरान सबसे कम है।

महंगाई की मौजूदा दर रिज़र्व बैंक द्वारा तय लक्ष्य के मुक़ाबले एक प्रतिशत से भी अधिक कम है। रिज़र्व बैंक की कोशिश 2007-08 के दौरान मुद्रास्फीति को 5 प्रतिशत के करीब रखने की है, जबकि मध्यावधि में इसे 4 से 4.5 प्रतिशत के बीच लाया जाएगा।

बीते वर्ष की समान अवधि में महंगाई की दर 5.12 प्रतिशत थी जबकि बीते सप्ताह के दौरान यह दर 4.10 प्रतिशत थी। इससे पहले मुद्रास्फीति की दर 29 अप्रैल, 2006 के समाप्त सप्ताह के दौरान मौजूदा स्तर से कम थी। महंगाई की दर में भारी कमी के बावजूद फलों और सब्ज़ियों, दूध, अंडों, मीट और मछली जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं की क़ीमतों में कमी आई है, हालांकि ज्यादातर विनिर्मित वस्तुओं और गैर खाद्य वस्तुओं की क़ीमतों में कमी देखने को मिली है।

महंगाई पर नियंत्रण के लिये बीते महीने

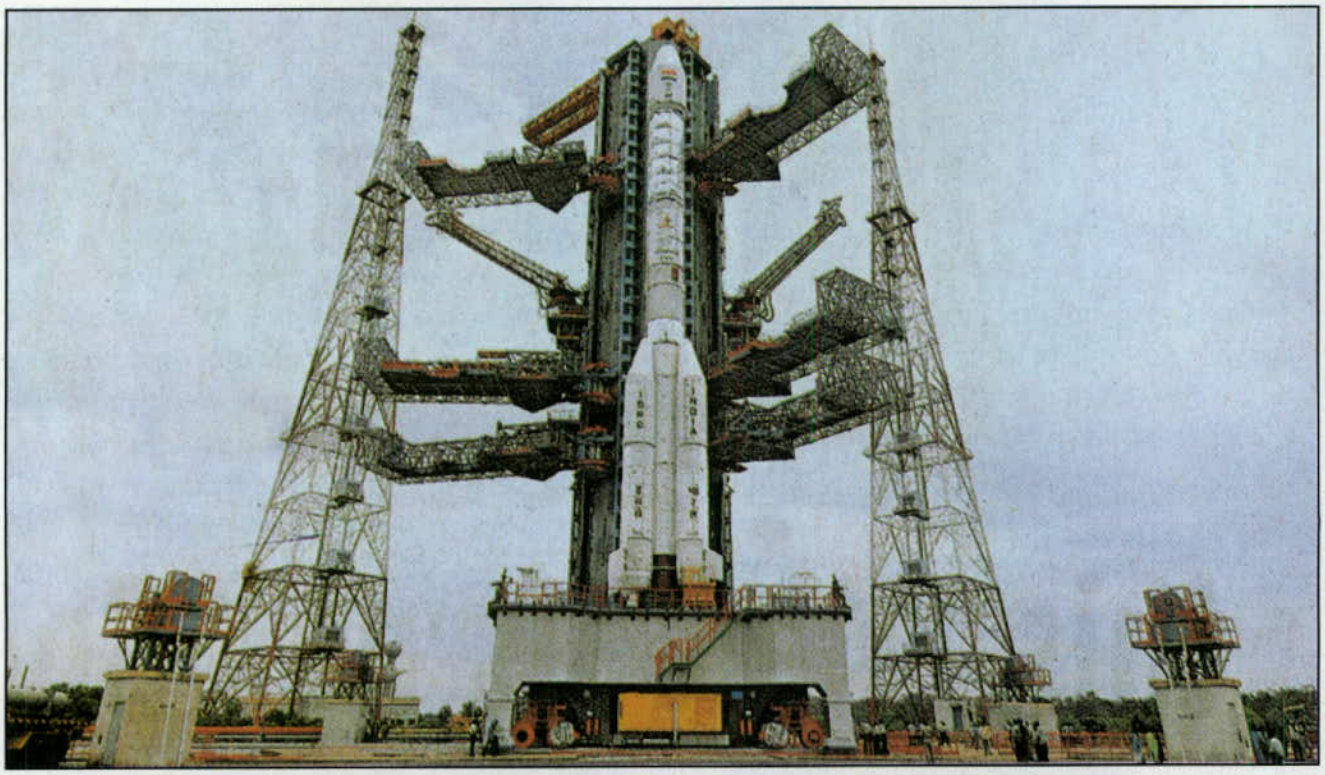

इसरो के नवीनतम संचार उपग्रह इंनसैट–4 सीआर को अंतरिक्ष में ले जाने से पूर्व श्री हरिकोटा में लांचपैड पर तैयार खड़ा प्रक्षेपण यान जीएसएलवीएफ 04

रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति की तिमाही समीक्षा में नकद आरक्षित अनुपात को 6.5 से बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया था। इस कदम से केंद्रीय बैंक ने व्यवस्था से अतिरिक्त नकदी को सोखा था। यह सख़्त मौद्रिक नीति का ही असर है कि महंगाई की दर पिछले 11 सप्ताह के दौरान लगातार पांच प्रतिशत से कम बनी हुई है।

वार्षिक मुद्रास्फीति की दर इस साल जनवरी में 6.69 प्रतिशत के स्तर पर थी हालांकि बाद में रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक सख़्ती और सरकार द्वारा आयात शुल्कों में कटौती के चलते इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। सरकार ने 23 जून, 2007 के लिये महंगाई के संशोधित आंकड़े जारी किए हैं। नये आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान महंगाई की दर 4.32 प्रतिशत रही है जो पूर्व अनुमानों के मुताबिक 4.13 प्रतिशत थी।

इस दौरान थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) 0.1 प्रतिशत बढ़कर 213.6 अंक हो गया है। महंगाई की गणना डब्ल्यूपीआई के आधार पर की जाती है। प्राथमिक वस्तुओं के सूचकांक में 0.5 प्रतिशत और खाद्य वस्तुओं के सूचकांक में 0.9 प्रतिशत और गैर खाद्य वस्तुओं की क़ीमतों में 0.1 प्रतिशत का इज़ाफा हुआ है जबकि ईंधन, बिजली, लाइट और लुब्रिकेंट्स की क़ीमतों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला है। विनिर्मित वस्तुओं की क़ीमतों में 0.1 प्रतिशत की कमी देखी गई है।

- **इनसैट- 4 सीआर : कामयाबी की नयी उड़ान**

अंतरिक्ष में भारत ने एक और कामयाब उड़ान भरी है। कम्यूनिकेशन की दुनिया में क्रांति लाने का दम रखने वाले सैटेलाइट इनसैट-4सीआर अपनी कक्ष में पहुंच गया है। यहां से जिओसिनक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (जीएसएलवी) ने इसे लेकर उड़ान भरी। प्रक्षेपण के 17.55 मिनट बाद उपग्रह अपनी कक्षा में सफलता के साथ स्थापित हो गया। इनसैट-4सीआर देश में डीटीएच टेलिविज़न के विस्तार और उपग्रह समाचार संकलन में अहम भूमिका निभाएगा। इस सैटलाइट पर 12 हाई पावर केयू बैंड ट्रांसपॉन्डर लगे हैं।

जीएसएलवी का मकसद उपग्रह को जिओसिनक्रोनस ट्रॉसफर ऑर्बिट में स्थापित करना होता है। इनसैट-4 सीआर को ले जाने वाला व्हीकल जीएसएलवी-एफओ4 इस सीरीज में पांचवें नंबर का है। हमारे वैज्ञानिकों के लिये यह प्रक्षेपण अहम है। दरअसल जीएसएलवी सीरीज की पिछली लॉन्च नाकाम रही थी। इसके बाद से इस साल 10 जनवरी को पीएसएलवी-सी7 और 23 अप्रैल को पीएसएलवी-सी8 को कामयाबी के साथ प्रक्षेपण किया जा चुका है। भारत 1979 से अब तक उपग्रह प्रक्षेपण के कुल 24 प्रयास कर चुका है जिसमें से चार बार नाकामी मिली।

इससे देश में डीटीएच प्रसारण को फायदा होगा। रिलायंस, वीडियोकॉन, भारती जैसी कंपनियां डीटीएच सेवा देने

के लिये सैटेलाइट के ट्रांसपॉन्डर का इंतजार कर रही हैं। संभावना है कि रिलायंस की डीटीएच सर्विस ब्लू मैजिक को इनसैट-4सीआर में जगह मिले। रिलायंस ने सैटलाइट के आठ केयू बैंड ट्रांसपॉन्डर मांगे हैं। बाकी के चार ट्रांसपॉन्डर नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर के लिये आरक्षित हैं। इसके अलावा इनसैट-4सीआर से बढ़िया क्वॉलिटी के डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन में भी मदद मिलेगी।

49 मीटर ऊंचा प्रक्षेपण यान अपने साथ ले गया 2130 किलोग्राम का उपग्रह। करीब 115 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद यान ने सैटेलाइट को छोड़ दिया और वह अपनी कक्षा में स्थापित हो गया। उपग्रह की आयु 10 साल है। ऊर्जा के लिये इसमें सोलर सिस्टम और निकल हाइड्रोजन बैटरियां लगी हैं।

जीएसएलवी के जरिये पहली बार 20 सितंबर, 2004 को एजुसैट प्रक्षेपित किया गया था। यह थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक व्हीकल है। अपनी मौजूदा क्षमता में यह 2200 किलो का उपग्रह जीटीओ में स्थापित कर सकता है। आने वाले दिनों में जब रूसी तकनीक की जगह इसरो की क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी तो इसकी क्षमता 2400 किलो तक हो जाएगी। जीएसएलवी-एमके3 पर भी काम हो रहा जो चार टन के उपग्रह ले जा सकेगा।

- **देश में बाल मज़दूरों की संख्या सवा करोड़**

सरकार ने बताया कि साल 2001 की जनगणना के मुताबिक देश में बाल मज़दूरों की संख्या 1.26 करोड़ है। श्रम और रोज़गार राज्यमंत्री आस्कर फर्नांडीज ने राज्य सभा में सईदा अनवरा तैमूर और विजय दर्डा के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल मज़दूरों के पुनर्वास के लिये राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना चलाई जा रही है। इन बाल मज़दूरों के परिवारों के आर्थिक उन्नयन के लिये विभिन्न परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं।

श्री फर्नांडीज ने बंधुआ मज़दूरों के बारे में वरिदर सिंह बाजवा के पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि इस साल 31 जुलाई तक पश्चिम बंगाल में 88 बंधुआ मज़दूरों का पुनर्वास किया गया। इसके लिये केंद्र सरकार ने राज्य को 8.50 लाख रुपये की सहायता राशि दी थी।

उन्होंने बताया कि साल 2006-07 में उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से 10.40 लाख रुपये और पश्चिम बंगाल को 3.01 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई थी। साल 2006-07 में उत्तर प्रदेश में 104 बंधुआ मज़दूरों का और पश्चिम बंगाल में 93 बंधुआ मज़दूरों का पुनर्वास किया गया था।

- **ऋग्वेद की पांडुलिपियां यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल**

अंतरराष्ट्रीय संस्था यूनेस्को ने *ऋग्वेद* की 1800 से 1900 ईसा पूर्व की 30 पांडुलिपियों को अपनी विरासत सूची में शामिल कर लिया है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री अंबिका सोनी ने राज्यसभा में गिरीश कुमार सांगी के सवाल के लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन ने यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल करने के लिये भंडारकर ओरियंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे से *ऋग्वेद* की पांडुलिपियों का नामांकन पेश किया था। इनमें से 30 पांडुलिपियों को विश्व स्मृति रजिस्टर 2007 में शामिल कर लिया गया है।

- **नेहरू कप में जीत दर्ज़ कर भारत ने इतिहास रचा**

चैंपियन शब्द के साथ जुड़ने के लिये भारतीय फुटबाल लंबे समय से छटपटा रहा था। एशियाई खेल 1962 में स्वर्ण जीतने के बाद भारत ने ऐसी कोई सफलता नहीं पाई थी, जिसमें ऊंची रैंकिंग की टीमें खेल रही हों। वियतमान में हुए 2003 का एलजी कप भारत जीता ज़रूर था पर उसमें इतनी शक्तिशाली टीमें नहीं थीं। एक दशक के लंबे अरसे के बाद फिर से शुरू हुए नेहरू कप के फाइनल में अपने से 39वीं रैंकिंग ऊंची सीरियाई टीम को पीटकर भारत ने इतिहास रच दिया।

एन.पी. प्रदीप के गोल से मिली यह उपलब्धि। इसे इत्तफाक ही कहा जाएगा कि भारतीय टीम को यह सफलता देश की महान खेल शख्सियत ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मिली। टूर्नामेंट की प्रायोजक ओएनजीसी ने भारतीय फुटबाल टीम की इस सफलता पर 80 हज़ार डॉलर देने की घोषणा की। इसके अलावा भारतीय कप्तान बाईचुंग भूटिया को श्रीमती दीपा दासमुंशी ने दस लाख रुपये का चेक दिया। ❑

लेखकों से अनुरोध

कृपया अपने लेख टाइप करा कर सीडी में भेजें। साथ में एक मूल टंकित प्रति हो। वापसी के लिये टिकट लगा लिफाफा अवश्य संलग्न करें। डाक टिकट लगा लिफाफा संलग्न न होने पर अस्वीकृति की दशा में रचनाएं वापस भेजना संभव नहीं होगा। लेख पर दो से अधिक लेखकों के नाम केवल विशेष शोध लेखों पर ही दें। जिन रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा वे स्वीकार नहीं की जा सकेंगी। रचना के प्रकाशन के संबंध में किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार अथवा फोन न करें। विशेष अवसरों के लिये लेख तीन माह पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए। रचनाओं के साथ यथासंभव प्रासंगिक चित्र भी भेजें। यदि आपका ई-मेल पता है तो कृपया अपना ई-मेल भी संलग्न करें। सभी रचनाएं 'संपादक, योजना' के नाम प्रेषित करें। **- संपादक**

ध्येयIAS | DHYEYA The IAS

हमारा ध्येय आपकी क्षमता का विकास

.....Aim to Learn, Learn to Aim

दर्शनशास्त्र

अंतिम चयनित (2006)

- नवल किशोर
- रघुनाथ भारती
- विजयेन्द्र कुमार
- कौशलेन्द्र तिवारी

द्वारा

दीपक कुमार सिंह

सत्र आरंभ :
दिनांक : 18 अक्टूबर, 2007
समय : 9:30 प्रातः - 12:30 दोपहर

दर्शनशास्त्र
DSDL PROGRAMME

उपलब्ध सामग्री • IAS परीक्षा-उपयोगी शृंखला - 1 : पाश्चात्य दर्शन (प्लेटो से हेगेल तक) • IAS परीक्षा-उपयोगी शृंखला - 2 : समकालीन पाश्चात्य दर्शन (मूर से क्वाइन तक) • IAS परीक्षा-उपयोगी शृंखला - 3 : भारतीय दर्शन (चार्वाक जैन, बौद्ध एवं सांख्य) • IAS परीक्षा-उपयोगी शृंखला - 4 : भारतीय दर्शन (न्याय-वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत) • IAS परीक्षा-उपयोगी शृंखला - 5 : सामाजिक राजनीतिक दर्शन (राजनीतिक आदर्श से समाजवाद और मार्क्सवाद तक) • IAS परीक्षा-उपयोगी शृंखला - 6 : सामाजिक राजनीतिक (मानववाद से पारिस्थितिकी दर्शन तक) • IAS परीक्षा-उपयोगी शृंखला - 7 : धर्म दर्शन (ईश्वर की धारणाएँ से धर्म और नैतिकता तक)

Correspondence Course Programme begins...

भूगोल

द्वारा **कुमार गौरव**

GEO FOUNDATION TARGET PT - CUM - MAINS 2008

• Fundamentals of Geography for *Basic Understanding and Selection of Optional* • One Year PT Geo Test Programme • Mastering Maps through *Map Learning* • Writing Skill Development Programme • Group Meeting Session *for Face-to-Face Learning* • Test Series and Discussion Programme *for Self Assessment* • Mains Exclusive for *Examination Oriented Preparation*

दिल्ली केन्द्र
ध्येयIAS
18 October
Time - 1:30 – 5:30 p.m.
A-19, IIIrd Floor, Priyanka Tower, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi

इलाहाबाद केन्द्र
Endeavour for Civil Services
22 October
Time - 2:00 – 6:00 p.m.
573, Mumford Ganj (Nigam Chauraha) Allahabad, PM.9415217610

कोर्स की अवधि | मुख्य परीक्षा : 2008 (5 माह) | प्रा.–मुख्य : 2008 (7 माह)

DHYEYA EDUCATIONAL SERVICES PVT. LTD.
A-19, IIIrd Floor, Priyanka Tower, Mukherjee Nagar, Delhi-9 Ph. 27655121, 9899457549

YH-10/07/9

समय प्रबंधन

○ विजय प्रकाश श्रीवास्तव

पुराने समय से कहावत चली आ रही है कि बीत चुका समय एवं हाथ से निकला अवसर लौट कर नहीं आते। हम सभी ने इसकी सच्चाई को महसूस किया होगा। वस्तुत: किसी भी व्यवसाय अथवा पेशे में सफल होने के लिये समय प्रबंधन ज़रूरी है।

समय कम पड़ने की शिकायत काफी लोग किया करते हैं। संभव है आपको भी कई बार यह लगता हो कि आपके पास जो उपलब्ध समय है वह आपकी विभिन्न ज़रूरतों के लिये पर्याप्त नहीं है या आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपको उन कार्यों के लिये समय नहीं मिलता। गिने-चुने लोग ही ऐसे होंगे जिनका कहना हो कि उन्हें समय की कोई कमी नहीं होती।

लोगों के बीच अन्य असमानताएं हो सकती हैं लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिये दिन 24 घंटों का ही होता है। समय की कमी की समस्या पर गंभीरता से विचार करें तो हम पाएंगे कि इस समस्या का कोई आधार नहीं है। हर कोई उपलब्ध दिन के 24 घंटों का उपयोग अलग-अलग तरीके से करता है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनके पास करने को हमेशा कुछ न कुछ होता है और वे अपनी उपलब्धियों के नाम पर काफी कुछ गिना सकते हैं, तो भी वे समय कम होने की बात नहीं करते। दूसरी तरफ, ऐसे लोग भी हैं जो समय की कमी का रोना तो रोते हैं लेकिन आप उन्हें अक्सर समय नष्ट करते पाएंगे और उनके पास उपलब्धियों के नाम पर भी कुछ नहीं होगा।

इस तुलना से हम आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि व्यक्ति की सफलता एवं उपलब्धियां काफी कुछ उसके द्वारा समय के सही उपयोग पर निर्भर करती हैं। व्यक्ति की क्षमता एवं कार्यकुशलता का एक परिचालक उसके द्वारा समय का सदुपयोग भी है। सिर्फ़ व्यस्त रहने से समय का सदुपयोग नहीं हो जाता। समय प्रबंधन से आशय समय नष्ट न करने के साथ-साथ इसे महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कार्यों में लगाना भी है।

देखा जाए तो उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, कार्यपालकों, राजनीतिज्ञों तथा उद्यमियों वगैरह के ऐसे तमाम उदाहरण मिलेंगे जिनके जीवन में काफी गतिशीलता है और जिन्होंने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, पर वे समय की कमी को लेकर कभी परेशान नहीं रहे। खूबी की बात तो यह है कि अपना निर्धारित कार्य करने के साथ ऐसे व्यक्ति अपनी रुचियों के लिये भी समय निकाल लेते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि वे जानते हैं कि उन्हें कब क्या करना है और उसी के अनुसार वे विभिन्न कार्यों के लिये समय का आवंटन करते हैं।

अगर आप भी अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहते हैं तो इसके लिये आपको सुनियोजित प्रयास करने होंगे। सर्वप्रथम अपने मन से यह बात निकाल दीजिए कि आपके पास समय कम है और काम ज्यादा। इसकी बजाय प्रत्येक दिन सुबह इस संकल्प के साथ शुरू कीजिए कि आप अपने समय का पूर्ण एवं सर्वोत्तम उपयोग करेंगे। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम आपकी प्राथमिकताओं का निर्धारण है। यदि आप बीते दिनों में समय के उपयोग के अपने तरीके का अध्ययन करें तो पाएंगे कि आपका थोड़ा या अधिक समय व्यर्थ के कार्यों, अनावश्यक बातचीत आदि में गुज़रता है। इनसे छुटकारा पाने की कोशिश कीजिए ताकि इस समय को आप अन्य मूल्यवान, उपयोगी एवं लाभप्रद कार्यों में लगा सकें।

आपने पाया होगा कि कई बार टेलीविज़न पर कोई उपयोगी कार्यक्रम न होते हुए भी टीवी चलता रहता है और लोग उसके सामने निष्क्रिय बैठे कार्यक्रम देखते रहते हैं। इसी प्रकार किसी के हाथ कोई पत्रिका लग गई और वह उसे शुरू से आखिर तक पढ़ता है भले ही उसकी कुछ रचनाओं की उसके लिये कोई उपयोगिता न हो। यदि हम टीवी पर केवल चुने हुए एवं उपयोगी कार्यक्रम देखें तथा केवल लाभदायक एवं उपयुक्त सामग्री का अध्ययन करें तो हमारे लिये काफी समय निकल सकता है। एक बार अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के बाद ज्यादा ज़रूरी कार्यों को पहले हाथ में लीजिए। विभिन्न कार्यों में लगने वाले समय का अनुमान कर कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा करने पर ज़ोर दें। इस प्रकार से आपमें समयानुशासन की प्रवृत्ति विकसित होगी।

समयानुशासन आपको टाल-मटोल की आदत से छुटकारा दिलाता है। काम टालने के लिये लोग बहाना ढूंढ़ा करते हैं। कई बार आलस का बहाना होता है तो कभी मन न होने का। आलस्य से उबरने या मन के तैयार होने तक काफी देर हो चुकी होती है और समय पर कार्य न पूरा होने की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। टाल-मटोल की आदत व्यक्ति की छवि भी ख़राब कर सकती है। आलस्य को दूर रखकर व्यक्ति यदि अपने कार्य को समय रहते पूरा कर लेता है तो उसे खुशी तो होती ही है, भावनात्मक संतोष भी मिलता है। एक काम पूरा करने के बाद दूसरा काम हाथ में लिया जा सकता है।

बेहतर होगा कि किसी भी दिन किए जाने

दीक्षांत IAS समाजशास्त्र के लिए समर्पित संस्थान

समाजशास्त्र

by

DR. S. S. PANDEY

निःशुल्क कार्यशाला
प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा - 2008

30th October, 07 at 5 PM

हमारे सफल अभ्यर्थी...

ARCHNA
UPSC, 06

NAVAL KISHORE
UPSC, 06

SHARAD KUMAR
Dy.S.P.
BPSC (10th Rank)

PANKAJ SHUKLA,
Chattisgarh PSC
27th Rank (Dy.S.P.)

SHWETA CHNDRAKER
Chattisgarh PSC
93rd Rank

VIVEK KUMAR DUBE
समाजशास्त्र में 72% अंक
(UPPSC,04 में सब रजिस्ट्रार पद हेतु प्रथम रैंक पर चयनित)

AVNISH KUMAR PANDEY
(UPPSC (L),03
में द्वितीय रैंक पर चयनित

DEEPAK KUMAR
IPS

ANAND KUMAR
IRS

SANJAY KUMAR
IPS

PANKAJ S.
SISODIYA, UPSC

RICHA,
UPSC

RICHA MISRA
Chttisgarh PSC
93rd Rank
&
MPPSC

ARVIND WANI
Chattisgarh PSC

VIJENDRA
PAL SINGH
U.P. PSC

MANISH DIWEDI
UPPSC &
MPPSC

RAJNISH
BPSC

RAVI MOHAN PATEL
38th Rank, MPPSC

हमारे छात्रों द्वारा समाजशास्त्र

(हिन्दी माध्यम, UPSC) में अंक प्राप्त किया गया...

संदीप त्रिपाठी - 362 (169-193), अशोक कुमार - 346 (171-175)
सुबोध कुमार सिंह - 298 (192-106), विवेक कुमार दुबे - 177 (द्वितीय पत्र)
धीरज अग्रवाल - 352, ऋषा - 325, विवेक कुमार दुबे - 72% (U.P.PSC)

Mains Special Programme, 2008

- 5 महीने (30 अक्टूबर से 31 मार्च) का कक्षा कार्यक्रम (Daily)
- संशोधित Printed Notes & Class Notes
- 50 (120 Questions) Test.
- UPSC में पूछे गये 15 वर्षों के प्रश्नों की समीक्षा
- State PCS हेतु विशेष कक्षा-कार्यक्रम

Mains Special Programme, 2008

- 4 महीने (30 अक्टूबर से 31 मार्च) का कक्षा कार्यक्रम (Daily)
- 1½ महीने का प्रश्नोत्तर परिचर्चा कार्यक्रम जिसमें संभावित 250 प्रश्नों के उत्तरों के रूपरेखा पर चर्चा एवं उनका विश्लेषण
- संशोधित Printed Notes & Class Notes
- नवीन घटनाओं एवं नवीन सैद्धान्तिक विकास के साथ सम्बद्ध करते हुए अध्यापन
- U.P.S.C. में पूछे गये 20 वर्षों के प्रश्नों की समीक्षा
- प्रत्येक सप्ताह Class Tests
- State PSC के अतिरिक्त पाठ्यक्रम का अध्यापन

पत्राचार - प्रा०-2000/- मुख्य : 2500/-, प्रा० + मुख्य : 4000/-; भेजें - D.D. Shipra Pandey के नाम देय

301-305, Satija House, Comm. Complex, Behind Batra Cinema, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9, Tel. : 9312511015, 9868902785

YH-10/07/7

वाले कार्यों की सूची दिन के शुरू में या एक दिन पहले बना ली जाए। इससे आपके सामने यह स्पष्ट होगा कि आपको दिनभर में क्या-क्या करना है, काम भूलने जाने की स्थिति भी नहीं आएगी। जो काम होते जाएं उन्हें सूची से काट दें। रात को सोने से पूर्व समीक्षा करें कि आप दिनभर में जितना कुछ करना चाहते थे कर पाए या नहीं और क्या दिन का उपयोग इससे और बेहतर ढंग से किया जा सकता था? हो सकता है कतिपय कारणों से आप सूची के सभी कार्यों को न कर सके हों या कुछ परिस्थितिजन्य विवशताएं आ गई हों। लेकिन आपसे जो चूकें हुई हों उन्हें आगे दुहराएं नहीं। इस प्रकार आपका हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर बन सकता है। हो सकता है कुछ दिनों बाद आपका समय प्रबंधन इतना अच्छा हो जाए कि आपको समीक्षा की ज़रूरत ही न रहे। यदि आप हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं तो अपनी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से कर के देखिए जो कभी जल्दी में नहीं होता फिर भी उसके काम समय पर पूरे होते हैं। दोनों के पास बराबर समय है लेकिन समय के उपयोग करने के तरीके एवं योजना में अंतर है।

यदि हम 24 घंटों में ही ज्यादा कुछ करना चाहते हैं तो हमें अपने लिये अतिरिक्त समय सिरजना होगा। उदाहरण से यह बात स्पष्ट होगी। हमारा अच्छा-खासा वक़्त नींद में गुज़रता है। हममें से कई लोग सोने में आवश्यकता से अधिक समय व्यतीत करते हैं। एक स्वस्थ वयस्क के लिये 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त मानी जाती है लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो 9-10 घंटे सोकर भी अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते। यदि हम रोज़ आधा घंटा देर से सोएं एवं सुबह आधा घंटा पहले उठें तो हमारे पास हर रोज़ एक घंटे का अतिरिक्त समय होगा, वर्षभर में हमें इस प्रकार 365 घंटे मिल सकते हैं। सोचने की बात है कि इस अतिरिक्त समय में कितना कुछ किया जा सकता है। काम की गति बढ़ा कर भी आप अपने लिये अतिरिक्त समय जुटा सकते हैं, चाहे पैदल चलने की गति हो या पढ़ने-लिखने की।

प्रत्येक सफल व्यक्ति समय की क़ीमत एवं महत्व को पहचानता है तथा इसके एक-एक पल का सदुपयोग करता है। यदि आप सही ढंग से योजना बनाएंगे तो आपके पास अपने सभी कार्यों के लिये समय होगा। आप की दिनचर्या भले ही व्यस्त हो कभी-कभी थोड़ा वक़्त रचनात्मक कार्यों एवं रुचियों के लिये भी निकालना चाहिए। दुनिया में ज्ञान, अनुभव एवं विविधताओं की प्रचुरता है और समय देकर ही हम इनका लाभ उठा सकते हैं।

एक प्रकार से कहा जाए तो समय प्रबंधन समय के संदर्भ में अपना प्रबंधन है। हम घड़ी की सुइयों को नहीं रोक सकते, परंतु यह ज़रूर सुनिश्चित कर सकते हैं कि समय बीत जाने पर हमें पछतावा न हो। यदि हमने समय को गंवाया नहीं है और इसका सदुपयोग किया है तो पछतावे की नौबत नहीं आएगी। वर्तमान का सही उपयोग भविष्य के लिये भी लाभकर होगा।

समय प्रबंधन के गुर सीखकर हम अपनी गतिविधियों का दायरा बढ़ा सकते हैं एवं अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं।❑

(लेखक भोपाल स्थित बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज के संकाय सदस्य हैं)

कर्ज़ से दबे किसानों के लिये राहत कार्यक्रम

देश के लगभग 48.6 प्रतिशत किसान परिवार ऋण के बोझ तले दबे हैं। आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में तो यह प्रतिशत 82 तक पहुंच गया है। कृषि ऋणग्रस्तता को सुलझाने और किसानों को राहत प्रदान करने के लिये सरकार ने इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान के निदेशक की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था। इस दल ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सरकार इसकी सिफ़ारिशों पर कार्रवाई कर रही है।

कृषि मंत्री शरद पवार ने संसद के बीते मानसून सत्र में सदन को बताया कि राज्यों में कृषि ऋण से पीड़ित क्षेत्रों की पहचान का कोई प्रस्ताव तो नहीं है, लेकिन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल जैसे चार राज्यों में ऐसे 31 जिलों की पहचान की गई है जहां आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक है। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में तीन वर्षों में अमल में लाया जाने वाला पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को राहत देने के लिये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 50 लाख रुपये अग्रिम सहायता भी दी गई है।

हाल ही में सरकार ने कृषि के लिये दो नयी योजनाओं को हरी स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से पहली है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिसके तहत धान, गेहूं व दालों की, उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। दूसरी है अतिरिक्त केंद्रीय सहायता योजना। इसके तहत राज्यों को कृषि में अधिक निवेश करने और उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाएगा।

कर्ज़ के बोझ तले दबे किसान

आंध्र प्रदेश: 82 प्रतिशत, तमिलनाडु: 74.5 प्रतिशत, पंजाब: 65.4 प्रतिशत, केरल: 64.4 प्रतिशत, कर्नाटक: 61.6 प्रतिशत, महाराष्ट्र: 54.8 प्रतिशत, हरियाणा: 53.1 प्रतिशत, राजस्थान: 52.4 प्रतिशत, गुजरात: 51.9 प्रतिशत

SAROJ KUMAR'S IAS ERA

IAS/PCS - 2007-08

GEOGRAPHY, GENERAL STUDIES & History - (P.T.&Mains) WITH

SAROJ KUMAR

Free workshop with SAROJ KUMAR *(Hindi & Eng. Medium)*

29 OCT. 2007	Geog. (P.T.)	10.30 AM
30 OCT. 2007	Geog. (Mains)	10.30 AM
31 OCT. 2007	G.S. (P.T.)	10.30 AM
1 NOV. 2007	G.S. (Mains)	10.30 AM
2 NOV. 2007	History	10.30 AM
3 NOV. 2007	Essay	10.30 AM

TEST SERIES	DURATION
Geog. (Mains)	1 Month
Geog. (P.T.)	1 Month
G.S. (Mains)	1 Month
G.S. (P.T.)	1 Month
History (Mains)	1 Month
History (P.T.)	1 Month

FOUNDATION COURSE	DURATION
Geog. (P.T. & Mains)	4-5 months
G.S. (P.T. & Mains)	4-5 months
History (P.T. & Mains)	4-5 months
Essay	1 month

POSTAL COURSE (HINDI & ENGLISH MEDIUM)

Geog. (P.T. & mains) ❖ G.S. (P.T. & Mains) ❖ Sociology (Mains) in हिन्दी only

P.C.S. Special Course — **Duration**

U.P., M.P., Jharkhand, Rajasthan, Bihar, Haryana, Uttranchal, West Bengal, H.P. Chhatisgarh etc. — 1 Month

HIGHEST MARKS

G.S. Marks		Geog. Marks	Interview Marks	Essay Marks	History Marks
K.K. Nirala 360	M.K. Sharma 358	R. Kumari (Eng. Med.) 426	A. Kumar 240	A. Kumar 153	S. Yadav 365
P. Singh 338	D. Rawat 323	H.Meena (Hindi Med.) 362	S. Aggarwal 226		

Batch Starts :-5th, 10th, 20th Sept., 5th, 20th Oct. & 5th Nov.

Special Classes	Duration
Geog. (P.T.)	2 Months
G.S. (P.T.)	2 Months
History (P.T.)	2 Months

Contact

DR. VEENA SHARMA

SAROJ KUMAR'S IAS ERA

1/9, Roop Nagar, G.T. Karnal Road, Near Shakti Nagar Red Light, Above P.N.B.
Shakti Nagar Branch, Delhi-110007 Ph.: 011-64154427 Mob. : 9910360051, 9910415305

YH-10/07/10

शिशु के लिये अनुपम आहार है मां का दूध

❍ अनिल कुमार

मातृत्व से बढ़कर स्त्री के जीवन में कोई दूसरा सुख नहीं होता। शिशु को गोद में लेकर अथवा सीने से लगाकर कोई भी मां कुछ क्षणों के लिये अपनी सारी पीड़ा भूल जाती है। मां का दूध अमृत तुल्य होता है। शिशु के लिये प्रकृति प्रदत्त यह ऐसा अनुपम आहार है जिसकी तुलना कोई अन्य आहार नहीं कर सकता।

बच्चे के स्वाभाविक विकास के लिये तथा मां के दूध में पाचन के रूप में प्रोटीन, वसा, कुछ एन्जाइम्स और विटामिन जैसे पोषक तत्व भी विद्यमान होते हैं जिनकी वजह से बढ़ते हुए बच्चों को अनेक तरह की बीमारियों से लड़ने की भी विशेष क्षमता हासिल होती है, अर्थात बच्चे के शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता का विकास होता है।

छोटा बच्चा जब मां का दूध पीता है तो मां और बच्चे के बीच प्यार और निकटता भी बढ़ती है। जिन बच्चों को किसी भी कारणवश मां का दूध नहीं मिल पाता उस बच्चे के शारीरिक विकास के साथ-साथ मानसिक विकास पर भी बुरा असर पडता है।

मां का दूध पीने से बच्चा हृष्ट-पुष्ट तथा मज़बूत तो बनता ही है अनेक तरह के संक्रमण से भी बचा रहा है। स्तनपान सरल एवं सस्ता तो है ही यह मां और बच्चे दोनों को भावानात्मक संतुष्टि भी प्रदान करता है। मां का दूध पीने वाले बच्चों में कुपोषण, सूखा रोग, निर्जलीकरण बहुत कम होता है और एलर्जी, एग्जिमा आदि जो कि गाय के दूध से हो जाता है कि संभावनाएं भी बहुत कम रहती है।

मां के दूध में एंटीबाडीज होते हैं जो बच्चे की उस समय तक रक्षा करते रहते हैं जब तक बच्चे का शरीर स्वयं एंटीबाडीज पैदा करना नहीं सीख जाता। जिन बच्चों को मां के दूध के स्थान पर गाय का दूध पिलाया जाता है उन्हें दमा, अस्थमा, एग्जिमा और दूध पीते ही उल्टी कर देना जैसी एलर्जियां हो सकती है। वैसे भी गाय के दूध में बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व भी मौजूद नहीं होते हैं।

कुछ माताएं और विशेषत: वे जो अपने डील-डौल एवं शारीरिक सौंदर्य पर ही अधिक ध्यान देती हैं उनमें स्तनपान को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंता व्याप्त रहती है और वे अपने अबोध शिशु को स्तनपान कराने के बजाय दूध की बोतल पकड़ाने की कोशिश करती हैं। दरअसल उनके दिलोदिमाग में यह धारणा विद्यमान होती है कि बच्चे को स्तनपान कराने से उनका शरीर बेडौल हो जाएगा, लेकिन वास्तव में यह धारणा पूर्णतया गलत एवं निर्मूल है। स्तनपान कराने के दिनों में स्तन में थोड़ा-सा ढीलापन तो ज़रूर आ सकता है परंतु यह ढीलापन स्तनपान बंद होते ही अपने आप समाप्त हो जाता है और स्तन स्वत: ही अपने पूर्व आकार को ग्रहण कर लेते हैं। शुरू-शुरू में कुछ माताओं के लिये यह समस्या होती है कि नवजात शिशु को दिन में कितनी बार दूध पिलाया जाए विशेषकर, पहले बच्चे के जन्म के बाद। इस संबंध में विशेषज्ञों का कहना है कि शिशु जितनी बार चाहे उसे दूध पिलाते रहना चाहिए।

कुछ बच्चे ज्यादा भूख की वजह से मां का दूध पीते समय हवा भी पी जाते हैं और इस तरह पेट में वायु इकट्ठी होने से बच्चे के पेट में दर्द होने लगता है और दूध पीने के तुरंत बाद कई बच्चे रोने लगते हैं। अत: बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसे सीने से लगाकर उसकी पीठ थपथपानी चाहिए ताकि पेट से वायु बाहर निकल जाए।

यदि माता किसी संक्रामक रोग जैसे- टीबी, कुष्ठ रोग, टायफायड, मलेरिया आदि से पीड़ित हैं तो बच्चे के भी इन रोगों की चपेट में आने का भय बढ़ जाता है। अत: ऐसी अवस्था में पूर्ण उपचार एवं चिकित्सकीय परामर्श के बाद ही बच्चे को स्तनपान कराने का निर्णय लेना चाहिए। यदि स्तन पर फोड़े, फुंसी अथवा घाव हो तो इलाज कराने के उपरांत ही बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। ❑

डॉ. मनमोहन सिंह
माननीय प्रधानमंत्री

भारती
बढ़ती

नई स्कीमें

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

- चावल, गेहूं और दलहन के लिए
- ग्यारहवीं योजना में लगभग 5000 करोड़ रुपये का परिव्यय
- ग्यारहवीं योजना के अंत तक चावल के उत्पादन में 10 मिलियन टन, गेहूं के उत्पादन में 8 मिलियन टन और दलहन के उत्पादन में 2 मिलियन टन की वृद्धि

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए
- ग्यारहवीं योजना (राज्य योजनाओं के तहत) में 25000 करोड़ रुपये का परिव्यय
- क्षेत्र के लिए ज्यादा संसाधनों के आवंटन के लिए राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन देना

अन्य प्रमुख स्कीमें

- राज्यों में बागवानी क्षेत्र के समग्र और समेकित विकास के लिए **राष्ट्रीय बागवानी मिशन**। 2007-08 के लिए परिव्यय-1150 करोड़ रुपये
- ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के जरिए बेहतर जल प्रयोग कुशलता हेतु **लघु सिंचाई स्कीम**। 2007-08 के लिए परिव्यय-550 करोड़ रुपये
- बांस क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए **राष्ट्रीय बांस मिशन**। 2007-08 के लिए परिव्यय-70 करोड़ रुपये।

फसल उत्पादन बढ़ाने संबंधी उपाय

1 कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना

- कृषि और सहकारिता विभाग का योजना परिव्यय 2004-05 में 2670 करोड़ रुपये से बढ़कर 2007-08 में 7462 करोड़ रुपये हो गया जो 180% की वृद्धि दर्शाता है।

2 किसानों के लिए बेहतर ऋण प्रवाह

- कृषि सेक्टर के लिए संस्थागत ऋण प्रवाह में 2004-05 में 1253 करोड़ रुपये से बढ़कर 2006-07 में 2032 करोड़ रुपये तक अर्थात 62.17% वृद्धि दर्ज की।
- अल्प अवधि ग्रामीण सहकारी साख संरचना की बहाली के लिए 13,596 करोड़ रुपये की राशि का एक पैकेज कार्यान्वयनाधीन है।

3 पीड़ित किसानों के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज

- चार राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के 31 आत्महत्या संभावित जिलों में 16978.69 करोड़ रुपये के एक विशेष पुनर्वास पैकेज का कार्यान्वयन।

कृषि और
कृषि मंत्रा
भारत सर

य कृषि
कदम

श्री शरद पवार
माननीय केन्द्रीय कृषि, उपभोक्ता मामले
खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

4 वर्ष 2004-05 के संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

- वर्ष 2006-07 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 110 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई। वर्ष 2006-07 के लिए गेहूं पर अतिरिक्त 100 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस।
- वर्ष 2006-07 में चावल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 20 रुपये तक वृद्धि। वर्ष 2006-07 हेतु चावल पर प्रति क्विंटल अतिरिक्त 40 रुपये बोनस।

5 विपणन सुधार

- कृषि विपणन अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा दिया गया।
- कई राज्य सरकारों द्वारा एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन किया गया।
- महत्वपूर्ण शहरी केन्द्रों में फलों, सब्जियों और अन्य शीघ्र नष्ट होने वाली जिंसों के लिए आधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने हेतु आधुनिक टर्मिनल मंडियों को बढ़ावा दिया गया।

6 विस्तार को सुदृढ़ करना

- 263 जिलों में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों एटीएमए (आत्मा) को स्थापित किया गया। चालू वर्ष में 300 अन्य एटीएमए (आत्मा) स्थापित की जानी हैं।

स्थापित की गई नई संस्थाएं

- शुष्क भूमि और वर्षा सिंचित कृषि के सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण।
- पादप किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 को लागू करने के लिए पादप किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में बागवानी के विकास के लिए केन्द्रीय बागवानी संस्थान, नागालैंड।

कृषि उत्पादन में वृद्धि
(वर्ष 2004-05 से वर्ष 2006-07)

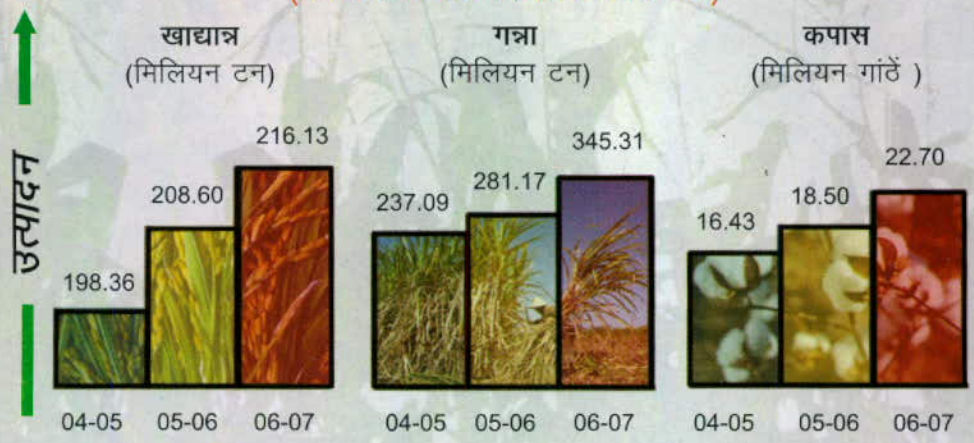

(आंकड़े *2006-07* चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार)

ेता विभाग

davp 01101/13/0030/0708

YH-10/07/14

1857 : प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में दिल्ली

○ देवेंद्र उपाध्याय

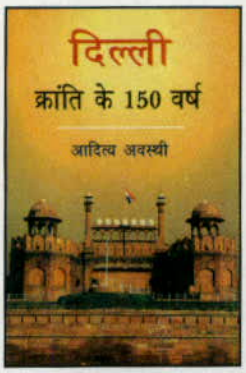

पुस्तक का नाम : दिल्ली : क्रांति के 150 वर्ष; **लेखक :** आदित्य अवस्थी, **प्रकाशक :** कल्याणी शिक्षा परिषद, जटवाड़ा, दरियागंज, नयी दिल्ली-2; **मूल्य :** 300 रु. ; **पृष्ठ :** 256

भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। मेरठ छावनी से 10 मई, 1857 को जिस क्रांति की चिंगारी भड़की थी वह पूरे देश में फैल गई। दिल्ली में बाग़ी सिपाहियों ने दिल्लीवासियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ फौज़ को नाकों चने चबाने पर मज़बूर कर दिल्ली से बाहर खदेड़ दिया। पूरे चार महीने तक उन्हें विपरीत परिस्थितियों में रिज पर रहने के लिये मज़बूर कर बहादुरशाह ज़फर के झंडे तले शाही सेना ने रिज पर ज़मे अंग्रेज़ों पर बार-बार हमले किए, सैकड़ों अंग्रेज़ अफसर और फौज़ी हताहत हुए।

दिल्ली क्रांति के 150 वर्ष में पत्रकार आदित्य अवस्थी ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र दिल्ली के उस घटनाक्रम का वृतांत प्रस्तुत किया है। पुस्तक में 150 वर्ष की दिल्ली की गाथा का विस्तार से बयान किया गया है, जो दिल्ली के 150 वर्ष के इतिहास का सफ़रनामा है।

सितंबर 1858 में दिल्ली फिर अपने कब्ज़े में लेने के बाद अंग्रेज़ों ने इस शहर और शहर के परंपरागत चरित्र को नेस्तनाबूद करने के लिये अनेक तरीक़े अपनाए। सैकड़ों लोगों को फांसी पर लटका दिया और उनकी संपत्ति लूट ली। हज़ारों लोगों को बेघर कर शहर से बाहर कर दिया। शहर की चारदीवारी, दरवाज़े और खिड़कियां तुड़वा दी। चारदीवारी में बने दरवाज़ों और खिड़कियों को तोड़कर उनके बीच से सड़कें निकाल दी।

दिल्ली जीतने के बाद अंग्रेज़ों ने मुगल वंश के शहज़ादों की खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी। बहादुरशाह जफ़र पर उन्होंने देशद्रोह का मुक़दमा चलाया और देशनिकाला देकर रंगून भेज दिया। कोई विदेशी किसी देश के बादशाह पर अपने ही देश के खिलाफ़ विद्रोह का आरोप लगाए ऐसा घृणित हथकंडा कभी सुना न गया था।

पुस्तक में 1857 की दिल्ली का चित्र सामने आता है। तब दिल्ली की आबादी थी सिर्फ़ डेढ़ लाख और चारदीवारी के भीतर फैली दिल्ली, जो शाहजहां द्वारा बसाई गई दिल्ली तक सीमित थी। तब मुसलमानों की संख्या अधिक थी और हिंदुओं की तादाद उनसे कम थी, गिने-चुने ईसाई भी थे पर उनमें सद्भाव था। तब बहादुशाह ज़फर दिल्ली की गद्दी पर थे। वे कहने भर को बादशाह थे, उनके नाम पर अंग्रेज़ अफसर राज कर रहे थे।

10 मई को जब मेरठ में सैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ क्रांति शुरू की तो उन्होंने 'दिल्ली चलो' का नारा दिया। विद्रोही सैनिकों में हिंदुओं की तादाद अधिक थी लेकिन उन्होंने मुगल बादशाह को ही भारत का असली बादशाह माना। मेरठ ही नहीं, हर छावनी ने बग़ावत का झंडा बुलंद कर दिल्ली के बादशाह को ही अपना नेता घोषित किया।

दिल्ली में क्रांति की शुरुआत 11 मई, 1857 की सुबह हुई जब मेरठ से बग़ावत करने वाले घुड़सवार सैनिकों ने दिल्ली में एकमात्र नाव के पुल से प्रवेश किया। उनके दिल्ली पहुंचने की ख़बर फैलती चली गई। इन सैनिकों की टुकड़ियों ने दरियागंज से शहर में प्रवेश करना शुरू कर दिया और फिर लालकिला की तरफ बढ़ते हुए उनका अंग्रेज़ों से मुक़ाबला हुआ। किले की तरफ बढ़ते हुए पहरेदारों ने भी उन्हें नहीं रोका, वे भी उनके साथ मिल गए। राजपुर छावनी के भारतीय सैनिक भी क्रांति में शामिल हो गए।

विद्रोही सैनिकों और अंग्रेज़ों की दूसरी मुठभेड़ दरियागंज के बाद कलकत्ता गेट के पास हुई जो बेला रोड स्थित हनुमान मंदिर के निकट था। पहाड़गंज थाना प्रमुख इंस्पेक्टर मोइनुद्दीन ने इस पूरी घटना का चश्मदीद बयान लिखा। *दिल्ली न्यूज़* के नाम से अख़बार निकालने वाले चुन्नीलाल ने कलकत्ता गेट की घटना का विवरण लिखा जिन्हें बाद में बहादुरशाह ज़फर पर मुक़दमा चलाए जाने के दौरान गवाह के रूप में पेश किया गया। इसके बाद लाहौरी गेट और दीवान-ए-खास होते हुए विद्रोही सैनिक बादशाह से मिलने अंदर घुस गए। वहां अनेक अंग्रेज़ मारे गए। विद्रोही सैनिकों ने बादशाह के समर्थन में नारेबाज़ी शुरू कर दी और उनसे विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिये इस लड़ाई का नेतृत्व करने की अपील की।

पुस्तक में आदित्य अवस्थी ने दिल्ली के 150 वर्ष के इतिहास का बखूबी चित्रण किया है, लेकिन कई बार वे फिर भटक कर पीछे चले गए हैं, जिससे कई स्थानों पर पाठ बोझिल महसूस होता है। पुस्तक की सहज़ता और भाषा की सरलता ने इसे पठनीय बनाए रखा है। दिल्ली के डेढ़ सौ वर्षों के इतिहास, विशेष रूप से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में दिल्ली की भूमिका को जानने - समझने में यह पुस्तक बहुत मदद करती है। ❑

(समीक्षक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

प्रकाशक व मुद्रक वीणा जैन, निदेशक द्वारा प्रकाशन विभाग के लिये अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स (प्रा.) लिमिटेड, डब्ल्यू-30, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नयी दिल्ली-110 020 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कांप्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003 से प्रकाशित। कार्यकारी संपादक : राकेशरेणु

आज़ादी के 60 साल

जय हिन्द

शक्तिशाली लोकतंत्र
सुदृढ़ धर्मनिरपेक्षता
प्रगतिशील अर्थव्यवस्था
सर्वजन विकास

भारत बने बेमिसाल

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

davp 22202/13/0018/0708

YH-10/07/6

Licenced under U (DN)-53/2006-08
रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2006-08 तथा डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस–प्राप्त पंजी सं. 951/57
Reg. No. D.L.(S)-05/3231/2006-08 Licenced to post without pre-payment at RMS, Delhi. R.N. 951/57

अध्यापन कार्य यानि राष्ट्र का निर्माण

यू.जी.सी.-नेट/जे.आर.एफ./स्लेट परीक्षा की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षोपयोगी विशेष सामग्री

Useful Books	Code	Price
UGC-NET Teaching & Research Aptitude (General Paper-I)	420	215.00
UGC-NET Teaching & Research Aptitude (Gen. Paper-I)	1553	235.00
UGC-NET Practice Work Book General Paper-I	1552	60.00
UGC-NET Geography	336	150.00
UGC-NET Obj. Geography (Paper II)	320	140.00
UGC-NET English (Paper-II)	925	135.00
UGC-NET English Litt. (Paper II)	940	80.00
UGC-NET English (Paper III)	1544	90.00
UGC-NET English (Paper II & III)	1549	160.00
UGC-NET Psychology (Paper-II)	322	100.00
UGC-NET History (Paper-III)	996	135.00
UGC-NET Commerce (Paper-II)	968	130.00
UGC-NET Commerce (Paper-II)	888	315.00
UGC-NET Commerce (Paper-III)	359	450.00
UGC-NET Computer Science (Paper-II & III)	894	370.00
UGC-NET Physical Education (Paper-II & III)	931	320.00

उपयोगी पुस्तकें	Code No.	Price
UGC-NET प्रैक्टिस वर्क बुक जनरल पेपर-I	656	65.00
UGC-NET जनरल पेपर-I *(डॉ. लाल, जैन एवं डॉ. वशिष्ठ)*	200	215.00
UGC-NET जनरल पेपर-I *(डॉ. मिथिलेश पाण्डेय)*	271	205.00
UGC-NET संस्कृत (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	509	140.00
UGC-NET संस्कृत (तृतीय प्रश्न-पत्र)	1047	250.00
UGC-NET संस्कृत (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	574	80.00
UGC-NET संस्कृत (तृतीय प्रश्न-पत्र)	1019	290.00
UGC-NET अर्थशास्त्र *(डॉ. अनुपम अग्रवाल)*	521	340.00
UGC-NET हिन्दी (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	567	210.00
UGC-NET हिन्दी (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1114	150.00
UGC-NET हिन्दी (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1257	125.00
UGC-NET हिन्दी (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	763	240.00
UGC-NET भूगोल *(डॉ. एम. एस. सिसोदिया)*	54	215.00
UGC-NET प्रैक्टिस वर्क बुक भूगोल (तृतीय प्रश्न-पत्र)	1292	70.00
UGC-NET भूगोल (तृतीय प्रश्न-पत्र)	206	225.00
UGC-NET राजनीति विज्ञान (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	685	320.00
UGC-NET राजनीति विज्ञान (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1125	99.00
UGC-NET राजनीति विज्ञान (तृतीय प्रश्न-पत्र)	201	240.00
UGC-NET राजनीति विज्ञान (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	681	320.00
UGC-NET राजनीति विज्ञान (तृतीय प्रश्न-पत्र)	777	70.00
UGC-NET इतिहास (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	204	255.00
UGC-NET इतिहास (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	659	130.00
UGC-NET इतिहास (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	714	175.00
UGC-NET वाणिज्य (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	682	255.00
UGC-NET वाणिज्य (तृतीय प्रश्न-पत्र)	1226	565.00
UGC-NET संगीत (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	779	60.00
UGC-NET संगीत (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1323	55.00
UGC-NET संगीत (तृतीय प्रश्न-पत्र)	596	95.00
UGC-NET मनोविज्ञान (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1048	120.00
UGC-NET मनोविज्ञान (तृतीय प्रश्न-पत्र)	1022	98.00
UGC-NET विधि (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1173	105.00
UGC-NET गृह विज्ञान (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1336	170.00
UGC-NET गृह विज्ञान (तृतीय प्रश्न-पत्र)	1337	295.00
UGC-NET समाजशास्त्र (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1335	190.00

उपकार प्रकाशन
2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा – 282 002 फोन : 2530966, 3208693; फैक्स : (0562) 2531940
E-mail : info@upkarprakashan.com Website : www.upkarprakashan.com
ब्राँच आफिस : 4840/24, गोविन्द लेन, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली – 2 फोन : 23251844, 23251866

YH-10/07/1